

अध्याय 3

विकास प्रवृत्तियां

3.1 अब तक नौ पंचवर्षीय योजनाओं में दर्ज की गई संवृद्धि की लक्षित एवं वास्तविक दरों की तुलना दर्शाती हैं कि पांचवी योजना तक वास्तविक संवृद्धि दरें लक्षित संवृद्धि दरों से कम रहीं परन्तु लक्षित संवृद्धि दर के मुकाबले संवृद्धि दर में कमी से यह प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। पांचवी योजना से आठवीं योजना तक प्राप्त संवृद्धि दरें लक्षित दरों की अपेक्षा लगातार अधिक रहीं। यह प्रवृत्ति नौवीं योजना में वास्तविक बनाम लक्षित दर में कमी के कारण समाप्त हो गई है। तथापि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) समरूप से सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बढ़ा है। (आफति 3.1 देखें)

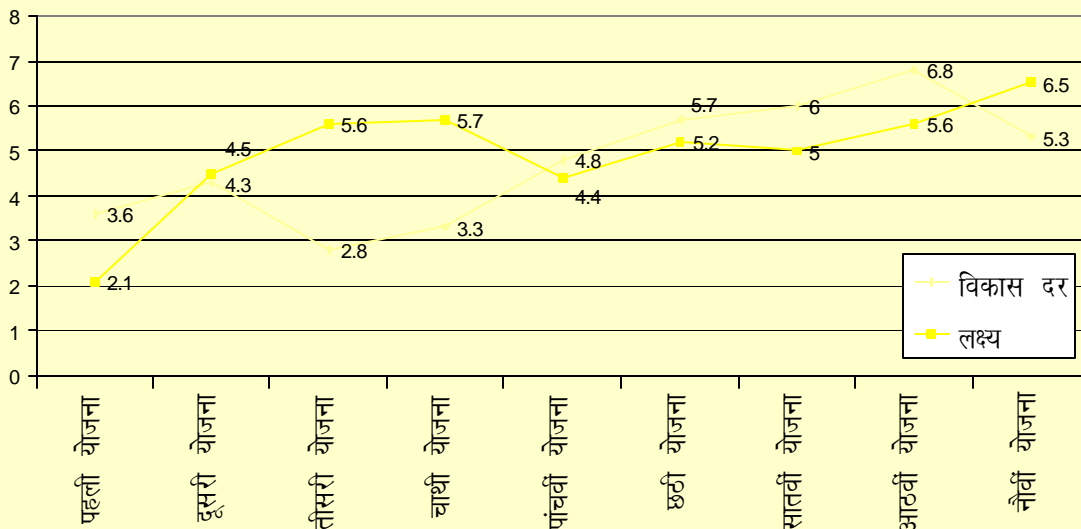
3.2 आर्थिक संवृद्धि की उच्च दर से गरीबी में कमी हुई है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पर्याप्त कमी हुई है। 1970 में 50 प्रतिशत से अधिक से घटकर 1990 में यह 30 प्रतिशत से कम रह गई है। सामाजिक क्षेत्रों में भी सुधार हुए हैं। 1951 में साक्षरता की दर 20

प्रतिशत से कम से बढ़कर 2001 में 65 प्रतिशत तक हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) की हाल ही की मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआरएस) के अनुसार भारत मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक श्रेणी में लगातार आगे बढ़ रहा है।

3.3 नियोजन एवं राज्य-संचालित औद्योगिकीकरण की कार्य नीति अपनाने का उद्देश्य देश में एक अधिक संतुलित बढ़ोत्तरी करने का था। यह आशा की जाती थी कि समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं कम हो जाएंगी। अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्रों में अधिक निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए योजनाएं एवं नीतियां तैयार की गईं। तथापि, आज भी राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक अंतर अभी भी विद्यमान हैं।

3.4 इस अध्याय में उपलब्ध एवं सामान्यतया स्वीकृत विकास मानकों के संदर्भ में देश के विभिन्न राज्यों में “विकास

आकृति 3.1 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर
;सकल घरेलू उत्पाद, ÷ प्रतिवर्ष



स्रोत: रा-ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2000, के.सं.स.

की तुलनात्मक प्रवृत्तियाँ” दिखाने के प्रयास किए गए हैं। आंकड़ों की सुसंगति और तुलनीयता की बाध्यताओं के रहते प्रयास यह किया गया है कि जहां तक संभव हो राज्यों के आयोजना अनुभव की अधिक से अधिक अवधि को कवर किया जाए। इस अध्याय को मुख्यतया आर्थिक संकेतकों, मानव विकास, संरचनात्मक ढांचा एवं पूंजीगत प्रवाह जैसे भागों में बांटा गया है जो विशिष्ट विषयों तथा क्षेत्रों से संबद्ध है।

मुख्य आर्थिक संकेतक

3.5 यह भाग राज्यों में यथासंभव अवधि के दौरान मुख्य आर्थिक प्रवृत्तियों की तुलना करता है। राज्यों की लम्बी अवधि की विकास प्रवृत्तियों को आंकने के लिए आय संवृद्धि, आय तथा रोजगार की ढांचागत संरचना, गरीबी, कृषि उत्पादकता तथा जनसंख्या जैसे मुख्य आर्थिक संकेतकों का प्रयोग किया गया है।

आय संवृद्धि

3.6 राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण मानक राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) की संवृद्धि है। आदर्श रूप से प्रत्येक राज्य की रा.घ.उ. सीरीज को सं.घ.उ. की राष्ट्रीय लेखा अनुमानों के साथ पूर्ण रूप से संगत होना चाहिए। तथापि ऐसा नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा रा.घ.उ. से संबंधित सूचना केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित की जाती है तथा इसका प्रयोग राष्ट्रीय लेखा अनुमानों के निवेशों में से एक निवेश के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रिया में, के.सं.स. विभिन्न राज्यों में रा.घ.उ. का अनुमान लगाने के तरीकों में जो अन्तर है वह नोट करता है। परन्तु यह सीरीज को परिष्कृत नहीं करता जिससे यह परस्पर तथा राष्ट्रीय लेखों से तुलनीय हो सके। तदनुसार, हम आंकड़ों के प्रयोग को केवल संवृद्धि दर की प्रवृत्तियों की तुलना करने तक ही सीमित रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आंकड़ों में निहित त्रुटियों को कम किया जा सके और जहां तक संभव हो प्रत्यक्ष अन्तर्राज्यीय तुलना से बचा जा सके।

3.7 हम केवल मुख्य राज्यों के 1960 से 1990 तक के घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर ही नजर डालेंगे, क्योंकि इस अवधि के दौरान छोटे राज्यों तथा नए राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब को छोड़कर अन्य सभी मुख्य राज्यों

के लिए राज्य आय आंकड़ा 1960-61 से उपलब्ध हैं। असम, हरियाणा तथा पंजाब के लिए 1960-61 तथा 1965-66 से आगे के आंकड़े उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आंकड़ों का सैट 1967-68 से आरम्भ होता है। चार दशकों के लिए दशक की संवृद्धि की वास्तविक दरों पर पहुंचने के लिए क्रमशः 1960-61, 1970-71, 1980-81 तथा 1993-94 आधार वर्ष माने गए हैं।

3.8 यद्यपि पहली आंकड़ा सीरीज़ 1984-85 तक है, हमने 1960-61 से 1979-80 को पहली अवधि माना है। यह इसलिए किया गया है कि 1980-81 से दूसरी आंकड़ा सीरीज़ आरंभ हुई जिसमें तरीके से सुधार शामिल किया गया। 1980-81 की सीरीज़ 1997-98 तक प्रयोग में थी। 1993-84 को आधार वर्ष मानकर एक तीसरी सीरीज़ 1999 में लागू की गई जिसमें आर्थिक गतिविधियों के समावेशन में परिवर्तन किए गए। अतः विभिन्न राज्यों के संवृद्धि संबंधी अनुभवों के अपने विश्लेषण में, हम इन तीन भिन्न-भिन्न आंकड़ा सीरीज़ का प्रयोग करेंगे। आंकड़े का स्रोत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन है।

3.9 साठ के दशक में तत्कालीन संगठित पंजाब तथा साथ के क्षेत्रों (अब हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा) द्वारा उच्चतम संवृद्धि दरें रिकार्ड की गईं। इस दशक में, बिहार में 1 प्रतिशत से भी कम संवृद्धि हुई, जो सबसे धीमी थी जिसका तात्पर्य था प्रति व्यक्ति आय में कमी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश ने 2 प्रतिशत से कम संवृद्धि दर रिकार्ड की। (तालिका 3.1)

3.10 सत्तर के दशक में, संवृद्धि की दर अधिकांशतः अपरिवर्तित रही। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर सहित महाराष्ट्र एवं गुजरात के पश्चिमी राज्यों तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों ने संवृद्धि की उच्च दरें रजिस्टर करना आरम्भ कर दिया। इस अवधि में मध्य प्रदेश तथा केरल में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय संवृद्धि में काफी कमी थी और यह राज्य इस दृष्टि से सबसे नीचे थे।

3.11 आर्थिक संवृद्धि का राष्ट्रीय औसत पिछले दशक के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर अस्सी के दशक में 5.6 प्रतिशत हो गया। प्रत्येक राज्य ने इस दशक के दौरान अपनी संवृद्धि में अधिकतम सुसंगति दर्ज की जैसा कि अंतर्राज्यीय असमानता के मापक में हुई कमी से स्पष्ट है जो 2.20 से घटकर 1.39 हो गई। राज्यों के आपस में संवृद्धि की दरों के लिए उच्चतम तथा न्यूनतम के बीच का अंतर 4.0 प्रतिशत प्वाइंट

तालिका 3.1
वर्तमान मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि की
दरों की प्रवृत्तियां - साठ तथा सत्तर के दशकों में

राज्य	निवल राज्य घरेलू उत्पाद		निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति	
	1960-61 से 1969-70	1970-71 से 1979-80	1960-61 से 1969-70	1970-71 से 1979-80
गोवा	उ.न.	6.1	उ.न.	3.6
महाराष्ट्र	2.9	5.7	.04	3.3
पंजाब	5.6	5.4	3.5	3.2
हरियाणा	5.5	4.8	2.6	2.2
गुजरात	2.7	4.5	0.1	2.0
कर्नाटक	3.4	4.3	1.2	1.8
दिल्ली	5.1	6.2	0.7	1.7
जम्मू व कश्मीर	3.1	4.4	0.5	1.6
तमिलनाडु	2.1	3.4	0.1	1.6
अखिल भारत	3.0	3.6	0.8	1.2
आन्ध्र प्रदेश	1.5	3.2	-0.4	1.1
असम	4.0	3.0	0.9	0.8
पश्चिम बंगाल	2.5	2.9	0.02	0.7
बिहार	0.7	2.8	-1.3	0.6
उत्तर प्रदेश	1.6	2.6	-0.2	0.4
उड़ीसा	9.7	2.3	7.3	0.3
राजस्थान	1.3	3.0	-1.1	0.2
हिमाचल प्रदेश	5.6	2.4	3.4	0.2
केरल	3.8	1.7	1.4	-0.2
मध्य प्रदेश	1.5	1.3	-1.1	-1.0

टिप्पणी : इस अवधि में उड़ीसा के लिए नि.रा.घ.उ. के अनुमान दर के लिए प्रयोग किए गए मानकों में विसंगतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप राज्यों की संवृद्धि दरें तुलनीय नहीं हैं। राज्यों के नाम 1970-71 से 1979 में प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. की संवृद्धि दरों में श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित किया गया है।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

था। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु ने उच्चतम संवृद्धि रिकार्ड की। जम्मू और कश्मीर तथा असम संवृद्धि की तालिका में सबसे नीचे के स्थान पर आ गए।

3.12 नि.रा.घ.उ. आंकड़ा की नई सीरीज़ के.सां.सं. द्वारा अगस्त, 2000 में जारी की गई तथा इसे बाद में नवम्बर, 2001 में अद्यतन किया गया। तालिका 3.2 में नई सीरीज़ पर आधारित नब्बे के दशक के लिए (आधार वर्ष 1993-

तालिका 3.2
वर्तमान मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि की
दरों की प्रवृत्तियां - अस्सी तथा नब्बे के दशकों में

राज्य	निवल राज्य घरेलू उत्पाद		निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति	
	1980-81 से 1990-91	1993-94 से 1998-99	1980-81 से 1990-91	1993-94 स 1998-99
कर्नाटक	5.4	8.2	3.3	6.4
गुजरात	5.1	8.0	3.0	6.2
तमिलनाडु	5.4	6.8	3.9	5.8
महाराष्ट्र	6.0	7.1	3.6	5.4
राजस्थान	5.9	7.7	3.8	5.3
पश्चिम बंगाल	4.8	6.8	2.6	5.0
अखिल भारत	5.6	6.8	3.3	4.8
गोवा	5.5	8.3	3.9	4.5
केरल	3.2	5.5	1.7	4.2
हिमाचल प्रदेश	5.0	6.7	3.1	3.9
हरियाणा	6.2	5.8	3.9	3.6
आन्ध्र प्रदेश	4.3	4.9	2.1	3.5
पंजाब	5.4	5.0	3.5	3.0
उड़ीसा	5.0	4.3	3.1	2.9
बिहार	4.7	4.2	2.5	2.6
मध्य प्रदेश	4.0	4.4	2.1	2.3
उत्तर प्रदेश	4.9	4.5	2.5	2.3
जम्मू व कश्मीर	2.2	4.7	-0.4	1.6
दिल्ली	7.6	6.7	3.2	1.6
असम	3.6	2.7	1.4	1.0

टिप्पणी : राज्यों के नाम 1993-94 से 1998-99 तक नि.रा.घ.उ. में प्रति व्यक्ति की संवृद्धि की दरों में रैंक के अनुसार दिए गए हैं।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

94) 1993-94 से आगे की नि.रा.घ.उ. में संवृद्धि की प्रवृत्तियां दी गई हैं। आर्थिक संवृद्धि की राष्ट्रीय औसत दर नब्बे के दशक में 1 प्रतिशत प्वाइंट से भी अधिक बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई। संवृद्धि के रिकार्ड से पृथक-पृथक राज्यों में हुई संवृद्धि में भिन्नता का पता चलता है (अस्सी के दशक में मानक भिन्नता 1.19 से बढ़कर नब्बे के दशक में 1.60 हो गई)। यह भिन्नता उसी प्रकार हुई जैसे सत्तर के दशक में हुई थी हालांकि उसमें, कुछ उल्लेखनीय अंतर था। राज्यों में आपसी संवृद्धि की दरों के लिए उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर 5.5 प्रतिशत बिन्दुओं पर था जो पिछले दशक के मुकाबले अधिक फैलाव का संकेतक है। अस्सी और नब्बे के दशकों में संवृद्धि अनुभव में एक मुख्य अंतर था पिछले दशकों की तुलना में पंजाब और हरियाणा की संवृद्धि दर धीमी रही जबकि कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में संवृद्धि दर काफी ऊंची रही। कर्नाटक की स.घ.उ. संवृद्धि सबसे अधिक 8.2 प्रतिशत थी। मुख्य राज्यों में असम में सबसे कम संवृद्धि रही।

3.13 अस्सी तथा नब्बे के दशकों की तुलना में, नब्बे के दशक के दौरान नि.रा.घ.उ. की अंतरराज्यीय समग्र असमानता तथा राज्यों की प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई। (तालिका 3.3 देखें)। हाल के दशकों में, अन्य अवधियों की तुलना में अस्सी के दशक की अवधि में असमानता राज्यों में न्यूनतम थी। नब्बे के दशक में असमानता अधिकतम थी।

3.14 नब्बे के दशक में सभी राज्यों के लिए आर्थिक संवृद्धि की दरों में प्रवृत्तियों की तुलना अनुबन्ध 3.1 में दी गई है।

यह देखा जा सकता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों, उड़ीसा तथा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र सहित कम विकसित क्षेत्रों ने 1993-94 से 1998-99 की हाल ही की अवधि के दौरान अखिल भारत औसत की सामान्यतया संवृद्धि दरों से कम संवृद्धि रिकार्ड की है। यह प्रवृत्ति अधिक तथा कम विकसित राज्यों के बीच की दूरी को और बढ़ाने का संकेत देती है। नब्बे के दशक के संवृद्धि अनुभव की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहला यह कि कुछ राज्यों में त्वरित संवृद्धि अनुभव दूसरे राज्यों की हानी करके है तथा यह केन्द्रीकृत नियोजन की भूमिका कम होने का परिणाम है। यह भी कहा जा सकता है कि संशोधित आर्थिक वातावरण ने कुछ विशेष राज्यों को उनकी वास्तविक आर्थिक क्षमता से अधिक संवृद्धि करने का मौका दिया है। यह अन्य राज्यों की हानी करके नहीं था। नब्बे के दशक में राष्ट्रीय औसत संवृद्धि 1 प्रतिशत बिन्दु बढ़ी तथा अधिकतर राज्यों ने इस दशक में सुधरित संवृद्धि का अनुभव किया।

आय एवं रोजगार में ढांचागत परिवर्तन

3.15 जैसा कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के ढांचे में अपेक्षित होता है राज्यों की अर्थव्यवस्था में मुख्य ढांचागत परिवर्तन हो रहे हैं। (देखें तालिका 3.4)। प्राथमिक क्षेत्र से माध्यमिक तथा तृतीयक क्षेत्रों की ओर झुकाव रहा है। सभी 23 राज्यों के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों जो कि मुख्य ढांचागत परिवर्तन दर्शाते हैं जो देश की परंपरागत और मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से हट कर हैं।

तालिका 3.3

राज्यों/सं.रा.क्षे. के बीच संवृद्धि में असमानता

अवधि	संवृद्धि में असमानता का माप (मानक विचलन)@		प्रति व्यक्ति आय तथा नि.रा.घ.उ. (सहभिन्नता) के बीच संवृद्धि में असमानता का तुलनात्मक माप	
	नि.रा.घ.उ.	प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ.		
1970-71 से 1979-80	2.22	1.81		3.67
1980-81 से 1990-91	1.71	1.02		0.71
1993-94 से 1998-99	3.13	2.40		5.23

टिप्पणी : @ अधिक मूल्य होने पर अधिक असमानता

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

3.16 वर्तमान मूल्यों पर उपलब्ध 23 राज्यों के निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में तुलनीय आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि पिछली तीन योजना अवधियों में, प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत अंश उपांतिक रूप से 1987-88 तथा 1993-94 में बढ़ा है तथा 1999-2000 में 30.83 प्रतिशत तक नीचे

गया है। माध्यमिक क्षेत्र की प्रवृत्ति बिल्कुल उलट है, जैसा कि होना चाहिए तथा 1999-2000 में यह 14.02 प्रतिशत पर रहा। तथापि तृतीयक क्षेत्र का अंश 1987-88 से 49.14 से धीरे-धीरे बढ़कर 1999-2001 में सबसे अधिक 55.14 पर पहुंचा है।

तालिका 3.4
नि.रा.घ.उ. में प्रतिशत हिस्सेदारी में प्रतिशत परिवर्तन (1987-88 से 1999-2000)

क्र.सं.	राज्य	प्रतिशत हिस्सेदारी में परिवर्तन		
		प्राथमिक	माध्यमिक	तृतीयक
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	-11.97	5.02	7.93
2	अरुणाचल प्रदेश	-29.07	-52.96	41.87
3	असम	-11.25	9.40	12.03
4	बिहार	-23.55	-10.43	34.64
5	गुजरात	-21.69	12.52	4.65
6	हरियाणा	-15.18	10.85	9.45
7	हिमाचल प्रदेश	-24.96	48.23	11.81
8	जम्मू व कश्मीर	-11.38	-17.23	10.42
9	कर्नाटक	-25.42	10.51	18.50
10	केरल	-28.01	-23.21	24.25
11	मध्य प्रदेश	-16.40	21.05	13.36
12	महाराष्ट्र	-32.48	-4.72	18.52
13	मणिपुर	-28.13	56.89	20.98
14	मेघालय	-15.24	-33.22	10.19
15	उड़ीसा	-4.91	-66.27	22.62
16	पंजाब	-5.00	-5.03	7.33
17	राजस्थान	-18.15	0.85	15.66
18	तमिलनाडु	-26.15	-13.74	18.73
19	त्रिपुरा	-23.94	175.97	10.31
20	उत्तर प्रदेश	-10.78	27.11	2.96
21	पश्चिम बंगाल	16.72	-38.15	3.74
22	दिल्ली	-54.37	-43.14	12.07
23	पांडिचेरी	-56.55	164.88	-27.51

टिप्पणी : बिहार में झारखंड शामिल है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल है और उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल शामिल है।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

3.17 विकास के सामान्य पैटर्न के विरुद्ध, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मामले में आय में माध्यमिक क्षेत्र के अंश में पर्याप्त कमी आई है।

3.18 समग्र रूप से, आय में रोजगार प्रवृत्तियां ढांचागत प्रवृत्तियों के साथ मेल खाते हैं। (तालिका 3.5 देखें)।

पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली इसका अपवाद हैं जिन्होंने क्षेत्रीय आय में संवृद्धि में तेज बढ़ोत्तरी की बजाए कृषि क्षेत्र में रोजगार की संवृद्धि में कमी दिखाई है तथा दिल्ली के मामले में इस क्षेत्र से आय की संवृद्धि में तेज कमी की बजाए कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संवृद्धि में बढ़ोत्तरी का अपवाद हैं।

तालिका 3.5
रोजगार में प्रतिशत अंश में प्रतिशत परिवर्तन
(1987-88 से 1999-2000)

क्र.सं.	राज्य	प्रतिशत हिस्सेदारी में परिवर्तन		
		प्राथमिक	माध्यमिक	तृतीयक
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	-10.16	-9.80	35.25
2	अरुणाचल प्रदेश	19.01	146.93	-28.61
3	असम	-16.44	26.90	38.23
4	बिहार	-2.84	9.33	8.68
5	गुजरात	-6.12	8.52	7.44
6	हरियाणा	-23.35	-1.96	49.31
7	हिमाचल प्रदेश	-20.03	4.29	76.71
8	जम्मू व कश्मीर	-2.82	-54.71	24.74
9	कर्नाटक	-12.57	-4.03	41.89
10	केरल	-27.62	-1.70	37.30
11	मध्य प्रदेश	-10.88	-0.52	54.64
12	महाराष्ट्र	-20.94	11.76	46.69
13	मणिपुर	5.12	-1.24	-9.08
14	मेघालय	-9.39	-22.57	37.11
15	उड़ीसा	-1.20	0.02	3.98
16	पंजाब	-16.54	-8.29	29.39
17	राजस्थान	-6.08	4.31	13.75
18	तमिलनाडु	-18.10	0.99	31.38
19	त्रिपुरा	-4.74	-37.65	7.89
20	उत्तर प्रदेश	-14.27	29.02	35.65
21	पश्चिम बंगाल	-9.48	-0.82	17.01
22	दिल्ली	25.34	-6.34	0.75
23	पांडिचेरी	-42.79	29.99	30.36

टिप्पणी : 1. बिहार में झारखंड, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल सम्मिलित हैं।

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

गरीबी

3.20 राज्यों का संवृद्धि निष्पादन की गरीबी कम करने में निर्णायक भूमिका होती है जो कि हमारी नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रत्यक्षतः तेजी से विकास कर रहे राज्यों में गरीबी में बहुत तेजी से कमी होने की आशा की जाती है।

3.21 वर्ष 1973-74 और 1977-78 के लिए प्रत्येक राज्य में गरीबी के उपलब्ध अनुमान वहीं हैं जो प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.से.स.) द्वारा तैयार किए गए हैं। वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण वर्ष 1983, 1987-88, 1993-94 तथा 1999-2000 में कराए गए थे और राज्य विशिष्ट गरीबी के अनुमान योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं। यह अनुमान तालिका 3.6 में दिए गए हैं।

तालिका 3.6
गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत
(1999-2000 के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य	1973-74	1977-78	1983	1987-88	1993-94	1999-2000
1	जम्मू व कश्मीर	40.83	38.97	24.24	23.82	25.17	3.48
2	गोवा	44.26	37.23	18.90	24.52	14.92	4.40
3	चंडीगढ़	27.96	27.32	23.79	14.67	11.35	5.75
4	पंजाब	28.15	19.27	16.18	13.20	11.77	6.16
5	हिमाचल प्रदेश	26.39	32.45	16.40	15.45	28.44	7.63
6	दिल्ली	49.61	33.23	26.22	12.41	14.69	8.23
7	हरियाणा	35.36	29.55	21.37	16.64	25.05	8.74
8	केरल	59.79	52.22	40.42	31.79	25.43	12.72
9	गुजरात	48.15	41.23	32.79	31.54	24.21	14.07
10	राजस्थान	46.14	37.42	34.46	35.15	27.41	15.28
11	लक्षद्वीप	59.68	52.79	42.36	34.95	25.04	15.60
12	आन्ध्र प्रदेश	48.86	39.31	28.91	25.86	22.19	15.77
13	दादरा व नागर हवेली	46.55	37.20	15.67	67.11	50.84	17.14
14	मिज़ोरम	50.32	54.38	36.00	27.52	25.66	19.47
15	कर्नाटक	54.47	48.78	38.24	37.53	33.16	20.04
16	अण्डमान व निकोबार द्वीप	55.56	55.42	52.13	43.89	34.47	20.99
17	तमिलनाडु	54.94	54.79	51.66	43.39	35.03	21.12
18	पांडिचेरी	53.82	53.25	50.06	41.46	37.40	21.67
19	महाराष्ट्र	53.24	55.88	43.33	40.41	36.86	25.02
20	अखिल भारत	54.88	51.32	44.48	38.86	35.97	26.1
21	पश्चिम बंगाल	63.43	60.52	54.85	44.72	35.66	27.02
22	मणिपुर	49.96	53.72	37.02	31.35	33.78	28.54
23	उत्तर प्रदेश	57.07	49.05	47.07	41.46	40.85	31.15
24	नागालैंड	50.81	56.04	39.25	34.43	37.92	32.67
25	अरुणाचल प्रदेश	51.93	58.32	40.88	36.22	39.35	33.47
26	मेघालय	50.20	55.19	38.81	33.92	37.92	33.87
27	त्रिपुरा	51.00	56.88	40.03	35.23	39.01	34.44
28	असम	51.21	57.15	40.47	36.21	40.86	36.09
29	सिक्किम	50.86	55.89	39.71	36.06	41.43	36.55
30	मध्य प्रदेश	61.78	61.78	49.78	43.07	42.52	37.43
31	बिहार	61.91	61.55	62.22	52.13	54.96	42.60
32	उड़ीसा	66.18	70.07	65.29	55.58	48.56	47.15

स्रोत : योजना आयोग

टिप्पणी : हिमाचल प्रदेश की गरीबी रेखा तथा जम्मू व कश्मीर के व्यय वितरण का जम्मू व कश्मीर की गरीबी अनुपात अनुमान का प्रयोग किया गया है।

3.22 पूरे भारत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 1973-74 में 54.88 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत तक आ गयी है। उन्नीस राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का राष्ट्रीय औसत की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कम है तथापि विभिन्न राज्यों के गरीबी अनुपातों में बड़े अंतर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उड़ीसा में गरीबी अनुपात 47.15 प्रतिशत जो पंजाब (6.16 प्रतिशत) की तुलना में आठ गुणा है। उड़ीसा और बिहार की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरी तरफ 14 राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 20 प्रतिशत से कम है।

3.23 इस अवधि में पश्चिम बंगाल और केरल में गरीबी स्तरों में काफी सुधार आया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब ने भी गरीबी कम करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इन राज्यों में गरीबी अनुपात गिरकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गया है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले छः वर्षों में बिन्दु-वार गरीबी अनुपातों में कमी की यौगिक दर लगभग 13 प्रतिशत थी तथा सारे देश के लिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कमी एक सी थी। (तालिका 3.7 देखें)

3.24 राज्यों में गरीबी के विभिन्न स्तरों ने घटोत्तरी की तथापि भिन्न-भिन्न दरें दिखाई हैं। चार्ट 3.2 1973-74 तथा 1999-2000 के बीच ऊपर के पांच तथा सबसे नीचे के राज्यों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में परिवर्तन दिखाता है।

3.25 केरल का मामला ध्यान देने योग्य है, जिसने बहुत गरीबी अनुपात वाले राज्यों में आरम्भिक स्थिति से गरीबी रेखा के नीचे के बहुत कम प्रतिशत वाले राज्यों में अविश्वसनीय कमी की है।

3.26 तालिका 3.7 शहरी तथा ग्रामीण गरीबी स्तरों के अन्तर को दर्शाती है। 1973-74 में गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 56.44 थी। इस अवधि के लिए शहरी जनसंख्या में गरीबी का प्रतिशत 49 प्रतिशत थी। पश्चिम बंगाल में 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण गरीब थे, जबकि उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में भी 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसंख्या थी। 1973-74 में, केरल पांच सबसे गरीब राज्यों में था जिसमें लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण गरीब थे और 62 प्रतिशत शहरी गरीब थे। इस अवधि में ग्रामीण गरीबी का निचला स्तर हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में था जिनमें ग्रामीण गरीबी क्रमशः 34.28 तथा 27 प्रतिशत थी। दस राज्यों तथा सं.रा.क्षे. में गरीबी राष्ट्रीय औसत से कम थी तथा 21 में राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल तथा राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में शहरी गरीबी अनुपातों की तुलना में ग्रामीण गरीबी अनुपात अधिक थे। 1993-94 तथा 1999-2000 के बीच एक उत्साहवर्द्धक प्रवृत्ति सामने आई कि अधिकांश राज्यों में ग्रामीण गरीबी में शहरी गरीबी की तुलना में तेजी से कमी हुई।

3.27 अद्यतन अनुमानों के अनुसार, वर्तमान में उड़ीसा में सबसे अधिक तथा इसके बाद बिहार में ग्रामीण गरीबी है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण तथा शहरी गरीबी दोनों में गिरावट आई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी शहरी गरीबी अनुपातों में सुधार आया है जो 36.92 प्रतिशत से घटकर 7.47 प्रतिशत हुआ है तथापि ग्रामीण अनुपात 40.04 प्रतिशत पर लगातार ऊंचे हैं। 1999-2000 में ग्रामीण गरीबी अनुपातों के अपेक्षाकृत निचला स्तर हरियाणा (8.27 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (7.94 प्रतिशत), पंजाब (6.25 प्रतिशत), तथा गोवा (1.35 प्रतिशत) रहा है। चंडीगढ़ तथा दिल्ली में भी गरीबी अनुपात कम रहा है।

तालिका 3.7
1973-74 तथा 1999-2000 में गरीबी का अनुपात

क्र.सं.	राज्य	1973-74			1999-2000		
		ग्रामीण	शहरी	सम्मिलित	ग्रामीण	शहरी	सम्मिलित
1	जम्मू व कश्मीर	45.51	21.32	40.83	3.97	1.98	3.48
2	गोवा	46.85	37.69	44.26	1.35	7.52	4.4
3	चंडीगढ़	27.96	27.96	27.96	5.75	5.75	5.75
4	पंजाब	28.21	27.69	28.15	6.35	5.75	6.16
5	हिमाचल प्रदेश	27.42	13.17	26.39	7.94	4.63	7.63
6	दिल्ली	24.44	52.23	49.61	0.40	9.42	8.23
7	हरियाणा	34.23	40.18	35.36	8.27	9.99	8.74
8	केरल	59.19	62.74	59.79	9.38	20.27	12.72
9	गुजरात	46.35	52.57	48.15	13.17	15.59	14.07
10	राजस्थान	44.76	52.13	46.14	13.74	19.85	15.28
11	लक्षद्वीप	59.19	62.74	59.68	9.38	20.27	15.6
12	आन्ध्र प्रदेश	48.41	50.61	48.86	11.05	26.63	15.77
13	दादरा व नागर हवेली	46.85	37.69	46.55	17.57	13.52	17.14
14	मिज़ोरम	52.67	36.92	50.32	40.04	7.47	19.47
15	कर्नाटक	55.14	52.53	54.47	17.38	25.25	20.04
16	अण्डमान व निकोबार द्वीप	57.43	49.40	55.56	20.55	22.11	20.99
17	तमिलनाडु	57.43	49.40	54.94	20.55	22.11	21.12
18	पांडिचेरी	57.43	49.40	53.82	20.55	22.11	21.67
19	महाराष्ट्र	57.71	43.87	53.24	23.72	26.81	25.02
20	अखिल भारत	56.44	49.01	54.88	27.09	23.62	26.10
21	पश्चिम बंगाल	73.16	34.67	63.43	31.85	14.86	27.02
22	मणिपुर	52.67	36.92	49.96	40.04	7.47	28.54
23	उत्तर प्रदेश	56.53	60.09	57.07	31.22	30.89	31.15
24	नागालैंड	52.67	36.92	50.81	40.04	7.47	32.67
25	अरुणाचल प्रदेश	52.67	36.92	51.93	40.04	7.47	33.47
26	मेघालय	52.67	36.92	50.20	40.04	7.47	33.87
27	त्रिपुरा	52.67	36.92	51.00	40.04	7.47	34.44
28	असम	52.67	36.92	51.21	40.04	7.47	36.09
29	सिक्किम	52.67	36.92	50.86	40.04	7.47	36.55
30	मध्य प्रदेश	62.66	57.65	61.78	37.06	38.44	37.43
31	बिहार	62.99	52.96	61.91	44.30	32.91	42.6
32	उड़ीसा	67.28	55.62	66.18	48.01	42.83	47.15

1993-94 के लिए टिप्पणी:

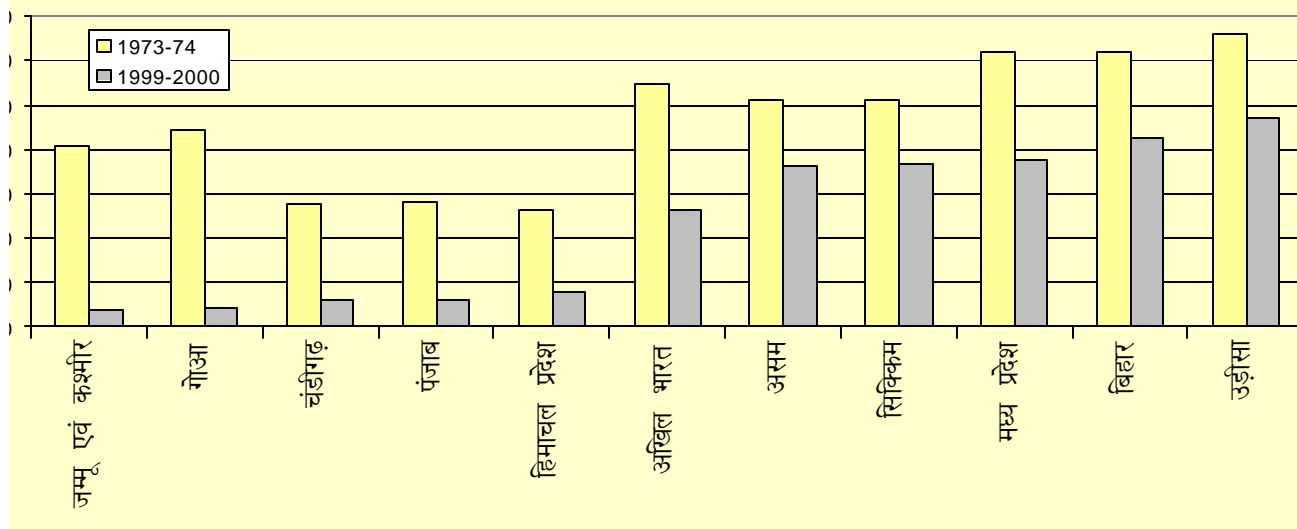
1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए किया गया है।
2. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पांडिचेरी तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया है।
3. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

4. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दादर एवं नागर हवेली के लिए किया गया है।
5. पंजाब शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चण्डीगढ़ की ग्रामीण तथा शहरी गरीबी दोनों के लिए किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।

1999-2000 के लिए टिप्पणी :

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।
3. हिमाचल की गरीबी रेखा तथा जम्मू व कश्मीर के व्यय वितरण का प्रयोग जम्मू व कश्मीर के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।
4. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पांडिचेरी तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए किया गया है।
5. पंजाब शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चण्डीगढ़ की ग्रामीण तथा शहरी गरीबी दोनों के लिए किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादर एवं नागर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादर एवं नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।
7. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन एवं दीव के लिए किया गया है।
8. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।
9. राजस्थान के शहरी गरीबी अनुपात को अनंतिम माना जाए।

आकृति 3.2 1973-74 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों में गरीबी की जनसंख्या का प्रतिशत ;निचले पांच व शीर्ष पांच राज्यद्व



स्रोत : योजना आयोग

3.28 चयनित राज्यों के लम्बी अवधि की प्रवृत्तियों में (जैसा कि उल्लेख किया गया है) कुछ राज्यों के मामले में संवृद्धि तथा गरीबी में ही कमी के बीच सकारात्मक सम्पर्क प्रतीत होता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात तथा आन्ध्र

प्रदेश जैसे तेजी से बढ़ते राज्यों द्वारा समीक्षाधीन अवधि में ग्रामीण गरीबी में महत्वपूर्ण गिरावट आई। (33 और 40 प्रतिशत बिन्दुओं के बीच)। मध्य प्रदेश के मामले में लम्बी अवधि में संतुलित संवृद्धि के साथ-साथ गरीबी में भी संतुलित गिरावट हुई है। बिहार तथा उड़ीसा दोनों ने अपेक्षाकृत कम आर्थिक संवृद्धि हुई है तथा प्रत्यक्षतः इसका गरीबी कम करने में कम असर पड़ा है।

3.29 पश्चिम बंगाल तथा केरल के मामले में संवृद्धि तथा गरीबी में कमी का संयोजन ठीक नहीं बैठा। दोनों राज्यों में पिछले तीन दशकों में ग्रामीण गरीबी अनुपात में पर्याप्त गिरावट आई है। तथापि जैसा कि हमने संवृद्धि निष्पादन के विश्लेषण में देखा है तथापि अस्सी के दशक तब केरल अपेक्षाकृत संतुलित संवृद्धि में कमजोरी के साथ प्रति व्यक्ति आय संवृद्धि नकारात्मक से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम के मध्य में थी। अतः तीन दशकों से कम समय में ग्रामीण गरीबी अनुपात में लगभग 50 प्रतिशत बिन्दुओं की गिरावट उन राज्यों के लिए अपेक्षाकृत बहुत अधिक है जो एक सुदृढ़ संवृद्धि निष्पादन रिकार्ड कर रहे थे। मानव विकास के मामले में केरल को एक सफल राज्य माना जाता है। केरल में वे अग्रताएं, जिन्होंने लोक नीति का निर्धारण किया है उनसे सामाजिक अवसरों में विस्तार हुआ तथा शेष देश के मुकाबले उच्च स्तर का मानव विकास हुआ है। इन नीतियों को लम्बी अवधि तक के लिए लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मानव विकास में उपलब्धियों ने ग्रामीण गरीबी की पर्याप्त गिरावट में एक प्रेरक वातावरण तैयार किया तथा इससे संवृद्धि दरों में बढ़ोत्तरी भी हुई।

3.30 पश्चिम बंगाल के मामले में भी पहले दो दशकों में आर्थिक संवृद्धि बहुत धीमी थी, केवल नब्बे के दशक में ही यह बढ़ी जिससे प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि यह ग्रामीण गरीबी अनुपात में 41 प्रतिशत बिन्दुओं की महत्वपूर्ण गिरावट का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश गिरावट नब्बे के दशक से पहले की अवधि में हुई प्रतीत होती है। पश्चिम बंगाल की स्थिति के अन्य राज्यों से भिन्न होने का कारण लोक नीति की अलग दिशा हो सकता है जो उस राज्य ने सत्तर के दशक से अपनाई है। परिसंपत्ति के पुनः वितरण (भूमि सुधार) के कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण गरीबों तक कृषि भूमि जैसी परिसंपत्ति की उपलब्धता बढ़ाने की नीति से आय आ जाने

के अवसरों के अधिक समान रूप से फैलाव में सहायता मिली है जो उस अर्थव्यवस्था की दर पर बिना कोई उल्लेखनीय प्रभाव डाले इस अवधि के दौरान ग्रामीण गरीबी में पर्याप्त कमी का कारण भी हो सकती है।

कृषि संवृद्धि

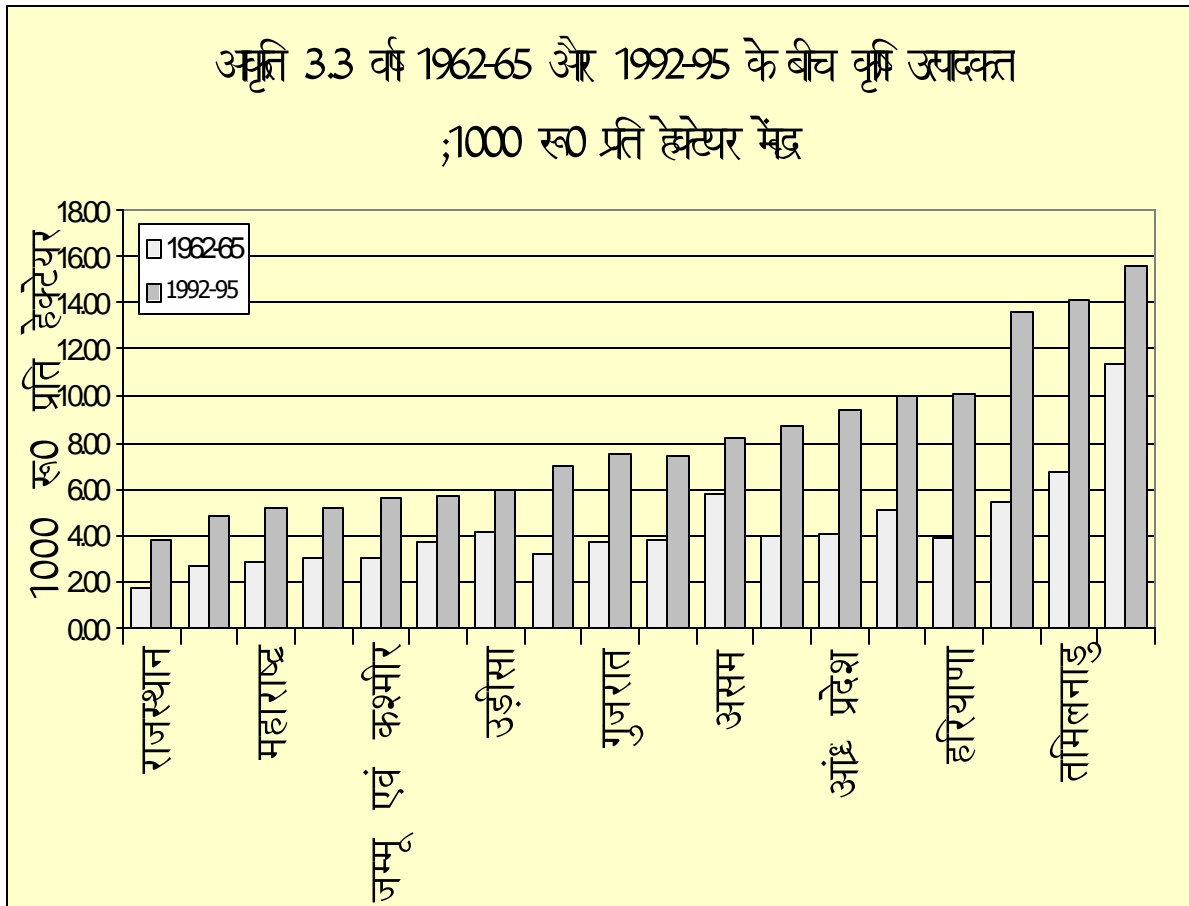
3.31 कृषि क्षेत्र में देश की 69 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार मिलता है। अतः यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका समग्र संवृद्धि, आय स्तरों तथा लोगों की संपन्नता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देश के विभिन्न राज्यों में कृषि की उत्पादकता में परिवर्तन राज्यों के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रगति का एक अच्छा सूचकांक है तथा इसका प्रभाव राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

3.32 कृषि उत्पादकता को आंकने के लिए हम 1962-65 तथा 1992-95। (विवरण अनुलग्नक 3.4 में दिए गए हैं) की समय अवधि के बीच विभिन्न राज्यों के लिए तीन वर्ष औसत भूमि उपज में संवृद्धि का प्रयोग करते हैं। आरम्भिक अवधि, 1962-65 में केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के डेल्टा तटीय राज्यों के लिए उपज स्तर उच्च थे जिसमें केरल की उपज सबसे अधिक थी। सिंचाई का विकास इसका मुख्य कारण था।

3.33 अखिल भारत स्तर पर, 1962-65 से 1970-73 की अवधि के दौरान, भूमि उपज 1.64 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब तथा हरियाणा ने संवृद्धि की बहुत ऊंची दरें प्राप्त कीं। उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा तमिलनाडु ने संतुलित संवृद्धि दरें की।

3.34 1970-73 तक, नई प्रौद्योगिकी के आने से अपेक्षित स्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हुए। 1970-73 से 1980-83 की अवधि के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में गेहूं तथा चावल प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ इन क्षेत्रों में भी उत्पादकता स्तरों में लाभ दर्ज करने आरम्भ किए। इस अवधि में गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब ने संवृद्धि की बहुत ऊंची दरें रिकार्ड कीं।

* भूमि उपज के उत्पादन को फसल के क्षेत्र द्वारा भाग देने पर प्राप्त मूल्य को परिभाषित किया जाता है।



स्रोत : भारत सरकार, भारत में मुख्य फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन (विभिन्न मामलों), कृषि मंत्रालय

3.35 1980-83 तथा 1992-95 के दौरान उत्पादकता की संवृद्धि की बहुत ऊंची दर अर्थात् 3.15 प्रतिशत प्रति वर्ष रिकार्ड की गई। यह संवृद्धि न्यूनाधिक सभी क्षेत्रों में हुई। पूर्वी क्षेत्र ने इस अवधि में उत्पादकता स्तरों में महत्वपूर्ण वृद्धि की। पिछली अवधि के दौरान केवल 0.57 की दर की तुलना में इसने 3.32 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च संवृद्धि की। पश्चिम बंगाल ने प्रति वर्ष 4.39 प्रतिशत की उच्चतम संवृद्धि दर प्राप्त की। इस समय अवधि की विशिष्ट बात यह थी कि जम्मू व कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों द्वारा संशोधित संवृद्धि दरें प्राप्त की गईं।

3.36 तीन दशकों की पूरी अवधि पर नजर डालने से यह देखने में आता है कि पूरे देश के लिए 1962-65 से 1992-95 की अवधि के दौरान कृषि उत्पादकता की संवृद्धि दर 2.30 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। इस अवधि के दौरान राज्यों में भी कृषि उत्पादकता की संवृद्धि की दरों में भी मध्यम स्तर की वृद्धि हुई। उत्पादन में उच्च संवृद्धि दर प्राप्त की तथा कृषि उत्पादकता में औसत से अधिक संवृद्धि दरें प्राप्त की। इस अवधि के दौरान असम

के पूर्वी राज्यों, बिहार तथा उड़ीसा ने अपेक्षाकृत कम संवृद्धि दर प्राप्त की। राज्यों की कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति से राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में तेज गिरावट की प्रवृत्ति उचित रूप से मेल खाती है। जिन राज्यों में कृषीय उत्पादकता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, वह वही राज्य थे जिनमें गरीबी में तेजी से गिरावट आई है।

जनसंख्या

3.37 चीन के बाद, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें जनसंख्या ने सौ करोड़ (बिलियन) के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत की जनसंख्या 1941 से 2001 में लगभग तिगुनी हो गई है। 70 के दशक में जनसंख्या की संवृद्धि दर 2.24 प्रतिशत प्रति वर्ष थी तथा इसके बाद धीरे-धीरे यह घट रही है यद्यपि जनसंख्या समग्र रूप से काफी तीव्र दर से बढ़ रही है। 1991-2001 की अवधि में संवृद्धि की दर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम रही है।

3.38 1991-2001 के दशक के दौरान, जनसंख्या में उच्चतम संवृद्धि दर नागालैंड राज्य की थी, जो कि असाधारण रूप से 4.97 प्रतिशत थी। 2.63 तथा 2.62 प्रतिशत की दर से मणिपुर और मेघालय का नंबर नागालैंड के बाद आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की संवृद्धि दरें लगातार ऊंची रहीं। इन राज्यों में जनसंख्या की समस्या पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्रों की संवृद्धि दर 4 प्रतिशत से अधिक थी। यद्यपि, इसका बहुत बड़ा भाग विस्थापन के कारण था। केरल तमिलनाडु तथा गोवा जैसे राज्यों में

1991-2001 के दशक में संवृद्धि दर में पर्याप्त गिरावट आई। इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत नीची दर रिकार्ड की गईं। केरल की 0.90 प्रतिशत की न्यूनतम दर के पश्चात् 1.06 प्रतिशत के साथ तमिलनाडु की थी।

3.39 कुल जनन क्षमता दर (टीएफआर) 2.1 को जनन क्षमता का प्रतिष्ठापन स्तर माना जाता है जिसे सभी राज्यों में जनसंख्या स्थिरता के लिए प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। भविष्य में 1998 के लिए कुल जनन क्षमता दरों की तुलना तथा 2007 वर्ष के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कु.ज. दर का प्रक्षेपण निर्देशित है।

तालिका 3.8
कुल जनन दर, 1998 तथा अनुमानित कुल जनन दर, 2007

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	कुल जनन दर 1998	कुल जनन दर 2007
1	केरल	1.8	उ.न.
2	तमिलनाडु	2.0	उ.न.
3	आन्ध्र प्रदेश	2.4	उ.न.
4	कर्नाटक	2.4	2.3
5	पश्चिम बंगाल	2.4	उ.न.
6	पंजाब	2.6	उ.न.
7	महाराष्ट्र	2.7	2.3
8	उड़ीसा	2.9	2.4
9	गुजरात	3.0	उ.न.
10	अखिल भारत	3.2	2.7
11	असम	3.2	2.5
12	हरियाणा	3.3	2.1
13	मध्य प्रदेश	3.9	3.4
14	राजस्थान	4.1	3.8
15	बिहार	4.3	3.3
16	उत्तर प्रदेश	4.6	4.4
17	गोवा	1.77	उ.न.
18	हिमाचल प्रदेश	2.14	उ.न.
19	दिल्ली	2.40	उ.न.
20	अरुणाचल प्रदेश	2.52	उ.न.
21	जम्मू व कश्मीर	2.71	उ.न.
22	सिक्किम	2.75	उ.न.
23	मिज़ोरम	2.89	उ.न.
24	मणिपुर	3.04	उ.न.
25	नागालैंड	3.77	उ.न.
26	मेघालय	4.57	उ.न.

टिप्पणी : उ.न. : इन राज्यों के लिए अनुमान तैयार नहीं किए गए।

स्रोत : कुल जनन दर, 1998 क्र.सं. 1 से 16 : सैम्पल पंजीकरण प्रणाली 1998

17 से 26 : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99

कुल जनन दर 2007 अनुमानित आंकड़ें : जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग, योजना आयोग

3.40 इस तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी राज्यों को छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के नए गठित राज्यों को छोड़कर 2007 तक कुल कु.प्र.द. तीन से कम रखनी होगी। 15 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 2.1 की कु.प्र.द. प्राप्त कर ली है लेकिन अधिकांश राज्य 2.1 से अधिक की कु.उ.द. के साथ अभी भी बढ़ रहे हैं तथा इन राज्यों में दसवीं योजना के दौरान नीति संबंधी निर्णय लेने होंगे।

मानव विकास

3.41 मानव विकास से आशय लोगों की चयन प्रक्रिया का विस्तार करना है। सैद्धान्तिक रूप से यह चयन प्रक्रिया असंख्य हो सकते हैं तथा समय-समय पर बदल सकते हैं। परन्तु विकास के सभी स्तरों पर, लोगों का लम्बा तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा अच्छे जीवन स्तर के लिए संसाधनों की आवश्यकता पर पहुंचना जैसे तीन आवश्यक स्तर हैं। यदि यह तीन आवश्यक स्तर उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य कोई अवसरों तक पहुंचा नहीं जा सकता है।

3.42 मानव विकास के दो पहलू हैं : मानव योग्यताओं का निर्धारण- जैसा कि बेहतर स्वास्थ्य, ज्ञान तथा कौशल- तथा लोगों द्वारा प्राप्त की गई योग्यताओं को प्रयोग में लाना। इसलिए विकास का तात्पर्य मात्र आय और पूंजी को बढ़ाना नहीं है। विकास में संकेन्द्रण लोगों पर होना चाहिए।

3.43 इस खण्ड में, हम शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लिंग के क्षेत्रों सहित राज्यों के लोक व्यय अनुपातों से संबंधित तुलनात्मक रूप रेखाओं का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001 में निकाले गए मानव विकास सूचकांक के परिणामों पर भी विचार किया गया है।

शिक्षा

3.44 शिक्षा विकास प्रक्रिया में दो कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला शिक्षा एक साध्य के जीवन के दृष्टिकोण एवं गुणवत्ता

को बेहतर बनाती है, दूसरा शिक्षा मानव पूंजी का निर्माण करती है तथा यह विकास प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है।

3.45 यद्यपि शिक्षा के स्तर एवं तरीका मापा जा सकता है परन्तु शिक्षा उपलब्धियों के किसी मापन में साक्षरता आंकड़ें होना आवश्यक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए साक्षरता का स्तर एक महत्वपूर्ण और मूलभूत मानक है।

3.46 शिक्षा की समग्रता के अतिरिक्त, महिला शिक्षा की विकास प्रक्रिया में एक विशेष भूमिका है इसलिए, हम महिला साक्षरता को विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी अलग से देखते हैं।

राज्यों में साक्षरता स्तर

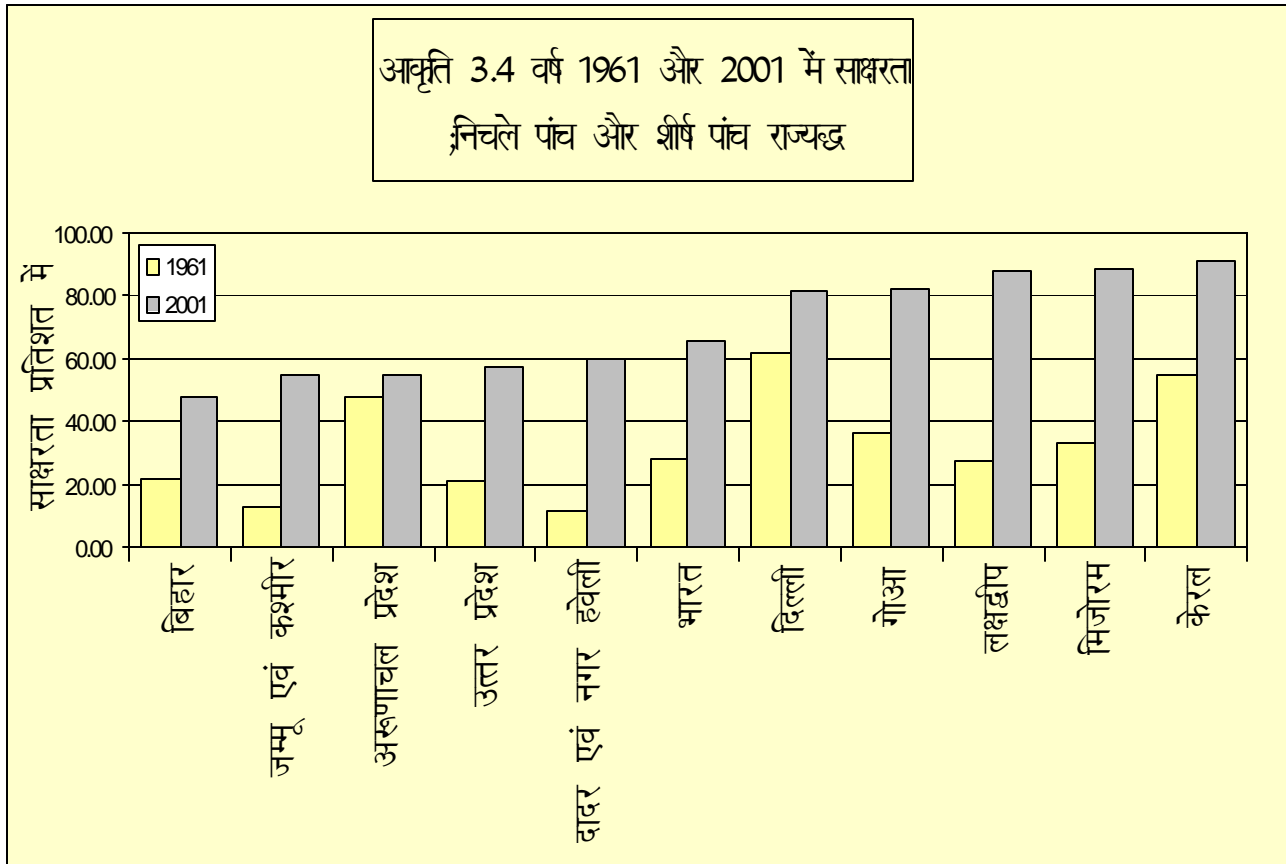
3.47 भारत में साक्षरता दरों में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। 1951 में 16.6 प्रतिशत से बढ़कर साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत हो गई है। राज्यों में केरल में 90.92 की सबसे ऊंची साक्षरता दर है, इसके बाद मिज़ोरम आता है जिसमें 2001 में साक्षरता दर 88.49 प्रतिशत थी। पोण्डीचेरी, गोवा तथा दिल्ली में साक्षरता दर 80 प्रतिशत से अधिक थी। हाल ही में, विशेष रूप से पिछले दशक में कुछ परम्परागत शिक्षा में पिछड़े राज्यों ने भी महत्वपूर्ण साक्षरता सुधार दिखाए हैं। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में शिक्षा लगभग 20 प्रतिशत बिन्दू एकल दशक में बढ़ी है। राजस्थान में 1991 में साक्षरता दर 38.50 प्रतिशत से 2001 में 61.03 तक बढ़ी है। मध्य प्रदेश ने 1991 में 44.2 प्रतिशत से 2001 में 64.11 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है। (तालिका 3.9)

3.48 बिहार में स्थिति विपरीत है। बिहार में साक्षरता, जो कि सन 1991 में राजस्थान के साथ बराबरी पर थी वह केवल एक दशक में बहुत पीछे रह गई है। राजस्थान में 2001 में 1 प्रतिशत के मुकाबले बिहार में साक्षरता दर केवल 47.53 प्रतिशत रह गई है। **आफति** 3.4 1991 से 2001 की अवधि के लिए ऊपरी पांच तथा सतही पांच राज्यों का निष्पादन दिखाती है।

तालिका 3.9
राज्य-वार साक्षरता दरें प्रतिशत में
(2001 के रैंकों के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001
1	केरल	40.70	55.10	60.40	70.40	89.80	90.92
2	मिज़ोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	59.90	82.30	88.49
3	लक्षद्वीप	15.20	27.20	43.70	55.10	81.80	87.52
4	गोवा	23.00	36.20	उ.न.	उ.न.	75.50	82.32
5	दिल्ली	38.40	62.00	56.60	61.50	75.30	81.82
6	चण्डीगढ़	उ.न.	55.10	61.60	64.80	77.80	81.76
7	पांडिचेरी	उ.न.	43.70	46.00	55.90	74.70	81.49
8	अण्डमान व निकोबार द्वीप	25.80	40.10	43.60	51.60	73.00	81.18
9	दमन व दीव	22.90	34.90	44.80	56.70	71.20	81.09
10	महाराष्ट्र	20.90	35.10	39.20	47.20	64.90	77.27
11	हिमाचल प्रदेश	7.70	24.90	32.00	42.50	63.90	77.13
12	त्रिपुरा	15.50	24.30	31.00	42.10	60.40	73.66
13	तमिलनाडु	20.80	36.40	39.50	46.80	62.70	73.47
14	गुजरात	उ.न.	उ.न.	35.80	43.70	61.30	69.97
15	पंजाब	15.20	31.50	33.70	40.90	58.50	69.95
16	सिक्किम	7.30	14.20	17.70	34.10	56.90	69.68
17	पश्चिम बंगाल	24.00	34.50	33.20	40.90	57.70	69.22
18	मणिपुर	11.40	36.00	32.90	41.40	59.90	68.87
19	हरियाणा	उ.न.	24.10	26.90	36.10	55.80	68.59
20	नागालैंड	10.40	20.40	27.40	42.60	61.60	67.11
21	कर्नाटक	19.30	29.80	31.50	38.50	56.00	67.04
	अखिल भारत	18.30	28.30	34.45	43.57	52.20	65.38
22	असम	18.30	33.00	28.70	उ.न.	52.90	64.28
23	मध्य प्रदेश	9.80	20.50	22.10	27.90	44.20	64.11
24	मेघालय	उ.न.	उ.न.	29.50	34.10	49.10	63.31
25	उड़ीसा	15.80	25.20	26.20	43.20	49.10	63.31
26	आन्ध्र प्रदेश	13.20	24.60	24.60	29.90	44.10	61.11
27	राजस्थान	8.90	18.10	19.10	24.40	38.60	61.03
28	दादरा व नागर हवेली	4.00	11.60	15.00	26.70	40.70	60.03
29	उत्तर प्रदेश	10.80	20.70	21.70	27.20	41.60	57.36
30	अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	47.90	11.30	20.80	41.60	54.74
31	जम्मू व कश्मीर	उ.न.	13.00	18.60	26.70	उ.न.	54.46
32	बिहार	12.20	21.80	19.90	26.20	38.50	47.53

स्रोत : भारत महापंजीयक का कार्यालय



टिप्पणी : 1. 1961 के लिए मिज़ोरम के संबंध में असम के आंकड़ें दिए गए हैं।

2. उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में उत्तरांचल सम्मिलित है।

स्रोत : भारत के महा पंजीयक का कार्यालय

साक्षरता दरों में लिंग असमानताएं

3.49 अखिल भारतीय स्तर तथा राज्यों में अलग-अलग स्तर में लिंग असमानताएं हैं। मिज़ोरम में इस प्रकार की असमानता सबसे कम थी जहां 2001 में पुरुष साक्षरता 90.69 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 86.13 प्रतिशत है। केरल के लिए 2001 में दोनों दरें क्रमशः 94.2 तथा 87.86 थी। सबसे अधिक असमानता कम साक्षरता वाले राज्यों में है। बिहार में, 2001 में महिलाओं के 33.57 प्रतिशत के मुकाबले 60.32 प्रतिशत पुरुष साक्षरता रिकार्ड किए गए। उत्तर प्रदेश में दरें क्रमशः 70.23 तथा 42.98 प्रतिशत तथा राजस्थान में 76.46 तथा 44.34 प्रतिशत थी। साथ ही यह भी मानना होगा कि इन राज्यों के साथ-साथ जम्मू व कश्मीर तथा मध्य प्रदेश 1961 से लम्बी दूरी तय कर चुके हैं जबकि महिला साक्षरता की दरें केवल एक अंक में थी। मेघालय इसका अपवाद है जहां

समग्र साक्षरता दर कम होने की बजाए पुरुष तथा महिला दर में अंतर बहुत कम है। (तालिका 3.10)

लिंग संतुलन

3.50 लिंग अनुपात, (मानदंड प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या) भारत में लिंग असमानता का द्योतक है। जीव विज्ञान के अनुसार लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए तथा विश्व के लगभग सभी देशों में ऐसा ही है। यद्यपि, भारत में अधिकतर राज्यों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक है। इसका मुख्य कारण भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का ठीक न होना है जिसके कारण बाल विवाह, निम्न साक्षरता स्तर, उच्च जनन क्षमता तथा मृत्यु दर आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

तालिका 3.10
पुरुषों एवं महिलाओं के लिए साक्षरता दरें - 1961, 1981 तथा 2001
(महिलाओं के लिए 2001 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं. राज्य/सं.रा.क्षे.	1961		1981		2001		
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	
1	केरल	64.9	45.6	75.3	65.7	94.2	87.9
2	मिज़ोरम	उ.न.	उ.न.	64.5	54.9	90.7	86.1
3	लक्षद्वीप	42.0	12.8	65.2	44.6	93.2	81.6
4	चण्डीगढ़	62.6	43.1	69.0	59.3	85.7	76.7
5	गोवा	48.7	22.8	उ.न.	उ.न.	88.9	75.5
6	अण्डमान व निकोबार द्वीप	48.8	24.5	58.7	42.1	86.1	75.3
7	दिल्ली	70.4	50.9	68.4	53.1	87.4	75.0
8	पांडिचेरी	58.9	28.7	65.8	45.7	88.9	74.1
9	दमन व दीव	44.6	26.0	65.6	47.6	88.4	70.4
10	हिमाचल प्रदेश	37.6	11.2	53.2	31.5	86.0	68.1
11	महाराष्ट्र	49.3	19.8	58.8	34.8	86.3	67.5
12	त्रिपुरा	35.3	12.4	51.7	32.0	81.5	65.4
13	तमिलनाडु	51.6	21.1	58.3	35.0	82.3	64.6
14	पंजाब	40.7	20.7	47.2	33.7	75.6	63.6
15	नागालैंड	27.2	13.0	50.1	33.9	71.8	61.9
16	सिक्किम	22.4	4.9	43.9	22.2	76.7	61.5
17	मेघालय	उ.न.	उ.न.	37.9	30.1	66.1	60.4
18	पश्चिम बंगाल	46.6	20.3	50.7	30.3	77.6	60.2
19	मणिपुर	53.5	18.9	53.3	29.1	77.9	59.7
20	गुजरात	0.0	0.0	54.4	32.3	80.5	58.6
21	कर्नाटक	42.3	16.7	48.8	27.7	76.3	57.5
22	हरियाणा	35.1	11.3	48.2	22.3	79.3	56.3
23	असम	44.3	19.6	उ.न.	उ.न.	71.9	56.0
	अखिल भारत	40.4	15.4	56.4	29.8	75.9	54.2
24	आन्ध्र प्रदेश	35.0	14.0	39.3	20.4	70.0	51.2
25	उड़ीसा	40.3	10.1	47.1	21.1	76.0	51.2
26	मध्य प्रदेश	32.2	8.1	39.5	15.5	76.8	50.3
27	राजस्थान	28.1	7.0	36.3	11.4	76.5	44.3
28	अरुणाचल प्रदेश	53.4	24.1	28.9	11.3	64.1	44.2
29	दादरा व नागर हवेली	17.7	5.0	36.3	16.8	73.3	43.0
30	उत्तर प्रदेश	31.9	8.3	38.8	14.0	70.2	43.0
31	जम्मू व कश्मीर	19.8	5.1	36.3	15.9	65.8	41.8
32	बिहार	35.2	8.2	38.1	13.6	60.3	33.6

टिप्पणी : राज्यों/सं.रा.क्षे. को 2001 में रैंक के अनुसार व्यवस्थित है।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

स्रोत : भारत महा पंजीयक का कार्यालय

तालिका 3.11
भारत में लिंग अनुपात (महिलाएं प्रति हजार पुरुष)
(2001 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001
1	केरल	1028	1022	1016	1032	1036	1058
2	पांडिचेरी	1030	1013	989	985	979	1001
3	तमिलनाडु	1007	992	978	977	974	986
4	आन्ध्र प्रदेश	986	981	977	975	972	978
5	मणिपुर	1036	1015	980	971	958	978
6	मेघालय	949	937	942	954	955	975
7	उड़ीसा	1022	1001	988	981	971	972
8	हिमाचल प्रदेश	912	938	958	973	976	970
9	कर्नाटक	966	959	957	963	960	964
10	गोवा	1128	1066	981	975	967	960
11	त्रिपुरा	904	932	943	946	945	950
12	लक्षद्वीप	1043	1020	978	975	943	947
13	मिज़ोरम	1041	1009	946	919	921	938
14	पश्चिम बंगाल	865	878	891	911	917	934
15	अखिल भारत	946	941	930	934	927	933
16	असम	868	869	896	910	923	932
17	महाराष्ट्र	941	936	930	937	934	922
18	राजस्थान	921	908	911	919	910	922
19	बिहार	1000	1005	957	948	907	921
20	गुजरात	952	940	934	942	934	921
21	मध्य प्रदेश	945	932	920	921	912	920
22	नागालैंड	999	933	871	863	886	909
23	अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	894	861	862	859	901
24	जम्मू व कश्मीर	873	878	878	892	896	900
25	उत्तर प्रदेश	998	907	876	882	876	898
26	सिक्किम	907	904	863	835	878	875
27	पंजाब	844	854	865	879	882	874
28	हरियाणा	871	868	867	870	865	861
29	अण्डमान व निकोबार द्वीप	625	617	644	760	818	846
30	दिल्ली	768	785	801	808	827	821
31	दादरा व नागर हवेली	946	963	1003	974	952	811
32	चण्डीगढ़	781	652	749	769	790	773
33	दमन व दीव	1125	1169	1099	1062	969	709

टिप्पणी : राज्यों/सं.रा.क्षे. को 2001 में रैंक के अनुसार व्यवस्थित है।

स्रोत : भारत की जनगणना

3.51 1951 में भारत में ऐसे 10 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र थे जिनमें लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में था। 2001 तक केवल केरल तथा पांडिचेरी में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में था। 1951 में कुछ राज्य जिनमें स्थिति अच्छी थी, उनमें भी अनुपात बहुत नीचे गिरा, अर्थात् उड़ीसा, जहां 1951 में 1022 से 2001 में 972 तक गिरा तथा तमिलनाडु में उसी अवधि में अनुपात में गिरावट 1007 से 986 हुई। बिहार में 1951 में 1000 से 2001 में 921 की तेज गिरावट दिखाई। राजस्थान ने पिछले दशक में 910 से 922 का उपांतिक सुधार हुआ जो कि अपने निम्न आरम्भिक बिन्दु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले दशक के दौरान, विशेष तौर पर हरियाणा तथा पंजाब जैसे अपेक्षाकृत अच्छे राज्यों में हुई गिरावट चिंता का विषय है।

3.52 केरल एक मात्र ऐसा राज्य है जहां स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हर समय अनुपात महिलाओं के पक्ष में रहा (तालिका 3.11)।

स्वास्थ्य

3.53 देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों में जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार एक मुख्य दबाव क्षेत्र रहा है। इसे अविकसित तथा समाज के पिछड़े लोगों पर विशेष सकेन्द्रण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। इस खण्ड में हम स्वास्थ्य स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों का मूल्यांकन करेंगे कि क्या इस बहुत महत्वपूर्ण मापदण्ड ने सुधार कुछ संकेत दिए हैं।

3.54 स्वास्थ्य स्थिति के विश्लेषण में दो मूल संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, वह है शिशु मृत्यु दर तथा जन्म पर जीवन प्रत्याशा।

शिशु मृत्यु दर

3.55 शिशु मृत्यु दर जिसे 6 वर्ष की कम आयु के प्रति एक हजार शिशु की मृत्यु के आधार पर आंका जाता है, जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पोषण आदि

के संदर्भ में मानव विकास के स्तर का भी सूचक है। गरीबी, कुपोषण, स्तनपान कराने की कमी तथा सफाई की कमी ये सब उच्च शिशु मृत्यु दर के साथ जुड़े हुए हैं। उच्च शिशु मृत्यु तथा उच्च जनन क्षमता एक दूसरे से सम्बद्ध है। इस आशय के साथ प्रामाण भी है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो थोड़े समय में शिशु मृत्यु समग्र जनसंख्या संवृद्धि को कम कर देती है तथापि अप्रत्यक्ष एवं कम मृत्यु का दूरगामी प्रभाव प्रतिपूरक मात्रा से अधिक जनन क्षमता कम करता है क्योंकि जब शिशु के जीवित रहने की निश्चितता होती है, मां-बाप “बीमा जन्म” को कम कर देते हैं तथा बच्चे के लिए गुणवत्ता निवेश करते हैं।

3.56 भारत में लगभग सभी राज्यों में 1971 से 1998 की अवधि में शिशु मृत्यु दरों में गिरावट हुई है, जैसा कि तालिका 3.12 में देखा जा सकता है, फिर भी कुछ राज्यों में स्थिति अन्य की अपेक्षा बेहतर रही है।

3.57 1981 में, मध्य प्रदेश में शि.मृ.द. सबसे ऊंची 150 थी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में यह दर 130 थी। हरियाणा, उड़ीसा तथा अरुणाचल प्रदेश ने भी उच्च शि.मृ.द. रिकार्ड की। मणिपुर ने सबसे कम शि.मृ.द. 32 पर रिकार्ड की।

3.58 1991 तक, लगभग सभी राज्यों में शि.मृ.द. गिर गई। परन्तु पुरुषों के मामले में शि.मृ.द. महिलाओं की अपेक्षा काफी अधिक थी जबकि 1981 में महिलाओं की मृत्यु दर काफी कम थी।

3.59 1991 तथा 1998 के बीच गिरावट तेज थी। समस्त भारत के लिए 1998 में शि.मृ.द. 71 थी। आज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान अपेक्षाकृत उच्च शि.मृ.द. वाले राज्य हैं। सभी राज्यों के बीच मिज़ोरम 23 पर तथा मणिपुर 25 पर, उत्तर-पूर्वी राज्यों ने सबसे कम शि.मृ.द. रिकार्ड की।

3.60 पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा बिहार जैसे कुछ राज्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के उच्च शि.मृ.द. होना चिन्ता का विषय है, क्योंकि इन राज्यों में महिला बच्चे की स्थिति पहले ही ठीक नहीं मानी जाती है।

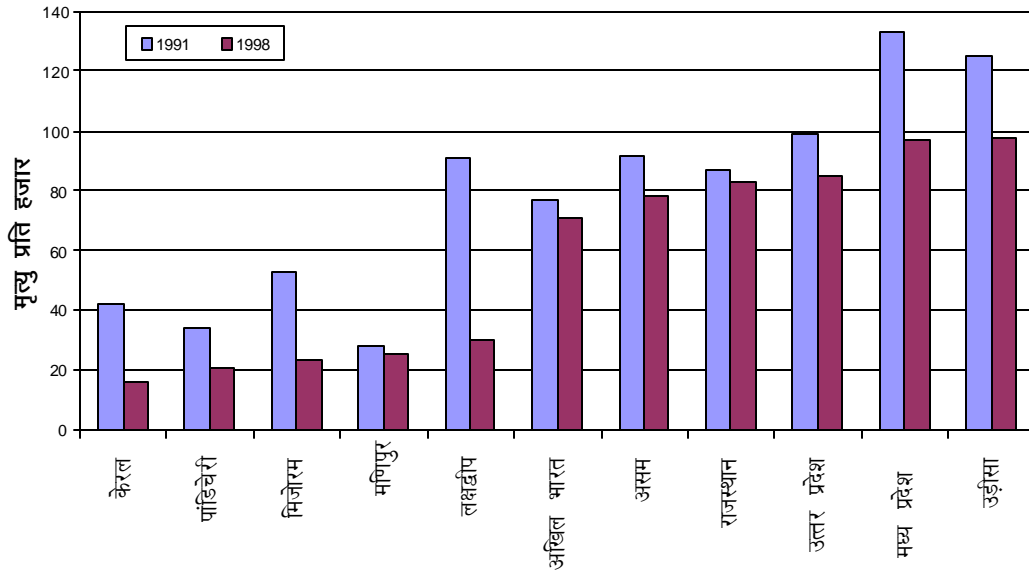
तालिका 3.12
राज्य-वार शिशु मृत्यु दर

क्र. सं.	राज्य/ सं.रा.क्षे.	1981			1991			2001
		पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	व्यक्ति
1	केरल	55	48	52	45	41	42	16
2	पांडिचेरी	77	68	73	32	35	34	21
3	मिज़ोरम	73	65	69	51	56	53	23
4	मणिपुर	31	33	32	29	27	28	25
5	लक्षद्वीप	124	88	118	100	78	91	30
6	अण्डमान व निकोबार द्वीप	78	66	77	71	61	69	30
7	चण्डीगढ़	53	53	53	50	47	48	32
8	गोवा	60	56	57	56	48	51	36
9	अरुणाचल प्रदेश	141	111	126	111	103	91	44
10	जम्मू व कश्मीर	78	78	78	उ.न.	उ.न.	उ.न.	45
11	महाराष्ट्र	96	89	92	72	76	74	49
12	त्रिपुरा	106	116	111	81	84	82	49
13	दिल्ली	66	70	67	55	51	54	51
14	मेघालय	81	76	79	79	82	80	52
15	सिक्किम	105	87	96	58	62	60	52
16	तमिलनाडु	89	82	86	55	51	54	53
17	पश्चिम बंगाल	103	57	95	75	51	62	53
18	पंजाब	74	79	77	81	53	74	54
19	कर्नाटक	87	74	81	74	72	74	58
20	दादरा व नागर हवेली	102	93	98	84	73	81	61
21	गुजरात	81	84	84	74	82	78	64
22	हिमाचल प्रदेश	101	89	92	84	81	82	64
23	आन्ध्र प्रदेश	100	82	91	67	51	55	66
24	बिहार	95	94	94	62	89	75	67
25	हरियाणा	87	119	94	57	54	52	69
26	अखिल भारत	122	108	115	74	79	77	71
27	असम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	96	87	92	78
28	राजस्थान	114	114	114	94	79	87	83
29	उत्तर प्रदेश	131	128	130	98	104	99	85
30	मध्य प्रदेश	158	140	150	131	136	133	97
31	उड़ीसा	119	111	115	129	111	125	98
32	नागालैंड	76	58	68	51	52	51	उ.न.
33	दमन व दीव	60	56	57	61	50	56	उ.न.

टिप्पणी : क) गोवा तथा दमन और दीव के लिए अनुमान पूर्ण योग है।
 ख) महिला एवं पुरुष शिशु मृत्यु दर 1998 से उपलब्ध नहीं है।
 ग) छोटे राज्यों/सं.रा.क्षे. के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है।
 घ) उ.न. : उपलब्ध नहीं

स्रोत : भारत के महा पंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय

आकृति 3.5
शीर्ष पांच और निचले पांच राज्यों में शिशु मृत्यु दर 1998



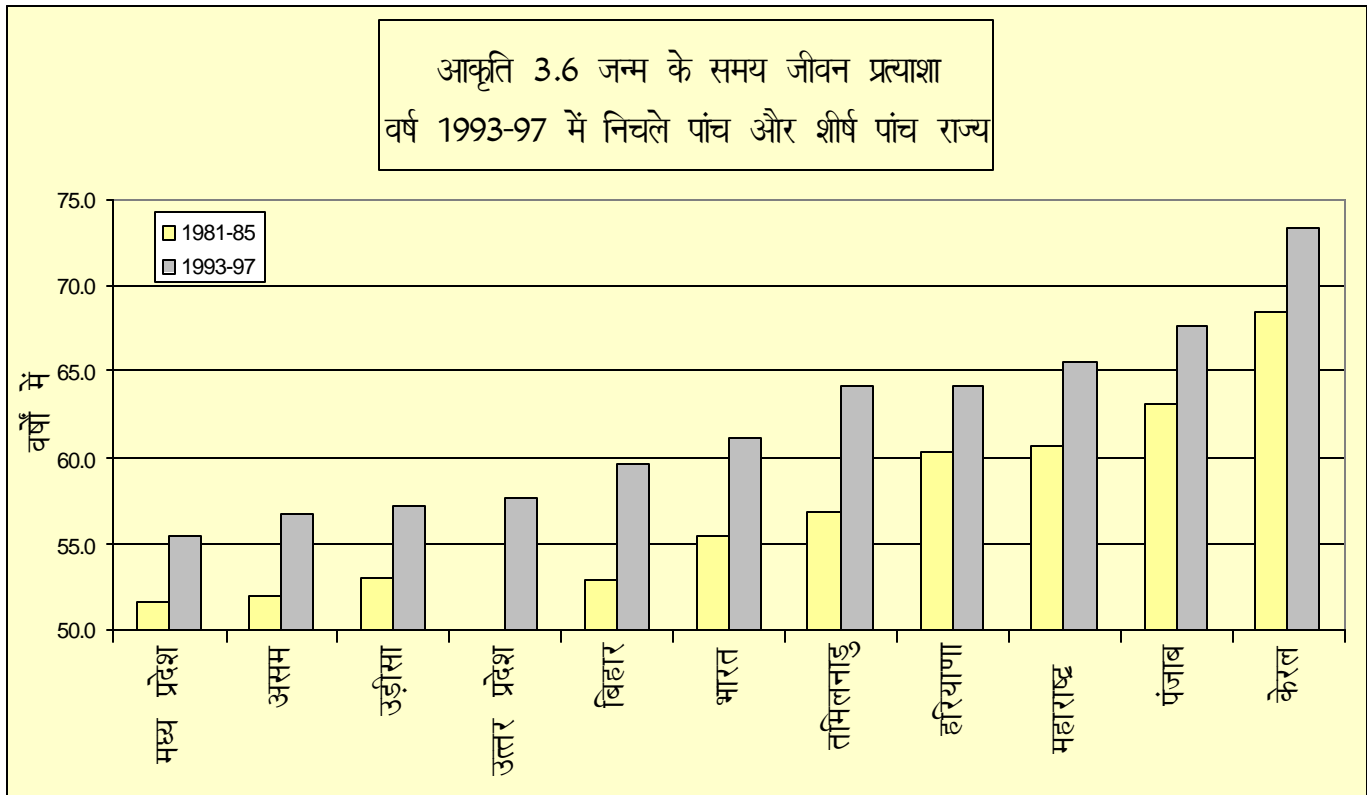
स्रोत : भारत के महा पंजीयक का कार्यालय

तालिका 3.13
राज्य-वार जन्म पर जीवन प्रत्याशा (1993-97 में रैंक पर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981-85	1991-95	1992-96	1993-97
1	केरल	68.4	72.9	73.1	73
2	पंजाब	63.1	67.2	67.4	68
3	महाराष्ट्र	60.7	64.8	65.2	66
4	तमिलनाडु	56.9	63.3	63.7	64
5	हरियाणा	60.3	63.4	63.8	64
6	कर्नाटक	60.7	62.5	62.9	63
7	पश्चिम बंगाल	57.4	62.1	62.4	63
8	गुजरात	57.6	61.0	61.4	62
9	आन्ध्र प्रदेश	58.4	61.8	62.0	62
10	अखिल भारत	55.5	60.3	60.7	61
11	राजस्थान	53.5	59.1	59.5	60
12	बिहार	52.9	59.3	59.4	60
13	उत्तर प्रदेश	50.0	56.8	57.2	58
14	उड़ीसा	53.0	56.5	56.9	57
15	असम	51.9	55.7	56.2	57
16	मध्य प्रदेश	51.6	54.7	55.2	56

टिप्पणी : 1. अपेक्षाकृत छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।
2. मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल है। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है।
3. झारखंड, बिहार में सम्मिलित है।

स्रोत : नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित संक्षिप्त जीवन तालिकाएं।



स्रोत : नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित संक्षिप्त जीवन तालिकाएं।

जन्म पर जीवन प्रत्याशा

3.61 जन्म पर जीवन प्रत्याशा अथवा दीर्घायु लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर अच्छे होने का एक समग्र संकेतक है। जैसे-जैसे समाज सम्पन्न होता है, लोगों के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। 1981-85 से 1993-97 तक की अवधि के लिए जीवन स्थिति तालिका 3.13 में दी गई है।

3.62 1981-85 से पूरे 1993-97 तक मुख्य राज्यों में पंजाब के बाद केरल की जीवन प्रत्याशा की दर सबसे ऊंची थी। 1993-97 में ऊपरी पांच तथा सतही पांच राज्यों से संबंधित स्थिति आपति 3.6 में दी गई है।

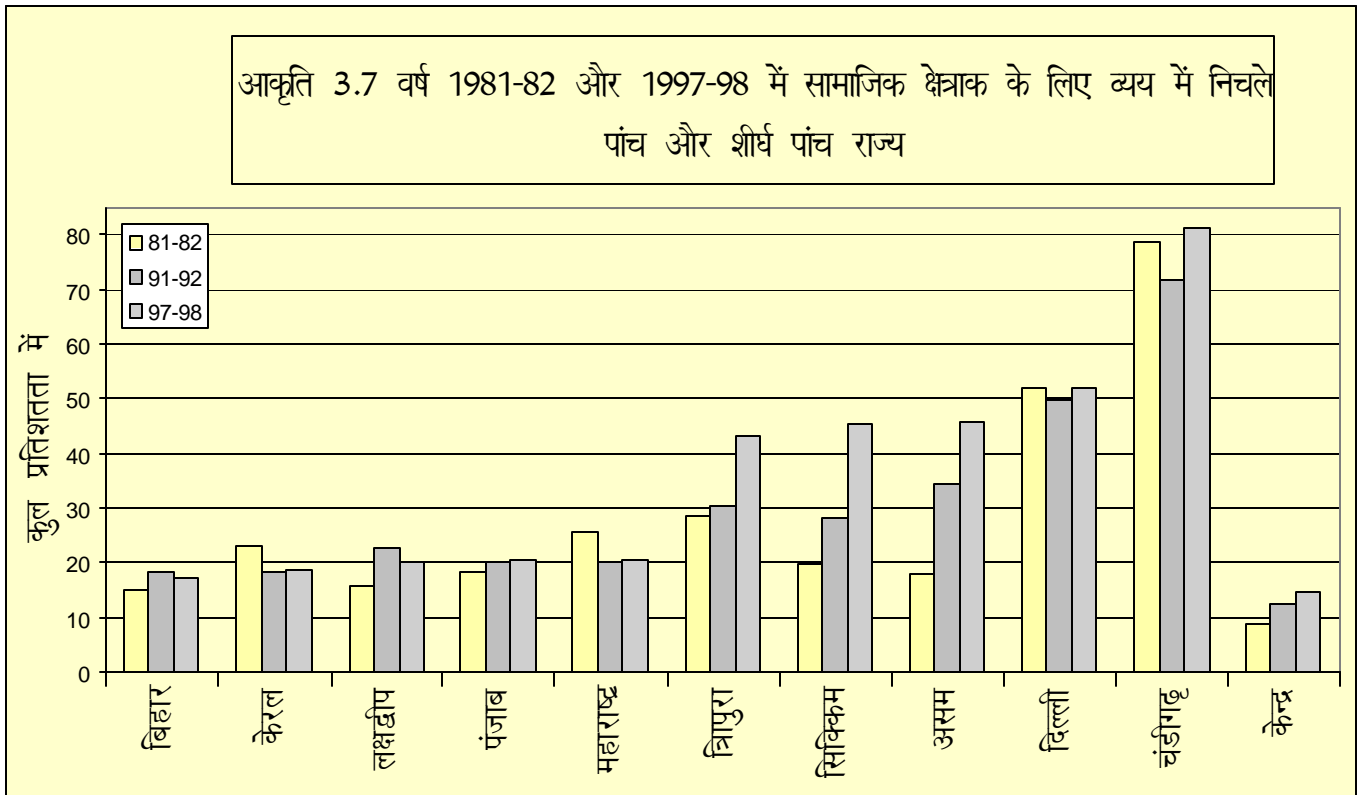
सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित योजना व्यय

वास्तविक योजना व्यय की क्षेत्रीय रचना

3.63 पिछले दो दशकों में क्षेत्रीय संरचना के योजना व्यय

पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि 1981-82 तथा 1997-98 के बीच अधिकतर बड़े कृषीय राज्यों के लिए कृषि तथा सिंचाई के आवंटन ने अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई है। उत्तर प्रदेश में यह गिरावट 19.05 तक हुई तथा पंजाब में 25.24 प्रतिशत से 12.75 प्रतिशत हुई। हरियाणा तथा मध्य प्रदेश ने भी कृषि में लगने वाले लोक व्यय के अंश में गिरावट आई है। कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र केवल ऐसे राज्य हैं कि जिनमें इस अवधि के दौरान कृषि की ओर लगने वाले योजना व्यय के अंश में बढ़ोत्तरी हुई है।

3.64 सामाजिक क्षेत्रों के मामले में अनेक राज्यों में इस अवधि में व्यय के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों में भी सामाजिक क्षेत्रों में योजना व्यय बढ़ा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम तथा हरियाणा में प्रवृत्तियां उसी प्रकार हैं। यद्यपि केरल, महाराष्ट्र तथा जम्मू व कश्मीर में इस प्रतिशत में गिरावट आई है। 1997-98 के वर्ष में उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्च व्यय एक उल्लेखनीय बिन्दु है। यह सभी राज्य 40 प्रतिशत से अधिक सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करते हैं (आपति 3.7)।



स्रोत : विभिन्न योजना दस्तावेज, योजना आयोग

3.65 मानव विकास के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए व्यय को देखने के लिए हम शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुपातों पर नजर डालते हैं। यह शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्ययों को कुल लोक व्यय के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। इन क्षेत्रों में लोग व्ययों का बड़ा भाग योजना के बाहर होगा, यह अनुपात एक अच्छा तुलनात्मक संकेतक हो सकता है (तालिका 3.14)।

3.66 यह देखा जा सकता है कि अधिकतर राज्यों ने शिक्षा व्यय अनुपातों में बढ़ोत्तरी दर्शाई है। इससे यह परिलक्षित होता है कि वे शिक्षा पर लोक व्यय का पर्याप्त हिस्सा खर्च कर रहे हैं। असम के लिए शिक्षा व्यय अनुपात 1980-81 में 12.76 से बढ़कर 1998-99 में 26.34 तक हो गया है। बिहार में इसी अवधि में यह 13.19 से बढ़कर 21.16 हो गया। परन्तु बिहार की शिक्षा उपलब्धियों में

यह बढ़ोत्तरी तदनु रूप परिलक्षित नहीं होती जिसका कारण योजनाव्यय का कम होना हो सकता है। दूसरी ओर, केरल के मामले में उच्चतम साक्षरता दर के लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद इस अनुपात में कमी हुई है।

3.67 अधिकतर राज्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यय अनुपात में गिरावट आई है। मेघालय के लिए सबसे अधिक गिरावट पंजीकृत की गई जहां दो समीक्षाधीन समय अवधियों के बीच यह अनुपात 15.34 से गिर कर 7.22 आ गया। हरियाणा तथा मध्य प्रदेश के मामले में भी इसमें महत्वपूर्ण कमी दिखाई है। 1998-99 में अधिकतम अनुपात तमिलनाडु के लिए 8.34 प्रतिशत था। अनेक राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत बजटीय सहायता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

तालिका 3.14
स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर योग के व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
(1998-99 में स्वास्थ्य व्यय अनुपात के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षा व्यय अनुपात		स्वास्थ्य व्यय अनुपात	
		1980-81	1998-99	1980-81	1998-99
1	आन्ध्र प्रदेश	14.35	12.98	7.63	8.45
2	तमिलनाडु	14.38	19.76	6.56	8.32
3	मेघालय	9.97	16.95	15.34	7.22
4	पश्चिम बंगाल	15.92	17.78	9.07	6.49
5	राजस्थान	13.07	19.53	10.21	6.42
6	हिमाचल प्रदेश	13.38	16.83	10.65	6.38
7	कर्नाटक	13.30	17.94	5.48	6.02
8	मध्य प्रदेश	10.82	16.36	7.59	5.80
9	केन्द्र सरकार	2.70	3.90	1.40	5.78
10	उड़ीसा	12.35	17.16	6.70	5.58
11	केरल	25.30	18.73	9.57	5.47
12	अरुणाचल प्रदेश	उ.न.	12.04	उ.न.	5.43
13	गुजरात	12.55	16.38	6.08	5.41
14	नागालैंड	8.03	9.55	9.57	5.39
15	जम्मू व कश्मीर	10.37	10.90	11.82	5.16
16	गोवा	उ.न.	14.47	उ.न.	5.11
17	मिज़ोरम	उ.न.	12.97	उ.न.	4.93
18	महाराष्ट्र	14.63	17.67	6.53	4.84
19	बिहार	13.19	21.16	5.49	4.81
20	पंजाब	16.99	15.76	6.52	4.73
21	त्रिपुरा	11.60	17.23	4.57	4.69
22	मणिपुर	12.25	18.52	8.66	4.67
23	असम	12.76	26.34	5.23	4.65
24	उत्तर प्रदेश	13.15	18.31	5.89	4.10
25	हरियाणा	12.06	14.50	6.51	3.84
26	सिक्किम	8.11	7.31	5.65	2.84

टिप्पणी : लोक व्यय अनुपात सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात के रूप में कुल लोक व्यय है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यय अनुपातों को कुल लोक व्यय के अनुपात के रूप में दर्शाया गया है।

उ.न. = उपलब्ध नहीं

स्रोत : राज्य वित्त - बजटों का एक अध्ययन, 2000-01, भा.रि.बै. तथा केन्द्रीय सरकार के लिए आंकड़ों के लिए केन्द्रीय बजट दस्तावेज।

3.68 यह तथ्य कि कुछ राज्य स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक भाग व्यय करते हैं, उन्हें सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में भी परिलक्षित किया जाना चाहिए। जो राज्य शिक्षा पर अधिक भाग व्यय कर रहे हैं उन्हें उच्च साक्षरता दरें प्राप्त करनी चाहिए तथा जो स्वास्थ्य पर अधिक मात्रा व्यय कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य संकेतक

बेहतर होने चाहिए। शिक्षा के लिए बिहार तथा असम के मामले में जिस सीमा तक यह परिणाम दिखाई नहीं देता है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुपातिक अधिक व्ययों का प्रभाव ऐसे व्ययों के प्रति व्यक्ति निर्पक्ष स्तरों तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं वास्तविक रूप से अनुवर्ती कारवाई पर भी निर्भर करता है।

तालिका 3.15
मानव विकास सूचकांक 1981, 1991 तथा 2001
(1991 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/ स.रा.क्षे	1981		1991		2001	
		मूल्य	रैंक	मूल्य	रैंक	मूल्य	रैंक
1	चण्डीगढ़	0.550	1	0.674	1	अ.न.	
2	दिल्ली	0.495	3	0.624	2	अ.न.	
3	केरल	0.500	2	0.591	3	0.638	1
4	गोवा	0.445	5	0.575	4	अ.न.	
5	अण्डमान व निकोबार	0.394	11	0.574	5	अ.न.	
6	पांडिचेरी	0.386	12	0.571	6	अ.न.	
7	मिज़ोरम	0.411	8	0.548	7	अ.न.	
8	दमन व दीव	0.438	6	0.544	8	अ.न.	
9	मणिपुर	0.461	4	0.536	9	अ.न.	
10	लक्षद्वीप	0.434	7	0.532	10	अ.न.	
11	नागालैंड	0.328	20	0.486	11	अ.न.	
12	पंजाब	0.411	9	0.475	12	0.537	2
13	हिमाचल प्रदेश	0.398	10	0.469	13	अ.न.	
14	तमिलनाडु	0.343	17	0.466	14	0.531	3
15	महाराष्ट्र	0.363	13	0.452	15	0.523	4
16	हरियाणा	0.360	15	0.443	16	0.509	5
17	गुजरात	0.360	14	0.431	17	0.479	6
18	सिक्किम	0.342	18	0.425	18	अ.न.	
19	कर्नाटक	0.346	16	0.412	19	0.478	7
20	पश्चिम बंगाल	0.305	22	0.404	20	0.472	8
21	जम्मू व कश्मीर	0.337	19	0.402	21	अ.न.	
22	त्रिपुरा	0.287	24	0.389	22	अ.न.	
23	आन्ध्र प्रदेश	0.298	23	0.377	23	0.416	10
24	मेघालय	0.317	21	0.365	24	अ.न.	
25	दादरा व नागर हवेली	0.276	25	0.361	25	अ.न.	
26	असम	0.272	26	0.348	26	0.386	14
27	राजस्थान	0.256	28	0.347	27	0.424	9
28	उड़ीसा	0.267	27	0.345	28	0.404	11
29	अरुणाचल प्रदेश	0.242	31	0.328	29	अ.न.	
30	मध्य प्रदेश	0.245	30	0.328	30	0.394	12
31	उत्तर प्रदेश	0.255	29	0.314	31	0.388	13
32	बिहार	0.237	32	0.308	32	0.367	15
	समस्त भारत	0.302		0.381		0.472	
	मानक विचलन	0.083		0.100			

टिप्पणी : अ.न. : इन राज्यों के लिए अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

स्रोत : मानव विकास रिपोर्ट 2001, योजना आयोग

मानव विकास सूचकांक

3.69 योजना आयोग द्वारा सबसे पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (रा.मा.वि.रि.) 2001 में निकाली गई जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1981 तथा 1991 के मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) के मूल्यों का अनुमान लगाया। तालिका 3.15 कुछ मुख्य राज्यों के निष्कर्षों को दर्शाती है।

3.70 यद्यपि 2001 के लिए मा.वि.सू. में सभी राज्यों का समावेश नहीं है। रा.मा.वि.रि. के अनुमान के अनुसार समूचे देश के लिए मा.वि.सू. 1981 में 0.302 से बढ़कर 0.472 तक पहुंच गया है। एक मध्य आय वाला राज्य होने के बावजूद केरल में 1981 में मा.वि.सू. 0.500 था जो 2001 में बढ़कर 0.638 हो गया और इस प्रकार से रा.मा.वि.रि. की तालिका में वह ऊपर है। पश्चिम बंगाल, जिसका सूचकांक 1981 में 0.305 था, 1991 में 0.404 तथा 2001 में बढ़कर 0.472 हो गया। उड़ीसा, 1981 में 0.267, 1991 में 0.345 तथा 2001 में 0.404 के सूचकांक के साथ सूची में सबसे नीचे है। बिहार में 2001 में 0.367 का न्यूनतम मूल्य अर्जित किया हालांकि वह पिछले वर्षों से बेहतर है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में, मिज़ोरम का मा.वि.सू. सबसे अधिक तथा अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है।

3.71 मा.वि.सू. के संदर्भ में जिन राज्यों ने अच्छा निष्पादन किया वे पंजाब (0.537), तमिलनाडु (0.531), तथा महाराष्ट्र (0.523) हैं। कर्नाटक का मा.वि.सू. जो कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति का केन्द्र है, को अभी लंबा सफर तय करना है जिसमें 2001 में सूचकांक 0.478 रहा।

3.72 जहां तक शहरी-ग्रामीण के बीच की खाई का संबंध है रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सूचकांक 0.263 से बढ़कर 0.340 हो गया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 0.442 से बढ़कर 0.511 हो गया। केरल के मामले में ग्रामीण-शहरी खाई सबसे कम तथा मध्य प्रदेश के मामले में सबसे अधिक थी। समूचा चित्र मिश्रित सा है क्योंकि विभिन्न राज्यों ने, मानव विकास पर सकेन्द्रण पर निर्भर करते हुए अलग-अलग निष्पादन किए हैं। दक्षिणी राज्यों ने सामान्यतः बेहतर निष्पादन किया है। महिलाओं के प्रति बर्ताव तथा उनकी स्थिति में अन्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शिशु मृत्यु में बेहतर निष्पादन का कारण हो सकता है। रा.मा.वि.रि. का लिंग विकास

सूचकांक भी भारत के दक्षिणी राज्यों के लिए निश्चित रूप से बेहतर है।

आधारभूत संरचना

3.73 आधारभूत संरचना को सामान्यतः सुविधाओं की भौतिक बनावट के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से लोगों को वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अर्थव्यवस्था से इसके संबंध बहुआयामी तथा जटिल हैं, क्योंकि यह उत्पादन तथा उपभोग को सीधे प्रभावित करता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के लिए उत्तरदायी होता है तथा इसमें बहुत व्यय होता है।

3.74 एक अच्छी आधारभूत संरचना उत्पादकता बढ़ाती है तथा उत्पादन लागतें कम करती हैं। परन्तु संवृद्धि को आत्मसात करने के लिए इसका तेजी से विस्तार होना आवश्यक है। आर्थिक संवृद्धि से आधारभूत संरचना की क्षमता बढ़ती है। जैसे-जैसे देशों का विकास हो वैसे-वैसे आधारभूत संरचना का भाग बदलना चाहिए। आधारभूत संरचना इस बात का भी निर्धारण करती है कि संवृद्धि का गरीबी दूर करने पर कितना प्रभाव पड़ा है।

3.75 इस खंड में हम विद्युत, सड़कें, रेल, संचार, डाक तथा बैंकिंग के आधारिक संरचना के साथ राज्य-वार तुलनाओं का अवलोकन करेंगे। ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा तैयार किए गए आधारिक संरचना संबंधी सूचकांक पर भी विचार किया जाएगा।

विद्युत

3.76 सस्ती, पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित विद्युत की उपलब्धता विकास की एक आवश्यक शर्त है। जहां उत्पादन क्षमता प्रत्यक्ष रूप से विद्युत उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और परिणामतः उपलब्धता पर भी देश के राज्यों में विद्युत उपलब्धता हमेशा एक अच्छा संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि किसी विशेष राज्य में उत्पादित को नेशनल पावर ग्रिड के माध्यम से बांटना संभव है। विद्युत उपलब्धता का एक अधिक विश्वसनीय संकेतक विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग है (तालिका 3.16)।

तालिका 3.16
बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग (किलोवाट में)
(अखिल भारत को छोड़कर वर्ष 1999-2000 के रैंक क्रम में व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	1974-75	1980-81	1989-90	1996-97	1999-2000
1	अरुणाचल प्रदेश	3.4	14.6	56.6	81.0	68.6
2	मणिपुर	7.7	7.9	79.5	128.0	69.5
3	नागालैंड	27.2	34.2	58.6	88.0	84.7
4	असम	24.0	33.5	92.7	104.0	95.5
5	त्रिपुरा	6.0	14.5	45.0	80.0	95.5
6	मिज़ोरम	4.3	5.6	65.0	128.0	120.7
7	बिहार	48.0	74.1	109.0	138.0	140.8
8	मेघालय	31.3	31.0	106.4	135.0	160.3
9	उत्तर प्रदेश	50.0	83.1	157.4	197.0	175.8
10	पश्चिम बंगाल	106.1	117.0	136.2	194.0	204.4
11	लक्षद्वीप	11.2	26.8	143.6	234.0	217.9
12	अण्डमान व निकोबार	27.2	42.3	109.7	210.0	222.4
13	केरल	79.4	112.0	171.0	241.0	261.8
14	जम्मू व कश्मीर	52.7	74.8	176.4	218.0	267.9
15	राजस्थान	55.9	99.4	191.6	301.0	334.5
16	हिमाचल प्रदेश	58.8	66.4	191.9	306.0	339.1
17	मध्य प्रदेश	61.3	100.3	217.4	367.0	351.7
18	उड़ीसा	69.2	114.0	249.2	309.0	354.6
19	कर्नाटक	119.3	146.0	272.8	340.0	380.1
20	आन्ध्र प्रदेश	55.4	101.8	233.5	346.0	391.0
21	तमिलनाडु	126.4	186.0	295.0	468.0	484.1
22	महाराष्ट्र	172.6	244.5	393.6	556.0	520.5
23	हरियाणा	115.1	209.5	367.4	504.0	530.8
24	दिल्ली	299.2	403.8	673.6	577.0	653.2
25	गोवा	157.5	250.8	411.2	724.0	712.5
26	चण्डीगढ़	363.7	309.0	686.2	795.0	823.8
27	गुजरात	165.0	238.8	436.8	694.0	834.7
28	पंजाब	154.2	303.6	620.5	792.0	921.1
29	पांडिचेरी	214.4	263.7	592.4	867.0	931.9
30	दादरा व नागर हवेली	14.8	56.3	878.8	2379.0	3882.8
31	दमन व दीव	130.8	276.4	440.1	2335.0	3927.4
	अखिल भारत	174.9	120.5	236.0	334.0	354.75
	मानक विचलन	86.60	108	219	553	920

स्रोत : क) 1974-75, 1980-81, 1989-90 : सांख्यिकीय उद्धरण, भारत के.सं.सं प्रकाशन विभिन्न मामले।
ख) 1996-97, 1999-2000 : राज्य बिजली बोर्ड तथा बिजली विभागों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट (2000-02), योजना आयोग।

3.77 तालिका से यह देखा जा सकता है कि लगभग तीन दशक पहले, 1974-75 में, सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रति व्यक्ति उपभोग आंकड़ें राष्ट्रीय स्तर से नीचे थे। चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत का उपभोग क्रमशः (363.7 कि.वा.ह.) (299.2 कि.वा.ह.) तथा (214.4 कि.वा.ह.) के साथ सबसे अधिक था। राज्यों में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक प्रति व्यक्ति उपभोग 172.6 कि.वा.ह. रिकार्ड किया। पंजाब ने औसतन 154.2 कि.वा.ह. उपभोग किया। राज्य जिन्होंने सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग किया है वह है मिज़ोरम (4.3 कि.वा.ह.) तथा अरुणाचल प्रदेश (3.4 कि.वा.ह.)।

3.78 1999-2000 तक पूरे देश के लिए प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 354.75 कि.वा.ह. तक बढ़ गया। दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव के संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रति व्यक्ति उच्चतम उपभोग 3800 कि.वा.ह. किया जो उनसे नीचे सबसे उच्च उपभोग वाले क्षेत्रों से चार गुना से अधिक है। गुजरात तथा गोवा 1999-2000 में प्रति व्यक्ति उच्चतम उपभोग करने वाले राज्य थे। हालांकि मिज़ोरम जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में महत्वपूर्ण संवृद्धि हुई। उत्तर-पूर्वी राज्यों में देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग रहा। बड़े राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल का प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर सबसे कम था।

3.79 विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग अंतर-राज्यीय अंतर बढ़ते रहे हैं। (आफ़ति 3.8 देखें)। निरपेक्षतर शर्तों में मानक विचलन के अनुसार मापी गई राज्य अन्तर राज्यीय विभिन्नताएं 1974-

75 में केवल 87 थी तथा वर्ष 1996-97 तक संतुलित बढ़ते हुए 549 के स्तर पर पहुंच गई है।

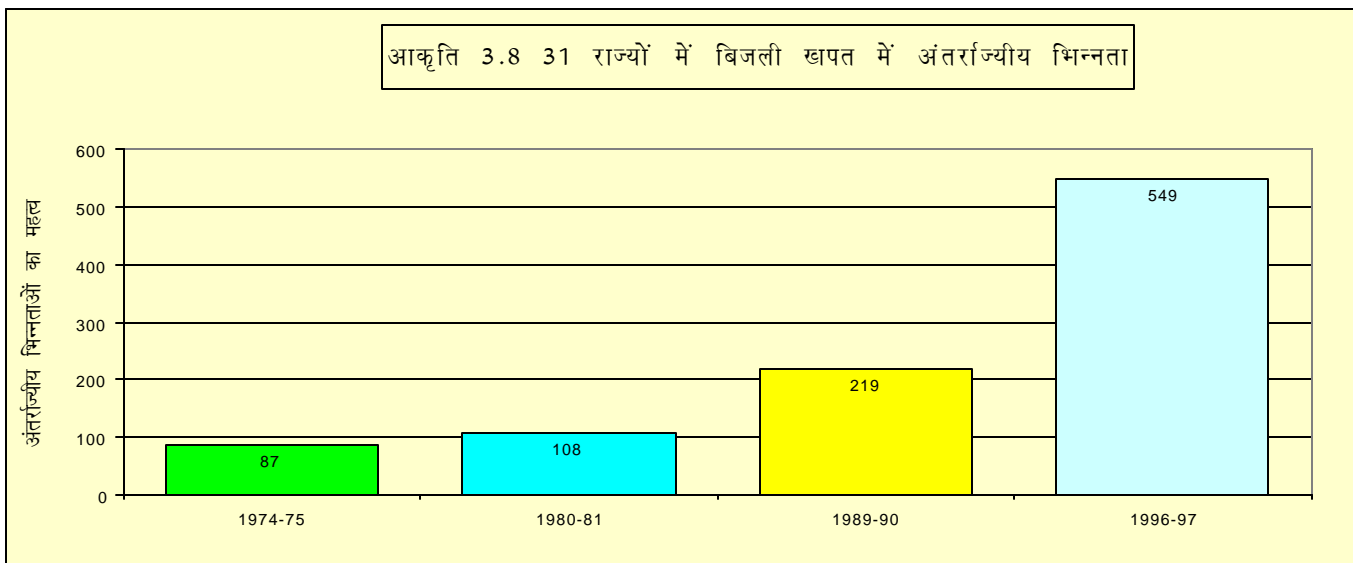
सड़कें

3.80 पिछले दशकों में भारत में सड़क यातायात माल ढुलाई तथा यात्री गमनागमन के मुख्य साधन के रूप में उभर कर आया है। पहाड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर रेलों की सुविधा नहीं है, यातायात का यह मुख्य यांत्रिक साधन है।

3.81 पिछले वर्षों माल तथा यात्रियों के गमनागमन में सड़कों के योगदान में काफी वृद्धि हुई है। 1950-51 में सड़कें केवल 12 प्रतिशत माल की ढुलाई तथा 26 प्रतिशत यात्री गमनागमन करती थी। 1991-92 तक यह 53 प्रतिशत माल की ढुलाई तथा 80 प्रतिशत यात्री गमनागमन करती हैं। सड़कों का नेटवर्क, 1951 में चार लाख कि.मी. से 1991 में 24 लाख कि.मी. तक सात गुना बढ़ा है।

सड़क घनत्व

3.82 सड़क घनत्व का एक मानक संकेतक प्रति हजार वर्ग किलोमीटरों में सड़क की लम्बाई है। उन्नीस सौ सत्तर के दशक में, जम्मू व कश्मीर में सबसे कम सड़क घनत्व 40 कि.मी. था। इसके बाद, मिज़ोरम में सड़क घनत्व 43 कि.मी. था। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश में यह क्रमशः 82 कि.मी. तथा 125 कि.मी. था। राज्यों में केरल का उच्चतम घनत्व 3106 कि.मी. था, इसके बाद गोवा 1581 कि.मी. पर था (तालिका 3.17)।



तालिका 3.17
कि.मी. में राज्य-वार सड़क घनत्व
(सड़क लम्बाई क्षेत्र के प्रति '000 वर्ग कि.मी.)
(1996-97 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	1971-72	1981-82	1991-92	1996-97
1	दिल्ली	7984	10527	14256	17924
2	पांडिचेरी	3508*	4286	6698	4859
3	केरल	3106	2751	3567	3749
4	गोवा	1581*	2141	2005	2245
5	उड़ीसा	366	772	1260	1687
6	तमिलनाडु	714	1020	1523	1588
7	चण्डीगढ़	710*	1250	14000	15377
8	त्रिपुरा	386	759	1341	1405
9	पंजाब	594	916	1078	1278
10	महाराष्ट्र	316	586	730	1176
11	नागालैंड	284	379	901	1107
12	दादरा व नागर हवेली	460*	492	643	1086
13	असम	383	760	836	872
14	उत्तर प्रदेश	382	520	692	868
15	पश्चिम बंगाल	599	642	700	850
16	कर्नाटक	525*	557	701	751
17	भारत	344	466	615	749
18	आन्ध्र प्रदेश	264	468	553	647
19	हरियाणा	307	542	601	637
20	हिमाचल प्रदेश	215	369	459	542
21	बिहार	670	481	492	508
22	मणिपुर	392	239	314	490
23	गुजरात	221	375	419	464
24	मध्य प्रदेश	162	242	321	451
25	मेघालय	303	233	291	378
26	राजस्थान	146	212	363	379
27	सिक्किम	329*	156	227	258
28	मिज़ोरम	43*	119	179	229
29	अरुणाचल प्रदेश	125*	152	131	168
30	अण्डमान व निकोबार	82*	83	110	160
31	जम्मू व कश्मीर	40	53	56	97
32	दमन व दीव	उ.न.	उ.न.	उ.न.	26
33	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	उ.न.	31

टिप्पणी : * 1975-76 के आंकड़ों को देखें।

उ.न. (उपलब्ध नहीं)

स्रोत : मूल सड़क सांख्यिकीय भूतल परिवहन मंत्रालय - विभिन्न मामलों।

3.83 1996-97 के दौरान, राज्यों में केरल का उच्चतम घनत्व 3749 प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र था, गोवा का 2245 कि.मी. तथा उड़ीसा का भी उच्च सड़क घनत्व 1682 कि.मी. था। 1997 में जम्मू व कश्मीर राज्य का सड़क घनत्व सबसे कम था, जिसका घनत्व 96 कि.मी. प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र था तथा इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 168 कि.मी. पर था। इस अवधि में जबकि पूरे देश में सड़क घनत्व दुगना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश जिसमें सड़क यातायात की सुविधा की उपलब्धता सबसे कम है उसमें घनत्व केवल 34 प्रतिशत तक ही बढ़ पाया।

3.84 पहाड़ी राज्यों में रेल की लाइनों का नेटवर्क नगण्य है तथा सड़कें यातायात का मुख्य साधन है। तथापि इन राज्यों में सड़क घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 168 कि.मी. मिज़ोरम का 229 तथा सिक्किम का घनत्व 258 कि.मी. प्रति 1000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है।

रेलवे

3.85 भारत में परंपरागत रूप से रेल यातायात का मुख्य साधन रही है और यद्यपि अब यह भूतल परिवहन यातायात का बहुत बड़ा भाग नहीं ढोती है, फिर भी अब भी यह देश के यातायात की रीढ़ की हड्डी है। रेल नेटवर्क का लगभग 85 प्रतिशत भाग अंग्रेजों से विरासत में प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद, रेल का नेटवर्क बड़ी धीमी गति से बढ़ा है। 1950-51 में कुल मार्ग लम्बाई 53,596 कि.मी. से बढ़कर 1996-97 में 62,725 कि.मी. हो गई। 1950 के दशक तथा 1960 के दशक में रेल नेटवर्क में बढ़ोत्तरी की दर 0.5-0.6 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जो बहुत कम थी। सत्तर तथा अस्सी के दशकों में यह दर और भी घटकर 0.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। 1980-81 तथा 1996-97 के बीच नेटवर्क में कुल संवृद्धि केवल 2.5 प्रतिशत रही।

3.86 रेल घनत्व एक अमुक राज्य में इस महत्वपूर्ण आधारीक संरचना की उपलब्धता का संकेतक है जिसे मार्ग लम्बाई के प्रति हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र के अनुसार आंका जाता है। 2000-01 में, राज्यों में पंजाब 41.73 कि.मी. उच्चतम रेल घनत्व पर था, पश्चिम बंगाल 4.26 कि.मी. पर लगभग बराबर था, बिहार 36.55 कि.मी. तथा उत्तर प्रदेश भी 35.93 कि.मी. के घनत्व के साथ रेल से अच्छी प्रकार से जुड़ा है। दक्षिण में, तमिलनाडु में 32.21 कि.मी. सहित उच्चतम रेल घनत्व था, इसके बाद केरल में रेल घनत्व 27.02 कि.मी. था। उत्तर-पूर्व में, असम के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में, रेल लाइनों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। मुख्य राज्यों में रेल लाइनों द्वारा जुड़ा (32.08), मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में रेल मार्गों का घनत्व सबसे कम है (तालिका 3.18 तथा आपति 3.10)।

तालिका 3.18

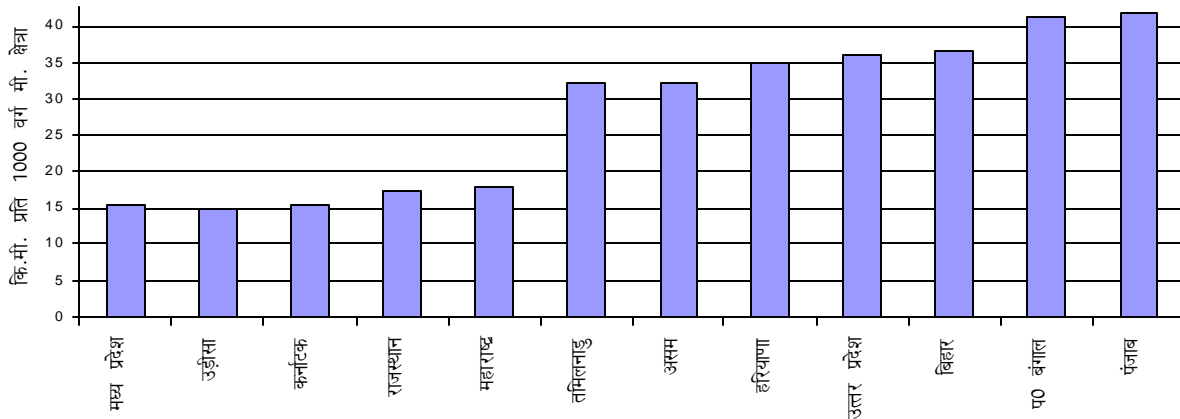
31.3.2001 के अनुसार राज्य-वार मार्ग कि.मी. प्रति लाख जनसंख्या एवं मार्ग कि.मी. प्रति 1000 वर्ग कि.मी.

क्र.सं.	राज्य	मार्ग कि.मी. प्रति 1000 जनसंख्या के	
		प्रति लाख	कि.मी.
0	1	2	3
1	दिल्ली	1.45	134.63
2	चण्डीगढ़	0.86	67.89
3	पंजाब	8.65	41.73
4	पश्चिम बंगाल	4.56	41.26
5	बिहार	4.15	36.55
6	उत्तर प्रदेश	5.16	35.93
7	हरियाणा	7.34	35.00
8	तमिलनाडु	6.74	32.21
9	असम	9.45	32.08
10	गुजरात	10.50	27.10
11	केरल	3.30	27.02
12	पांडिचेरी	1.14	22.56
13	झारखंड	6.68	22.54
14	गोवा	5.16	18.72
15	आन्ध्र प्रदेश	6.78	18.67
16	महाराष्ट्र	5.64	17.74
17	राजस्थान	10.49	17.32
18	मध्य प्रदेश	7.93	15.52
19	कर्नाटक	5.64	15.51
20	उड़ीसा	6.29	14.83
21	छत्तीसगढ़	5.68	8.73
22	उत्तरांचल	4.20	6.37
23	हिमाचल प्रदेश	4.42	4.83
24	त्रिपुरा	1.40	4.26
25	नागालैंड	0.65	0.78
26	जम्मू व कश्मीर	0.95	0.43
27	मिज़ोरम	0.17	0.07
28	मणिपुर	0.06	0.06
29	अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.02
30	मेघालय	0	0
31	सिक्किम	0	0
32	अण्डमान व निकोबार	0	0
33	दादरा व नागर हवेली	0	0
34	दमन व दीव	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0
कुल		135.56	700.36

स्रोत : आंकड़ा पुस्तक 2002-03, रेलवे बजट, 26 फरवरी, 2002

आफति 3.10

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार चुनिंदा तुलात्मक राज्यों के रेल घनत्व



दूर संचार

3.87 दूर संचार आधारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति के चलते ओर सूचना प्रौद्योगिकी की काफी संवृद्धि के कारण तथा अर्थव्यवस्था पर इसके काफी प्रभाव के कारण इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

3.88 राज्यों में नेटवर्क के विस्तारण को मापने के लिए, हम दूरभाष लाइनों तथा दूरभाष घनत्व में बढ़ोत्तरी के रूप में दूरभाष नेटवर्क के फैलाव पर नजर डालते हैं। दूरभाष घनत्व का तात्पर्य प्रति सौ व्यक्तियों के पास दूरभाषों की संख्या से है। दूरभाष घनत्व केवल नेटवर्क की संवृद्धि का कार्य ही नहीं है परन्तु यह मांग में बढ़ोत्तरी पर भी निर्भर है, जो समग्र आर्थिक विकास पर निर्भर करती है।

3.89 नब्बे के दशक ने दूरसंचार नेटवर्क की अभूतपूर्व संवृद्धि

देखी है। नौवीं योजना के दौरान संवृद्धि अपेक्षाकृत तीव्र थी।

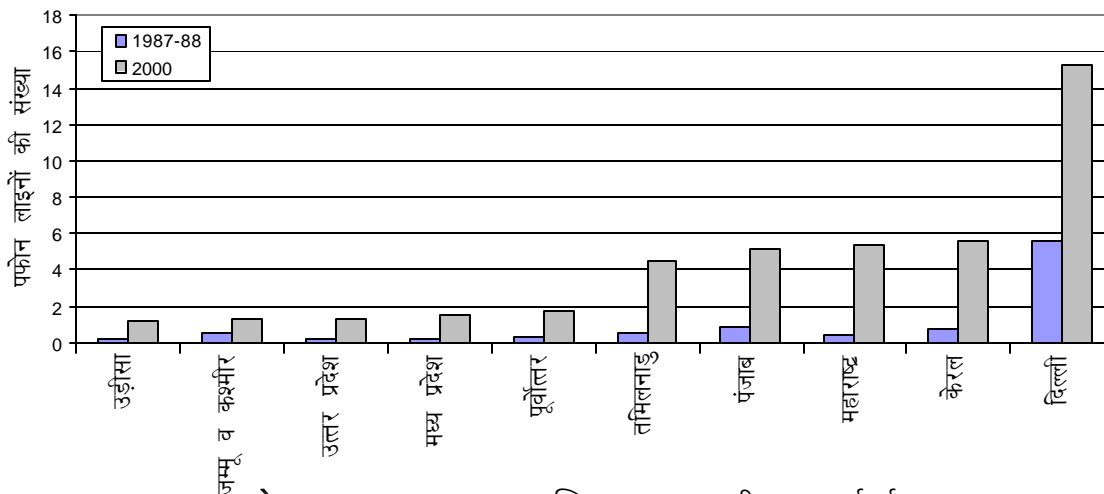
3.90 देश में 1987-88 में केवल 0.59 तथा 1991-92 में 0.78 प्रति 100 व्यक्ति दूरभाष लाइनों की तुलना में 1999-00 के दौरान 2.85 दूरभाष लाइनें थीं। तथापि, अन्य विकासशील देशों की तुलना में जहां यह लगभग 5-6 है, यह अनुपात अभी भी कम है, जबकि विश्व का औसत प्रति 100 व्यक्ति 11 दूरभाष है (तालिका 3.19)।

3.91 राज्यों में 1987-88 में, पश्चिम बंगाल का दूरभाष घनत्व 0.10 में सबसे कम था, इसके बाद बिहार 0.12 पर था। गुजरात में उच्चतम घनत्व 1.04 पर था, इसके बाद पंजाब 0.88 पर था।

3.92 2000 तक केरल में उच्चतम दूरभाष घनत्व 5.55 पर था, इसके बाद महाराष्ट्र 5.33 पर था (आफति 3.11 देखें)।

आफति 3.11

1987-88 की तुलना में वर्ष 2000 में शीर्ष पांच व निचले पांच राज्यों की टेली डेंसिटी टेलिफोन लाइनों संख्या प्रति 100 व्यक्ति



स्रोत : इन्फास्ट्रक्चर इन इण्डिया, 1996, सी एम आई ई।

तालिका 3.19
1987-88, 1991-92 तथा 2000 में राज्यवार टेली-घनत्व (प्रति 100 व्यक्ति)
(2000 में रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1991-92	2000
1	दिल्ली	5.56	7.69	15.27
2	केरल	0.78	1.16	5.55
3	महाराष्ट्र	0.45	0.63	5.33
4	पंजाब	0.88	1.23	5.18
5	तमिलनाडु	0.50	0.60	4.52
6	हिमाचल प्रदेश	0.55	0.85	4.32
7	गुजरात	1.04	1.32	4.22
8	कर्नाटक	0.69	0.93	3.74
9	हरियाणा	0.51	0.82	3.35
10	आन्ध्र प्रदेश	0.50	0.64	3.12
11	अखिल भारत	0.59	0.78	2.85
12	राजस्थान	0.37	0.49	2.11
13	पश्चिम बंगाल	0.10	0.11	2.06
14	उत्तर-पूर्वी राज्य	0.32	0.45	1.69
15	मध्य प्रदेश	0.23	0.45	1.54
16	उत्तर प्रदेश	0.22	0.28	1.33
17	जम्मू व कश्मीर	0.46	0.50	1.31
18	उड़ीसा	0.19	0.28	1.21
19	असम	0.18	0.24	1.06
20	बिहार	0.12	0.16	0.65
21	कलकत्ता	2.78	3.33	
22	चेन्नई	3.33	4.35	
23	मुम्बई	7.69	10.00	

टिप्पणी : खाली में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत : इन्फास्ट्रक्चर इन इण्डिया, 1996, सी एम आई ई तथा दूरसंचार विभाग के लिए 1999-2000

अन्य उच्च दूरभाष घनत्व वाले राज्य तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात थे, घनत्व क्रमशः 4.52 4.32 तथा 4.22 था। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए दूरभाष घनत्व अपेक्षाकृत कम 1.69 पर जारी रहा। पश्चिम बंगाल ने इन तीन योजना अवधियों में इसमें महत्वपूर्ण रिकार्ड किया जिससे दूरभाष घनत्व बढ़कर 2.06 तक पहुंच गया। लेकिन 2000 में बिहार का 0.65 दूरभाष घनत्व सबसे कम था। जम्मू व कश्मीर ने इस अवधि में सबसे कम 2.8 की संवृद्धि दर रिकार्ड की।

3.93 महानगरों में, 1996 में मुंबई तथा दिल्ली में प्रति 100 व्यक्तियों के लिए क्रमशः 13.26 तथा 10.29 दूरभाष थे, चैन्नई तथा कोलकाता में घनत्व क्रमशः 8.4 तथा 8.8 था।

डाक सेवा

3.94 भारतीय डाक प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी डाक प्रणाली है जिसमें 1.53 लाख डाकघर हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार की डाक सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, भारतीय डाक प्रणाली संसाधन जुटाने के प्रयासों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन कार्यों के महत्व को 31 मार्च, 1996 के अनुसार डाकघर बचत बैंकों (डा.घ.ब.बैं.) 160.5 मिलियन खातों में 91,795 करोड़ रु. तक जमा से आंका जा सकता है।

3.95 तथापि 1960 से, डाकघरों के विस्तार में धीरे-धीरे कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक डाकघर द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। 1980 के दशक के आरम्भ में ग्रामीण क्षेत्र के एक डाकघर द्वारा 25.9 कि.मी. के क्षेत्र में सेवा प्रदान की जाती थी, जबकि शहरी डाकघर 3.8 कि.मी. क्षेत्र में सेवा देते थे। 1994-95 तक शहरी डाकघर के 3.2 कि.मी. क्षेत्र को कवर करने की तुलना में ग्रामीण डाकघर 23.8 कि.मी. का क्षेत्र कवर करता था।

राज्यों में डाकघरों का विस्तारण

3.96 राज्यों में डाकघरों के विस्तारण का जायज़ा लेने के लिए हम उनके विस्तारण के दो संकेतकों पर नजर

डालते हैं : जनसंख्या तथा एक डाकघर के अन्तर्गत क्षेत्र। एक डाकघर के अन्तर्गत जनसंख्या इन डाकघर की शाखाओं पर काम के दबाव को परिलक्षित करती है। एक डाकघर के अन्तर्गत क्षेत्र एक डाकघर की एक क्षेत्र में पहुंच को दर्शाता है। यदि डाक नेटवर्क की संवृद्धि तेज है तो इन दो संकेतकों में कमी आनी चाहिए तथापि जैसे-जैसे अधिक डाकघर खुलेंगे एक डाकघर के अन्तर्गत क्षेत्र कम होगा परन्तु एक डाकघर के अन्तर्गत जनसंख्या की संवृद्धि भी एक कार्य है। प्रत्येक राज्य में इसमें केवल तभी कमी आएगी, यदि डाकघरों की संवृद्धि जनसंख्या की संवृद्धि से अधिक हो।

एक डाकघर के अन्तर्गत जनसंख्या

3.97 1970 के दशक के बाद डाकघरों की संवृद्धि में बहुत धीमापन आया है। लगभग सभी राज्यों में प्रति डाकघर के संदर्भ में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यद्यपि तथ्य का परिणाम था कि डाकघरों की संवृद्धि जनसंख्या की संवृद्धि के तदनु रूप नहीं बढ़ पाई। (तालिका 3.20)

3.98 1993-94 तक एक डाकघर द्वारा सेवा की जा रही जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई। समूचे भारत के लिए आंकड़ें 5,740 तक बढ़ गए। दो अवधियों के बीच राज्यों से संबंधित स्थिति में भी अधिक परिवर्तन नहीं आया। पश्चिम बंगाल में एक डाकघर द्वारा सेवा किए जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक 8,301 थी। इसके बाद बिहार में आंकड़ा 7,658 पर था तथा उत्तर प्रदेश में यह 7,232 पर था। कम से कम आंकड़ा सिक्किम के लिए था जहां प्रति डाकघर जनसंख्या 1,880 थी। इस बारे में नोट करने योग्य रोचक बात यह थी कि कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों ने इस संख्या में बढ़ोत्तरी की सामान्य प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रति डाकघर जनसंख्या में कमी दर्ज की जिससे इस क्षेत्र में सेवाओं के कवरेज में पर्याप्त सुधार का संकेत मिला। मिज़ोरम में प्रति डाकघर जनसंख्या 1980-81 में 1,968 से 1990-2000 में घटकर 1,724, सिक्किम के लिए 2,655 से 1989, अरुणाचल प्रदेश के लिए 3,292 से 2,856 तथा मणिपुर में 2,924 से 2,648 हो गई।

तालिका 3.20
एक डाकघर के अन्तर्गत जनसंख्या - 1980-81, 1990-91 तथा 1999-2000
(1999-2000 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति/डाकघर		
		1980-81	1990-91	1999-2000 (1991 जनगणना)
1	दिल्ली	11350	17380	16295
2	चण्डीगढ़	11300	12588	12818
3	पांडिचेरी	6163	8245	8526
4	बिहार	6798	7657	7216
5	पश्चिम बंगाल	7055	8132	6871
6	उत्तर प्रदेश	6383	7250	6871
7	महाराष्ट्र	5601	6611	6315
8	हरियाणा	5459	6470	6158
9	मध्य प्रदेश	5253	6083	5812
10	केरल	5563	5932	5751
11	असम	5792	5925	5698
12	दमन व दीव	4939	6313	5643
13	अखिल भारत	4908	5675	5462
14	पंजाब	4527	5343	5356
15	लक्ष्यद्वीप	4000	7429	5173
16	जम्मू व कश्मीर	4471	4967	4651
17	गुजरात	4072	4737	4609
18	तमिलनाडु	4158	4645	4608
19	कर्नाटक	3977	4637	4538
20	गोवा	4289	4912	4534
21	राजस्थान	3668	4446	4222
22	आन्ध्र प्रदेश	3341	4080	4097
23	उड़ीसा	3652	4040	3873
24	त्रिपुरा	3416	4122	3847
25	नागालैंड	3638	4537	3788
26	मेघालय	3196	3862	3613
27	दादरा व नागर हवेली	3714	3067	2961
28	अरुणाचल प्रदेश	3292	3378	2856
29	अण्डमान व निकोबार द्वीप	2423	2897	2856
30	मणिपुर	2924	3030	2648
31	सिक्किम	2655	2606	1989
32	हिमाचल प्रदेश	1834	1984	1847
33	मिज़ोरम	1968	2030	1724

स्रोत : डाक विभाग

3.99 यद्यपि पहाड़ी क्षेत्रों में एक डाकघर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की उसके बराबर क्षेत्रों के साथ तुलना तुरंत नहीं की जा सकती, परन्तु क्षेत्र डाकघर घनत्व का एक अच्छा संकेतक है। 1980-81 तथा 1999-2000 के बीच सभी राज्यों के लिए प्रति डाकघर गिरावट दर्ज की है। अरुणाचल प्रदेश में सेवा किया जाने वाला सबसे अधिक

क्षेत्र था, इसके बाद जम्मू व कश्मीर तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह है। 2000 में देश में सबसे अच्छा डाक घनत्व चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में था तथा राज्यों में केरल 7.72 कि.मी. पर था। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल भी अच्छी सेवा राज्यों में थे। (तालिका 3.21)

तालिका 3.21
एक डाकघर के अन्तर्गत क्षेत्र - 1980-81, 1990-91 तथा 1999-2000
(1999-2000 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ग कि.मी./डाकघर		
		1980-81	1990-91	1999-2000
1	अरुणाचल प्रदेश	435.2	329.69	278.07
2	जम्मू व कश्मीर		143.01	133.85
3	अण्डमान व निकोबार द्वीप			83.67
4	मिज़ोरम	84.01	62.37	52.74
5	नागालैंड	77.59	61.86	51.24
6	मेघालय	53.80	49.16	45.99
7	मध्य प्रदेश	44.57	40.78	38.98
8	सिक्किम	61.33	45.78	34.46
9	राजस्थान	36.85	34.67	32.92
10	मणिपुर	46.00	36.90	32.27
11	महाराष्ट्र	27.45	25.84	24.67
12	गुजरात	23.41	22.55	21.88
13	अखिल भारत	23.62	22.10	21.26
14	हिमाचल प्रदेश	23.85	12.61	20.12
15	असम	31.97	20.84	20.04
16	कर्नाटक	20.53	19.84	19.45
17	उड़ीसा	21.57	19.96	19.17
18	आन्ध्र प्रदेश	17.27	16.92	16.98
19	हरियाणा	18.68	17.53	16.67
20	त्रिपुरा	17.43	15.74	14.60
21	उत्तर प्रदेश	16.95	15.38	14.55
22	बिहार	16.9	15.42	14.53
23	गोवा	16.17	14.46	14.35
24	दादरा व नागर हवेली			14.02
25	पंजाब	13.57	13.32	12.95
26	तमिलनाडु	11.17	10.85	10.76
27	पश्चिम बंगाल	11.35	10.61	10.24
28	केरल	8.49	7.94	7.71
29	दमन व दीव			6.22
30	पांडिचेरी			5.26
31	लक्षद्वीप			3.20
32	दिल्ली			2.43
33	चण्डीगढ़			2.28

स्रोत: डाक विभाग

बैंकिंग

3.100 भारत में बैंकिंग सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण रहा है विशेष रूप से 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों में से अधिकतर लोक क्षेत्र है, ने वित्तीय मध्यवर्ती प्रक्रिया में प्रमुखता प्राप्त की है। इन बैंकों ने भौगोलिक कवरेज विस्तार बचत को संचालित करने तथा विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश में पर्याप्त लम्बे कदम उठाए हैं।

उधार-जमा अनुपात

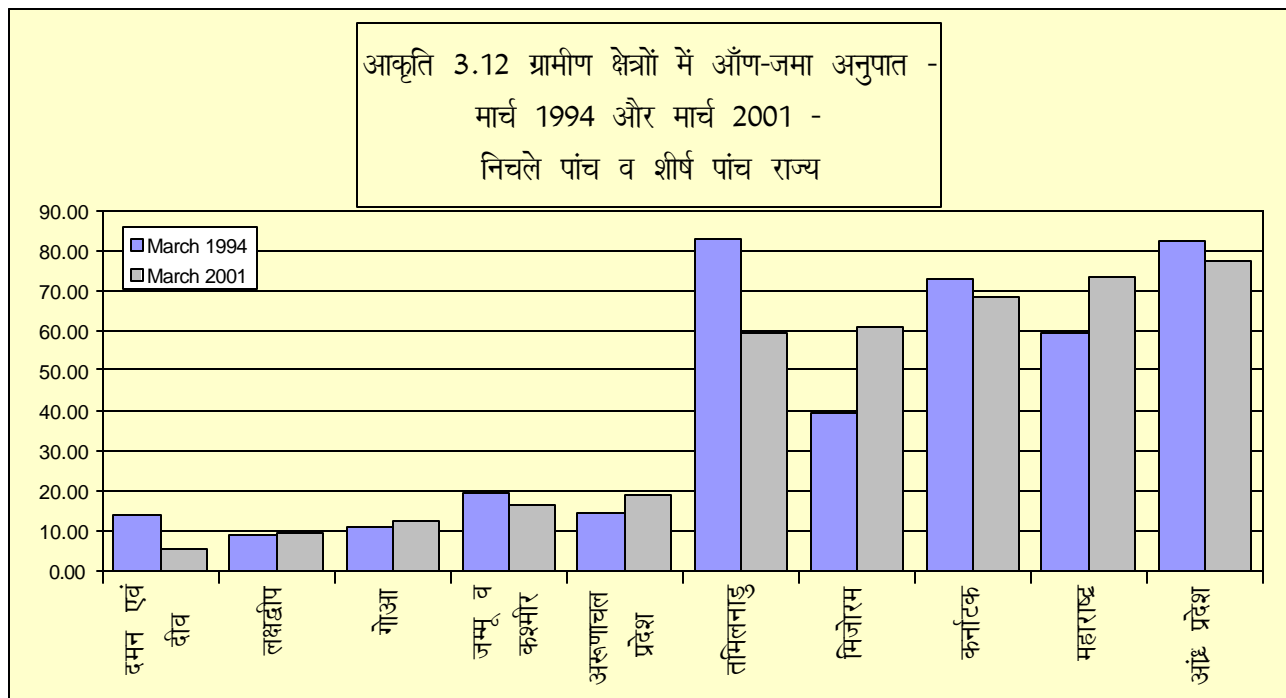
3.101 उधार-जमा अनुपात, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तारण, उधार अवसरों, देश के राज्यों में होने वाले विकास की प्रवृत्ति तथा रफ्तार को दर्शाती है।

3.102 पूर्वी-क्षेत्र में बैंक शाखाओं में उधार-जमा (उ.-ज.) अनुपात मार्च 1993 में 50 प्रतिशत से अधिक थी जो मार्च 2001 में गिरकर 37 प्रतिशत तक हो गई। बिहार में, मार्च 1994 में 35.24 अनुपात से घटकर मार्च 2001 में 21.3 तक आ गया। इसी अवधि में, उड़ीसा में यह 60.08 से घटकर 41.5 पर आ गया। केन्द्रीय क्षेत्र में उ.ज. अनुपात 42 प्रतिशत

से गिरकर 33 प्रतिशत तक तथा इसी अवधि में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह 39 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक आ गया। उत्तर प्रदेश में 37.22 से घटकर 28.8 प्रतिशत तक तथा मध्य प्रदेश में 54.9 से 28.8 तक आ गया। मुख्यता अनुपात दक्षिणी राज्यों में बढ़ा। इसी अवधि में उ.ज. अनुपात महाराष्ट्र में 56.36 से बढ़कर 85.4 तक तथा तमिलनाडु में 82.45 से बढ़कर 90.6 तक आ गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में उधार-जमा अनुपात

3.103 अविकसित क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की शाखाओं के उ.-ज. अनुपात में समस्त भारत के स्तरों पर धीरे-धीरे गिरावट आई है। जबकि समस्त भारत ग्रामीण उ.ज. अनुपात में लगभग 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक गिरावट आई है, इसके समान रूप अनुपातों ने केन्द्रीय, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 50-55 प्रतिशत से 26-33 प्रतिशत गिरावट आई है। (आफति 3.12) टिप्पणी का विषय है कि बैंक उधार की संवृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक जमाओं की संवृद्धि असाधारण रूप से तेज है। इन राज्यों में कम उ.ज. सामान्यता उधार देने के लिए या तो बैंक के नियमों में अपर्याप्त अवसरों के कारण या सुरक्षित उधार के लिए असंतोषजनक वातावरण है।



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

आधारिक संरचना संबंधी सूचकांक

3.104 तालिका 3.22 ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1999 के लिए तैयार किए गए आधारिक संरचना संबंधी सूचकांक को दर्शाती है। यह सूचकांक राज्यों में भौतिक, सामाजिक तथा संस्थागत ढांचे की उपलब्धता की समग्र तुलनात्मक रूपरेखा बताती है।

तालिका 3.22
सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा, 1999 का सूचकांक
(घटत क्रम में व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य	सूचकांक
1	अरुणाचल प्रदेश	69.71
2	जम्मू व कश्मीर	71.46
3	त्रिपुरा	74.87
4	मणिपुर	75.39
5	मेघालय	75.49
6	राजस्थान	75.86
7	नागालैंड	76.14
8	मध्य प्रदेश	76.79
9	असम	77.72
10	उड़ीसा	81.00
11	बिहार	81.33
12	मिज़ोरम	82.13
13	हिमाचल प्रदेश	95.03
14	उत्तर प्रदेश	101.23
15	आन्ध्र प्रदेश	103.30
16	कर्नाटक	104.88
17	सिक्किम	108.99
18	पश्चिम बंगाल	111.25
19	महाराष्ट्र	112.80
20	गुजरात	124.31
21	हरियाणा	137.54
22	तमिलनाडु	149.10
23	केरल	178.68
24	पंजाब	187.57
25	गोवा	200.57

स्रोत : ग्यारवीं वित्त आयोग रिपोर्ट, 2000

3.105 तालिका से देखा जा सकता है कि 1999 में वर्तमान सभी राज्यों में से गोवा का ढांचे के लिए सूचकांक सबसे ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि ढांचा सुविधाओं के अनुसार गोवा सबसे अच्छा स्थित राज्य है। उच्च ढांचा सूचकांक के साथ अन्य राज्य केरल, पंजाब, गुजरात तथा हरियाणा है। अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में से अधिकतर की तरह अरुणाचल प्रदेश का भी सबसे कम सूचकांक है। अन्य राज्यों के बीच राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ढांचा निधि में 1999 में सबसे कमजोर थे। राज्यों की ढांचागत निधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे निजी क्षेत्र निवेश निर्णयों तथा बाद में राज्यों को पूंजीगत प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।

पूंजीगत प्रवाह

3.106 पहली योजनाओं में, पूंजीगत प्रवाह, चाहे वह सार्वजनिक या निजी हो, प्रकृति में अधिकतर नियमित तथा निर्देशित होते थे। यद्यपि, उदासीकरण के बाद, तथा विशेष रूप से पिछली दो योजनाओं में निजी, संस्थागत तथा बाहरी पूंजी प्रवाह बाजार के निर्धारण में अधिक से अधिक अभिमुख हो रहे हैं। इन प्रवाहों के वितरण का पैटर्न का विषय रोचक है। इस खंड में, पांच मुख्य वर्गों में अर्थात् योजना परिव्यय, सार्वजनिक एवं निजी निवेश, संस्थागत निवेश, उधार उपयोग तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (वि.स.प.) में पूंजीगत प्रवाहों की दिशाओं पर नजर डालने का प्रयास किया गया है।

3.107 इन वर्गों से संबंधित सूचना आपस में सीधे तुलनीय नहीं है। किसी विशेष वर्ग के लिए यहां दी गई सूचना किसी निश्चित समय पर एक वर्ग के लिए भी पांच वर्ष की अवधि के औसत की तस्वीर में भिन्नता हो सकती है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निवेश, योजना परिव्ययों तथा बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में परस्पर दोहरापन है। ऐसे वर्गों में उधार उपयोगिता तथा निवेश को जोड़ा जाना चाहिए।

3.108 यद्यपि, एक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले राज्यों के संबंधित रैंकिंग से अनुमान प्राप्त करना सम्भव है। सभी आंकड़ों को मानकीकरण तथा तुलना में आसान करने के लिए प्रति व्यक्ति के अनुसार कम किया गया है। वि.सा.पा. के मामले को छोड़कर, जिसके लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के औसत वार्षिक प्रवाहों को लिया गया है, सभी आंकड़ें, 1999-2001 के लिए अद्यतन उपलब्ध सूचना के लिए हैं। राज्यों के प्रति व्यक्ति पूंजीगत प्रवाहों की स्थिति का तुलनात्मक विवरण तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23
राज्यों को प्रति व्यक्ति प्रवाहों की तुलनात्मक स्थिति, 1999/2000/2001

क्र. सं.	राज्य	जनसंख्या 2001	प्रति व्यक्ति	उधार सार्व. एवं जमा निजी	प्रति व्यक्ति	योजना परिव्यय	प्रति व्यक्ति	आरम्भिक निवेश	प्रति व्यक्ति	राज्यों में कुल उधार	राज्यों में प्रति	
		नि.रा.घ.अनुपातनिवेश उ. (रु.) 2001		सार्व एवं (रु.करोड़) निजी निवेश (रु.)		योजना (रु.करोड़) परिव्यय (रु.)		निवेश (रु.)		उपभोग कुल उधार (करोड़) उपभोग मार्च 2001 (रु.)		
2001												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गैर-विशेष श्रेणी												
1	आन्ध्र प्रदेश	75,727,541	14715	64.9	162416	21447.42	7816.48	1032.18	6887.36	909.49	35348.76	4667.89
2	बिहार	82,878,796	6328	20.7	23634	2851.63	2644.00	319.02	4524.49	545.92	5547.18	669.31
3	छत्तीसगढ़	20,795,956	@	49.9	25389	12208.62	1312.00	630.89	66.66	32.05	3748.97	1802.74
4	गोवा	1,343,998	उ.न.	27.3	7534	56056.63	460.00	3422.62	244.72	1820.84	1947.27	14488.64
5	गुजरात	50,596,992	18685	53.6	171399	33875.33	6500.00	1284.66	3641.14	719.64	29482.99	5827.02
6	हरियाणा	21,082,989	21551	54.0	19399	9201.26	1814.17	860.49	1743.57	827.00	10747.715	5097.67
7	झारखंड	26,909,428	@	30.6	24503	9105.73	2250.00	836.14	98.43	36.58	4733.35	1758.99
8	कर्नाटक	52,733,958	16343	61.8	130651	24775.50	7903.79	1498.80	3628.24	688.03	33856.03	6420.16
9	केरल	31,838,619	18262	42.3	38955	12235.14	2260.00	709.83	3733.05	1172.49	18697.06	5872.45
10	मध्य प्रदेश	60,385,118	10907	52.5	44001	7286.73	3937.76	652.11	4380.59	725.44	15264.19	2527.81
11	महाराष्ट्र	96,752,247	23398	83.5	169855	17555.66	10834.0	1119.77	6383.38	659.77	144064.2	14890.01
12	उड़ीसा	36,706,920	9162	41.6	93694	25524.80	2300.00	626.58	3851.48	1049.25	6262.34	1706.04
13	पंजाब	24,289,296	23040	42.3	30818	12687.89	3021.00	1243.76	2618.59	1078.08	18718.77	7706.59
14	राजस्थान	56,473,122	1253	49.6	38194	6763.22	4642.35	822.05	516187.87	914.04	13662.06	2419.21
15	तमिलनाडु	62,110,839	19141	90.6	163303	26292.19	5200.00	837.21	4405.87	709.36	57106.8	9194.34
16	उत्तर प्रदेश	166,052,259	9765	31.9	54859	3303.71	4872.77	293.45	10274.3	618.74	27192.58	1637.59
17	पश्चिम बंगाल	80,221,171	15569	43.4	57058	7112.59	5693.31	709.70	5308.71	661.76	29475.59	3674.29
विशेष श्रेणी राज्य												
1	अरुणाचल प्रदेश	1,091,117	14338	22.1	4134	37887.78	660.91	6057.19	59.8	548.06	135.51	1241.94
2	असम	26,638,407	9720	38.1	112303	42158.30	1710.00	641.93	1663.25	624.38	3759.79	1411.42
3	मणिपुर	2,388,634	11370	40.7	1207	5053.10	352.65	1476.37	138.76	580.92	175.76	735.82
4	मेघालय	2,306,069	11678	17.3	697	3022.46	472.82	2050.33	262.91	1140.08	285.35	1237.39
5	मिज़ोरम	891,058	उ.न.	29.0	1196	13422.25	441.51	4954.90	78.70	876.15	114.74	1287.68
6	नागालैंड	1,988,636	उ.न.	13.6	273	1372.80	411.47	2069.11	266	1337.60	122.45	615.75
7	सिक्किम	540,493	13356	14.5	6628	122628.7	300.00	5550.49	105.32	1948.59	88.1	1629.99
8	त्रिपुरा	3,191,168	10213	21.7	5609	17576.64	560.00	1754.84	196.15	614.67	339.08	1062.56
9	हिमाचल प्रदेश	6,077,248	15012	25.7	31664	52102.53	1744.51	2870.56	107.49	176.87	1903.38	3131.98
10	जम्मू व कश्मीर	10,069,917	12338	33.5	17034	16915.73	2050.00	2035.77	817.46	811.78	3313.21	3290.21
11	उत्तरांचल	8,479,562	@	23.9	16911	19943.25	1050.00	1238.27	13.26	15.64	2233.33	2633.78
सं.रा.क्षे.												
1	अण्ड. निकोबार	356,265	उ.न.	27.5	77	2161.31	370.00	10385.5			106.26	2982.61
2	चण्डीगढ़	900,914	46347	99.3	1170	12986.81	154.11	1710.60			7509.27	83351.69
3	दादरा व नागर	220,451		135.2	584	26491.15	51.48	2335.21			299.41	13581.70
4	दमन व दीव	158,059		75.3	12	759.21	42.19	2669.26			304.24	19248.51
5	दिल्ली	13,782,976	35705	57.6	16246	11787.00	3800.00	2757.02	195.8	142.06	61306.79	44480.08
6	लक्षद्वीप	60,595		11.8	24	3960.72	104.98	17324.8			6.49	1071.05
7	पांडिचेरी	973,829	30768	35.8	2072	21276.84	355.00	3645.40	0.24	2.46	575.03	5904.84

टिप्पणी : * : शून्य या नगण्य

: 1999-2000 के अनंतिम अनुमान

@ : नए सृजित राज्यों के लिए उपलब्ध नहीं

स्रोत : भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूल सांख्यिकीय रिटर्न भा.रि.बै. 2001 कालम के लिए (5,12) राष्ट्रीय लेखा विभाग रा.ले.वि. के सं.स. के लिए कालम (4) भा.रि.बै. बुलिटन अप्रैल 2002 के लिए कालम (10); निवेश की मासिक समीक्षा। परियोजना सीएमआईई अप्रैल 2002 के लिए कालम (6); (कुल बकाया निवेश हाथ में, चित्र में घोषित, प्रस्तावित एवं क्रियान्वयन के अधीन परियोजना के लिए राशि सम्मिलित है)

तालिका 3.24
प्रति व्यक्ति प्रवाह में अग्रणी राज्य

प्रति व्यक्ति प्रवाह	गैर विशेष वर्ग के ऊपरी पांच	विशेष वर्ग के ऊपरी दो
योजना परिव्यय	गोवा, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम
सार्वजनिक एवं निजी निवेश	गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक	सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
संस्थागत निवेश	गोवा, केरल, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान	सिक्किम, नागालैंड
उधार उपयोग	महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक	हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर
*विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एसीए	*आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा	सिक्किम, मणिपुर

*अनुलग्नक 3.12 में दी गई सूचना पर आधारित

3.109 तालिका 3.23 से हमने प्रत्येक वर्ग के लिए राज्यों के गैर-विशेष वर्ग से पांच ऊपरी राज्यों तथा राज्यों के विशेष वर्ग से ऊपरी दो राज्यों को अलग-अलग किया है। इससे जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसे तालिका 3.24 में दर्शाया गया है।

3.110 उन राज्यों की पहचान करने का प्रयास किया गया है जो विभिन्न वर्गों के सम्पर्क में वर्गों की संख्या पर विचार करते हुए उच्चतम प्रति व्यक्ति प्रवाह प्राप्त कर रहे हैं जिसमें एक विशेष राज्य उच्च पांच कोष्ठक में आते हैं (या विशेष वर्ग राज्यों में ऊपरी दो)। यह देखा जाता है कि गोवा तथा कर्नाटक उच्च पांच में से चार सम्भाव्य वर्गों में उड़ीसा तथा

पंजाब तीन में, गुजरात, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र, पांच वर्गों में से आते हैं। विशेष वर्ग के पांच राज्यों में, चार में सिक्किम, दो में हिमाचल प्रदेश आते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह वह राज्य है जिन्होंने अद्यतन वर्ष में बहुत पूंजीगत प्रवाह आकर्षित किए हैं।

3.111 ऊपरी कारण के बाद के समय से निजी, संस्थागत तथा विदेशी पूंजीगत प्रवाहों के बारे में सामान्य धारणा यह है कि उनका बाहुल्य खुशहाल तथा अच्छे ढांचे वाले राज्यों में होगा। इस अवधारणा का परीक्षण करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय तथा ढांचा सूचकांक के अनुसार राज्यों की रैंकिंग पर नजर डालते हैं। इस संबंध में स्थिति तालिका 3.25 में दर्शाई गई है।

तालिका 3.25
आय एवं आधारिक संरचना की स्थिति

राज्य	प्रति व्यक्ति आय	आधारिक संरचना
का	(नि.रा.घ.उ.- 1999-2000) (रु. में)	सूचकांक, 1999
गैर विशेष वर्ग	1. महाराष्ट्र 2. पंजाब 3. हरियाणा 4. तमिलनाडु 5. गुजरात	1. गोवा 2. पंजाब 3. केरल 4. तमिलनाडु 5. हरियाणा
विशेष वर्ग	1. हिमाचल प्रदेश 2. अरुणाचल प्रदेश	1. सिक्किम 2. हिमाचल प्रदेश

3.112 यदि हम उन पर चयनित राज्यों को जोड़ें जो अपेक्षाकृत बड़े प्रति व्यक्ति पूंजीगत प्रवाहों को अधिक खुशहाली एवं ढांचा सूचकांक में अच्छे धन प्रदान करने वालों को आकर्षित करते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि उड़ीसा के सिवाय सम्भवतः सामंजस्य का बहुत ऊंचा स्तर है। गैर विशेष वर्ग के राज्यों के बीच जो, इन सूचियों में कम से कम एक सूची में आते हैं वह हरियाणा तथा केरल हैं जो उच्च आय/ढांचा सूचियों में भी आते हैं, जबकि आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान निम्न आय वाले राज्यों जो कम से कम एक सूची बनाते हैं, में आते हैं।

3.113 उड़ीसा के मामले में, यह सम्भव है कि बहुआयामी संस्थानों से प्राप्त सहायता के कारण विदेशी सहायता के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के साथ-साथ, अद्यतन वर्षों में विद्युत क्षेत्र के सुधारों से जुड़े निजी निवेश के उच्चतर स्तरों ने राज्य को कम से कम अस्थायी रूप से पूंजीगत प्रवाहों वाले अधिक विकसित राज्यों के समान ला दिया है। आन्ध्र प्रदेश के मामले में इसने आकर्षक वि.स.प. में बकाया सफलता प्राप्त करने पर इसे एक सूची (वि.स.प.) में एक अग्रणी राज्य बना दिया है।

3.114 ऊपर विभिन्न प्रकार के पूंजीगत प्रवाहों पर विचार करने के बाद, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संवितरण से उत्पन्न होने वाले प्रवाहों का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। संसाधन दबावों के वर्तमान उस युग में, राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके वे अपने आंतरिक संसाधनों में ज्यादा

से ज्यादा बढ़ोत्तरी करें। वि.स.प. के माध्यम से राज्य के संसाधनों को बढ़ाना एक सकल बहुत महत्वपूर्ण सम्भाव्य स्रोत है, क्योंकि वास्तव में, वि.स.प. पर व्यय का 70-90 प्रतिशत भाग राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.के.स.) के रूप में प्रतिपूरित कर दिया जाता है तथा किसी राज्य के अ.के.स. प्राप्त करने की राशि पर कोई सीमा नहीं है। राज्य द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने की अ.के.स. की राशि राज्य द्वारा किए गए प्रयासों तथा मूलतः (i) परियोजना क्रियान्वयन की दक्षता, (ii) दान देने वाली एजेन्सी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावों की तैयारी, (iii) प्रस्तावों का उत्साही अनुसरण, तथा (iv) राज्य का एक सकारात्मक नीति-निर्देशों का चित्रण, विशेषकर प्रबन्ध एवं सुधारों पर निर्भर करता है।

3.115 यही एक रास्ता है जिससे यह संभव है कि कम विकसित राज्य विकास प्रयासों में वित्त पोषण को आकर्षित कर सके चाहे वह राज्य आधारिक संरचना की दृष्टि से उतने संपन्न नहीं हैं। इस संदर्भ में आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्हें नौवीं योजना में प्रति वर्ष सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सहायता मिल रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो नौवीं योजना की अवधि में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (काफी हद तक), मध्य प्रदेश (कुछ हद तक), ने अच्छा निष्पादन किया है। (नौवीं योजना में राज्यों के ई ए पी प्रवाह अनुलग्नक 3.12 में दिए गए हैं)। ई ए पी का उच्च आय/आधारिक संरचना स्तरों से संघ के सभी प्रकार के पूंजी प्रवाहों में सबसे कमजोर हैं और इससे राज्य द्वारा पहल करने की पर्याप्त गुंजाइश का संकेत मिलता है।

**1993-94 मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य आय) 1993-94 से 1999-2000 तक
(घटते क्रमानुसार में संवृद्धि दर के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)**

(रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (पी)	निर्यात वृद्धि दर
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पांडिचेरी	9781	9644	9841	13468	17390	19300	19895	15.7
2	चण्डीगढ़	19699	19653	21962	24055	24614	27717	29661	7.5
3	कर्नाटक	7835	8095	8363	8997	9228	10282	10928	5.8
4	पश्चिम बंगाल	6781	7121	7514	7903	8438	8900	9425	5.7
5	सिक्किम	7550	7113	7633	8236	9125	9440	9816	5.6
6	राजस्थान	6192	7158	7209	7851	8641	8735	8272	5.3
7	तमिलनाडु	8952	9944	10191	10583	11240	11775	12504	5.3
8	दिल्ली	18023	19454	18996	20189	22326	22977	24032	5.0
9	मणिपुर	5833	5565	5612	6331	6773	7014	7244	4.8
10	गोवा	15602	15655	16180	18320	18122	उ.न.	उ.न.	4.7 #
11	गुजरात	9796	11535	11649	13206	12937	13493	13022	4.6
12	त्रिपुरा	5350	5107	5339	5724	6115	6456	6604	4.5
13	महाराष्ट्र	12290	12299	13406	13784	14114	14312	15410	3.8
14	आन्ध्र प्रदेश	7447	7739	8086	8531	8214	9018	9318	3.6
15	केरल	7938	8516	8748	8987	9079	9542	10107	3.6
16	हिमाचल प्रदेश	7364	7934	7966	8326	8583	8905	9177	3.5
17	हरियाणा	11090	11617	11570	12664	12544	13003	13709	3.4
18	उत्तर प्रदेश	5258	5411	5498	5965	5848	6117	6373	3.2
19	मेघालय	6706	6697	7150	7161	7331	7727	7826	2.8
20	मध्य प्रदेश	6537	6441	6686	6962	7022	7407	7564	2.8
21	बिहार	3810	4068	3723	4093	4203	4397	4475	2.7
22	पंजाब	12714	12778	12989	13687	13705	14007	14678	2.4
23	जम्मू व कश्मीर	6543	6619	6732	6978	7128	7296	7435	2.3
24	उड़ीसा	4797	4913	5053	4652	5272	5264	5411	2.0
25	अण्डमान व निकोबार	15192	16191	15354	15896	16357	उ.न.	उ.न.	1.3 #
26	नागालैंड	9129	9410	9646	9880	10287	9118	उ.न.	0.8 \$
27	अरुणाचल प्रदेश	8579	8407	9424	8635	8693	8401	9170	0.4
28	असम	5715	5737	5760	5793	5796	5664	5978	0.4

टिप्पणी : # : संवृद्धि दर 1993-94 से 1997-98 तक संबंधित है।

\$: संवृद्धि दर 1993-94 से 1998-99 तक संबंधित है।

पी : अनंतिम अनुमान

उ.न. : उपलब्ध नहीं ।

स्रोत : राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (फ्लोपी में)

औद्योगिक क्षेत्रों (यूपीएस) द्वारा रोजगार का प्रतिशत वितरण

क्र.सं.	राज्य	1987-88				1993-94				1999-00			
		प्राथमिकमाध्यमिकतृतीयकयोग				प्राथमिकमाध्यमिकतृतीयकयोग				प्राथमिकमाध्यमिकतृतीयकयोग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	67.40	10.30	22.30	100.00	67.98	9.14	22.88	100.00	60.55	9.29	30.16	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	56.40	1.00	42.60	100.00	79.58	1.91	18.51	100.00	67.12	2.47	30.41	100.00
3	असम	69.30	3.00	27.70	100.00	71.64	3.04	25.32	100.00	57.90	3.81	38.29	100.00
4	बिहार	75.70	6.70	17.60	100.00	76.62	4.86	18.52	100.00	73.55	7.32	19.13	100.00
5	गुजरात	55.90	12.90	31.20	100.00	57.40	16.20	26.40	100.00	52.48	14.00	33.52	100.00
6	हरियाणा	58.90	12.70	28.40	100.00	46.60	11.00	42.40	100.00	45.15	12.45	42.40	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	75.40	5.20	19.40	100.00	71.68	3.89	24.43	100.00	60.30	5.42	34.28	100.00
8	जम्मू व कश्मीर	54.30	12.30	33.40	100.00	51.55	5.95	42.50	100.00	52.77	5.57	41.66	100.00
9	कर्नाटक	66.80	12.00	21.20	100.00	66.37	10.64	22.99	100.00	58.40	11.52	30.08	100.00
10	केरल	47.90	15.90	36.20	100.00	45.36	14.90	39.74	100.00	34.67	15.63	49.70	100.00
11	मध्य प्रदेश	77.00	7.60	15.40	100.00	77.60	5.80	16.60	100.00	68.62	7.56	23.82	100.00
12	महाराष्ट्र	63.20	11.30	25.50	100.00	60.40	11.20	28.40	100.00	49.96	12.63	37.41	100.00
13	मणिपुर	60.40	6.40	33.20	100.00	55.19	9.11	35.70	100.00	63.49	6.33	30.18	100.00
14	मेघालय	77.63	1.69	20.68	100.00	78.80	1.10	20.10	100.00	70.35	1.31	28.35	100.00
15	उड़ीसा	69.80	9.10	21.10	100.00	73.95	7.23	18.82	100.00	68.96	9.10	21.94	100.00
16	पंजाब	52.10	14.50	33.40	100.00	49.36	11.73	38.91	100.00	43.48	13.30	43.22	100.00
17	राजस्थान	65.40	8.30	26.30	100.00	67.00	7.00	26.00	100.00	61.42	8.66	29.92	100.00
18	तमिलनाडु	51.20	19.90	28.90	100.00	52.40	18.12	29.48	100.00	41.93	20.10	37.97	100.00
19	त्रिपुरा	40.10	6.20	53.70	100.00	41.20	5.50	53.30	100.00	38.20	3.87	57.93	100.00
20	उत्तर प्रदेश	70.20	9.20	20.60	100.00	66.97	9.57	23.46	100.00	60.19	11.87	27.97	100.00
21	पश्चिम बंगाल	52.30	17.70	30.00	100.00	48.34	18.75	2.91	100.00	47.34	17.56	35.10	100.00
22	दिल्ली	4.20	25.20	70.60	100.00	2.20	27.70	70.10	100.00	5.26	23.61	71.13	100.00
23	पांडिचेरी	41.40	20.50	38.10	100.00	35.35	17.96	46.69	100.00	23.68	26.65	49.67	100.00
	मानक विचलन	16.16	6.16	12.47		17.89	6.46	13.14		16.26	6.60	11.97	
	औसत (23 राज्य)	58.82	10.85	30.33		58.41	10.10	31.49		52.43	10.87	36.71	

स्रोत : एन एस एस ओ। 1999-00 के लिए आंकड़े जनसंख्या के 2001 की जनगणना के शहरी ग्रामीण अनुपात का प्रयोग करके प्राप्त किए गए हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	1973-74			1977-78			1983		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	48.41	50.61	48.86	38.11	43.55	39.31	26.53	36.30	28.91
2	अरुणाचल प्रदेश	52.67	36.92	51.93	59.82	32.71	58.32	42.60	21.73	40.88
3	असम	52.67	36.92	51.21	59.82	32.71	57.15	42.60	21.73	40.47
4	बिहार	62.99	52.96	61.91	63.25	48.76	61.55	64.37	47.33	62.22
5	गोवा	46.85	37.69	44.26	37.64	36.31	37.23	14.81	27.00	18.90
6	गुजरात	46.35	52.57	48.15	41.76	40.02	41.23	29.80	39.14	32.79
7	हरियाणा	34.23	40.18	35.36	27.73	36.57	29.55	20.56	24.15	21.37
8	हिमाचल प्रदेश	27.42	13.17	26.39	33.49	19.44	32.45	17.00	9.43	16.40
9	जम्मू व कश्मीर	45.51	21.32	40.83	42.86	23.71	38.97	26.04	17.76	24.24
10	कर्नाटक	55.14	52.53	54.47	48.18	50.36	48.78	36.33	42.82	38.24
11	केरल	59.19	62.74	59.79	51.48	55.62	52.22	39.03	45.68	40.42
12	मध्य प्रदेश	62.66	57.65	61.78	62.52	58.66	61.78	48.90	53.06	49.78
13	महाराष्ट्र	57.71	43.87	53.24	63.97	40.09	55.88	45.23	40.26	43.44
14	मणिपुर	52.67	36.92	49.96	59.82	32.71	53.72	42.60	21.73	37.02
15	मेघालय	52.67	36.92	50.20	59.82	32.71	55.19	42.60	21.73	38.81
16	मिज़ोरम	52.67	36.92	50.32	59.82	32.71	54.38	42.60	21.73	36.00
17	नागालैंड	52.67	36.92	50.81	59.82	32.71	56.04	42.60	21.73	39.25
18	उड़ीसा	67.28	55.62	66.18	72.38	50.92	70.07	67.53	49.15	65.29
19	पंजाब	28.21	27.96	28.15	16.37	27.32	19.27	13.20	23.79	16.18
20	राजस्थान	44.76	52.13	46.14	35.89	43.53	37.42	33.50	37.94	34.46
21	सिक्किम	52.67	36.92	50.86	59.82	32.71	55.89	42.60	21.73	39.71
22	तमिलनाडु	57.43	49.40	54.94	57.68	48.69	54.79	53.99	46.96	51.66
23	त्रिपुरा	52.67	36.92	51.00	59.82	32.71	56.88	42.60	21.73	40.03
24	उत्तर प्रदेश	56.53	60.09	57.07	47.60	56.23	49.05	46.45	49.82	47.07
25	पश्चिम बंगाल	73.16	34.67	63.43	68.34	38.20	60.52	63.05	32.32	54.85
26	अण्डमान और निकोबार द्वीप	57.43	49.40	55.56	57.68	48.69	55.42	53.99	46.96	52.13
27	चण्डीगढ़	27.96	27.96	27.96	27.32	27.32	27.32	23.79	23.79	23.79
28	दादर और नागर हवेली	46.85	37.69	46.55	37.64	36.31	37.20	14.81	27.00	15.67
29	दिल्ली	24.44	52.23	49.61	30.19	33.51	33.23	7.66	27.89	26.22
30	लक्षद्वीप	59.19	62.74	59.68	51.48	55.62	52.79	39.03	45.68	42.36
31	पांडिचेरी	57.43	49.40	53.82	57.68	48.69	53.25	53.99	46.96	50.06
	अखिल भारत	56.44	49.01	54.88	53.07	45.24	51.32	45.65	40.79	44.48

स्रोत : योजना आयोग

गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	1987-88			1993-94			1999-00		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	20.92	40.11	25.86	15.92	38.33	22.19	11.05	26.63	15.77
2	अरुणाचल प्रदेश	39.35	9.94	36.22	45.01	7.73	39.35	40.04	7.47	33.47
3	असम	39.35	9.94	36.21	45.01	7.73	40.86	40.04	7.47	36.09
4	बिहार	52.63	48.73	52.13	58.21	34.50	54.96	44.30	32.91	42.6
5	गोवा	17.64	35.48	24.52	5.34	27.03	14.92	1.35	7.52	4.4
6	गुजरात	28.67	37.26	31.54	22.18	27.89	24.21	13.17	15.59	14.07
7	हरियाणा	16.22	17.99	16.64	28.02	16.38	25.05	8.27	9.99	8.74
8	हिमाचल प्रदेश	16.28	6.29	15.45	30.34	9.18	28.44	7.94	4.63	7.63
9	जम्मू व कश्मीर	25.70	17.47	23.82	30.34	9.18	25.17	3.97	1.98	3.48
10	कर्नाटक	32.82	48.42	37.53	29.88	40.14	33.16	17.38	25.25	20.04
11	केरल	29.10	40.33	31.79	25.76	24.55	25.43	9.38	20.27	12.72
12	मध्य प्रदेश	41.92	47.09	43.07	40.64	48.38	42.52	37.06	38.44	37.43
13	महाराष्ट्र	40.78	39.78	40.41	37.93	35.15	36.86	23.72	26.81	25.02
14	मणिपुर	39.35	9.94	31.35	45.01	7.73	33.78	40.04	7.47	28.54
15	मेघालय	39.35	9.94	33.92	45.01	7.73	37.92	40.04	7.47	33.87
16	मिज़ोरम	39.35	9.94	27.52	45.01	7.73	25.66	40.04	7.47	19.47
17	नागालैंड	39.35	9.94	34.43	45.01	7.73	37.92	40.04	7.47	32.67
18	उड़ीसा	57.64	41.63	55.58	49.72	41.64	48.56	48.01	42.83	47.15
19	पंजाब	12.60	14.67	13.20	11.95	11.35	11.77	6.35	5.75	6.16
20	राजस्थान	33.21	41.92	35.15	26.46	30.49	27.41	13.74	19.85	15.28
21	सिक्किम	39.35	9.94	36.06	45.01	7.73	41.43	40.04	7.47	36.55
22	तमिलनाडु	45.80	38.64	43.39	32.48	39.77	35.03	20.55	22.11	21.12
23	त्रिपुरा	39.35	9.94	35.23	45.01	7.73	39.01	40.04	7.47	34.44
24	उत्तर प्रदेश	41.10	42.96	41.46	42.28	35.39	40.85	31.22	30.89	31.15
25	पश्चिम बंगाल	48.30	35.08	44.72	40.80	22.41	35.66	31.85	14.86	27.02
26	अण्डमान और निकोबार द्वीप	45.80	38.64	43.89	32.48	39.77	34.47	20.55	22.11	20.99
27	चण्डीगढ़	14.67	14.67	14.67	11.35	11.35	11.35	5.75	5.75	5.75
28	दादर और नागर हवेली	67.11	0.00	67.11	51.95	39.93	50.84	17.57	13.52	17.14
29	दिल्ली	1.29	13.56	12.41	1.90	16.03	14.69	0.40	9.42	8.23
30	लक्षद्वीप	29.10	40.33	34.95	25.76	24.55	25.04	9.38	20.27	15.6
31	पांडिचेरी	45.80	38.64	41.46	32.48	39.77	37.40	20.55	22.11	21.67
	अखिल भारत	39.09	38.20	38.86	37.27	32.36	35.97	27.09	23.62	26.10

स्रोत : योजना आयोग

**फसल की उपज का राज्य एड्रव क्षेत्रवार स्तर तथा संवृद्धि
(1990-93 के स्थिर मूल्यों पर)**

क्र.सं.	राज्य								
		1962-65	1970-73	1980-83	1992-95	1962-73	1970-1980- 1983 1995	1962- 1995	
	पूर्व पश्चिमी क्षेत्र	4092.75	5024.54	6422.63	9582.5	2.6	2.49	3.39	2.88
1	हरियाणा	3927.21	5090.01	6229.13	10128.73	3.3	2.04	4.13	3.21
2	हिमाचल प्रदेश	3048.15	3733.76	3917.69	5195.93	2.57	0.48	2.38	1.79
3	जम्मू व कश्मीर	2986.95	4481.4	5758.75	5567.01	5.2	2.54	-0.28	2.1
4	पंजाब	5395.62	7476.29	9707.65	13597.22	4.16	2.65	2.85	3.13
5	उत्तर प्रदेश	3970.1	4589.98	5805.13	8656.2	1.83	2.38	3.39	2.63
	पूर्वी क्षेत्र	4338.3	4671.31	4944	7318.5	0.93	0.57	3.32	1.76
6	असम	5727.97	6241.2	6906.69	8196.82	1.08	1.02	1.44	1.2
7	बिहार	3679.55	4009.73	4048.56	5678.08	1.08	0.1	2.86	1.46
8	उड़ीसा	4114.37	4072.7	4374.84	5979.16	-0.13	0.72	2.64	1.25
9	पश्चिम बंगाल	5074.57	5614.56	5943.81	9958.45	1.27	0.57	4.39	2.27
	केन्द्रीय क्षेत्र	2653.78	2763.12	3463.09	4943.84	0.51	2.29	3.01	2.1
10	गुजरात	3673.01	4326.57	5693.43	7460.09	2.07	2.78	2.28	2.39
11	मध्य प्रदेश	2603.49	2835.86	3069.65	4773.12	1.07	0.8	3.75	2.04
12	महाराष्ट्र	2898.61	2343.57	3794.68	5176.94	-2.62	4.94	2.62	1.95
13	राजस्थान	1740.45	2217.1	2334.77	3715.22	3.07	0.52	3.95	2.56
	दक्षिणी क्षेत्र	4873.34	5872.68	6848.2	9990.63	2.36	1.55	3.2	2.42
14	आन्ध्र प्रदेश	4064.96	4363.05	6276.23	9390.64	0.89	3.7	3.41	2.83
15	कर्नाटक	3207.56	4267.23	4989.92	6969.7	3.63	1.58	2.82	2.62
16	केरल	11375.65	12957.56	12333.85	15625.96	1.64	-0.49	1.99	1.06
17	तमिलनाडु	6689.49	7889.75	8756.47	14073.94	2.1	1.03	4.03	2.51
	अखिल भारत	3738.19	4256.79	5090.42	7388.05	1.64	1.8	3.15	2.3

स्रोत : भारत सरकार, भारत में मुख्य फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन (विभिन्न मामले), कृषि मंत्रालय

अनुलग्नक - 3.5(1)

जनसंख्या हजार में (2001 के रैंकवार में व्यवस्थापित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	2001
1	अखिल भारत	361088	439235	548160	684329	846302	1027015
2	उत्तर प्रदेश	63220	73755	88341.52	110862.5	139112.3	166053
3	महाराष्ट्र	32002	39554	50412.24	62782.82	78937.19	96752
4	बिहार	38728	46447	56353.37	69914.73	86374.47	82879
5	पश्चिम बंगाल	26300	34926	44312.01	54580.65	68077.97	80221
6	आन्ध्र प्रदेश	31115	35983	43502.71	53551.03	66508.01	75728
7	तमिलनाडु	30119	33687	41199.17	48408.08	55859	62111
8	मध्य प्रदेश	26072	32372	41654.12	52178.84	66181.17	60385
9	राजस्थान	15971	20156	25765.81	34361.86	44005.99	56473
10	कर्नाटक	19402	23587	29299.01	37135.71	44977.2	52374
11	गुजरात	16263	20633	26697.48	34085.8	41309.58	50597
12	उड़ीसा	14646	17549	21944.62	26370.27	31659.74	36707
13	केरल	13549	16904	21347.38	25453.68	29098.52	31839
14	असम (2)	8029	10837	14625.15	18041.25	22414.32	26638
15	पंजाब	9160	11135	13551.06	16788.92	20281.97	24289
16	हरियाणा	5674	7591	10036.43	12922.12	16464	21083
17	दिल्ली	1744	2659	4065.698	6220.406	9420.644	13783
18	जम्मू व कश्मीर (3)	3254	3561	4616.632	5987.389	7718.7	10070
19	हिमाचल प्रदेश	2386	2812	3460.434	4280.818	5170.877	6077
20	त्रिपुरा	639	1142	1556.342	2053.058	2757.205	3191
21	मणिपुर	578	780	1072.753	1420.953	1837.149	2389
22	मेघालय	606	769	1011.699	1335.819	1774.778	2306
23	नागालैंड	213	369	516.449	774.93	1209.546	1989
24	गोवा	547	590	857.771	1086.73	1169.793	1344
25	अरुणाचल प्रदेश (1)		337	467.511	631.839	864.558	1091
26	पांडिचेरी	317	369	471.707	604.471	807.785	974
27	चण्डीगढ़	24	120	257.251	451.61	642.015	901
28	मिज़ोरम	196	266	332.39	493.757	689.756	891
29	सिक्किम	138	162	209.843	316.385	406.457	540
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप	31	64	115.133	188.741	280.661	356
31	दादर और नागर हवेली	41	58	74.14	103.676	138.477	220
32	दमन और दियू	49	37	63	79	101	158
33	लक्षद्वीप	21	24	31.81	40.249	51.707	61

टिप्पणी : (1) 1961 में पहली बार जनगणना के लिए लिया गया।

(2) असम में 1981 में जनगणना नहीं हो सकी। इन्टरपोलेशन द्वारा 1981 के लिए कुल जनसंख्या को लिया गया है।

(3) जम्मू व कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं हो सकी। जम्मू व कश्मीर के लिए जनसंख्या जैसा कि जनसंख्या प्रक्षेपण पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति (अक्टूबर 1989) द्वारा प्रक्षेपित की गई है।

स्रोत I: भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

**जनसंख्या की दशकीय संवृद्धि प्रतिशत
(1991-2001 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)**

क्र.सं.राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91	1991-2001
1 नागालैंड	73.24	39.96	50.05	56.08	64.44
2 दादर और नागर हवेली	41.46	27.83	39.84	33.57	58.87
3 दमन और दियू	-24.49	70.27	25.40	27.85	56.44
4 दिल्ली	52.47	52.90	53.00	51.45	46.31
5 चण्डीगढ़	400.00	114.38	75.55	42.16	40.34
6 सिक्किम	17.39	29.53	50.77	28.47	32.86
7 जम्मू व कश्मीर (3)	9.43	29.64	29.69	28.92	30.46
8 मणिपुर	34.95	37.53	32.46	29.29	30.04
9 मेघालय	26.90	31.56	32.04	29.29	30.04
10 मिज़ोरम	35.71	24.96	48.55	39.70	29.18
11 राजस्थान	26.20	27.83	33.36	28.07	28.33
12 हरियाणा	33.79	32.21	28.75	27.41	28.06
13 अण्डमान और निकोबार द्वीप	106.45	79.90	63.93	48.70	26.84
14 अरुणाचल प्रदेश (1)		38.73	35.15	36.83	26.19
15 महाराष्ट्र	23.60	27.45	24.54	25.73	22.57
16 गुजरात	26.87	29.39	27.67	21.19	22.48
17 भारत	21.64	24.80	24.84	23.67	21.32
18 पांडिचेरी	16.40	27.83	28.15	33.64	20.58
19 पंजाब	21.56	21.70	23.89	20.81	19.76
20 उत्तर प्रदेश	16.66	19.78	25.49	25.48	19.37
21 असम (2)	34.97	34.96	23.36	24.24	18.84
22 लक्षद्वीप	14.29	32.54	26.53	28.47	17.97
23 पश्चिम बंगाल	32.80	26.87	23.17	24.73	17.84
24 हिमाचल प्रदेश	17.85	23.06	23.71	20.79	17.52
25 कर्नाटक	21.57	24.22	26.75	21.12	17.25
26 उड़ीसा	19.82	25.05	20.17	20.06	15.94
27 त्रिपुरा	78.72	36.28	31.92	34.30	15.73
28 गोवा	7.86	45.38	26.69	7.64	14.89
29 आन्ध्र प्रदेश	15.65	20.90	23.10	24.20	13.86
30 तमिलनाडु	11.85	22.30	17.50	15.39	11.19
31 केरल	24.76	26.29	19.24	14.32	9.42
32 बिहार	19.93	21.33	24.06	23.54	-4.05
33 मध्य प्रदेश	24.16	28.67	25.27	26.84	-8.76

टिप्पणी : (1) 1961 में पहली बार जनगणना के लिए लिया गया।

(2) असम में 1981 में जनगणना नहीं हो सकी। 1981 के लिए कुल जनसंख्या इन्टरपोलेशन के द्वारा प्राप्त की गई है।

(3) जम्मू व कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं हो सकी। जम्मू व कश्मीर के लिए जनसंख्या जैसा कि जनसंख्या प्रक्षेपण पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति (अक्टूबर 1989) द्वारा प्रक्षेपित की गई है।

(4) वर्ष 2001 के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन राज्यों के विभाजन के बाद के हैं।

स्रोत : भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय।

घरों का प्रतिशत जिनमें सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता है

क्र.सं.	राज्य/ सं.रा.क्षे.	1981			1991			औसत वार्षिक परिवर्तन		
		ग्रामीण	शहरी	सम्मिश्रित	ग्रामीण	शहरी	सम्मिश्रित	ग्रामीण	शहरी	सम्मिश्रित
1	आन्ध्र प्रदेश	15.12	63.27	25.89	48.98	73.82	55.08	22.39	1.67	11.27
2	अरुणाचल प्रदेश	40.16	87.93	43.89	66.87	88.20	70.02	6.65	0.03	5.95
3	असम				43.28	64.07	45.86			
4	बिहार	33.77	65.36	37.64	56.55	73.39	58.76	6.75	1.23	5.61
5	दिल्ली	62.26	94.91	92.97	91.01	96.24	95.78	4.62	0.14	2.30
6	गोवा	8.57	52.31	22.50	30.50	61.71	43.41	25.64	1.80	9.29
7	गुजरात	36.16	86.78	52.41	60.04	87.23	69.78	6.60	0.05	3.31
8	हरियाणा	42.94	90.72	55.11	67.14	93.18	7.32	5.64	0.27	3.49
9	हिमाचल प्रदेश	39.56	89.56	44.50	75.51	91.93	77.34	9.09	0.26	7.38
10	जम्मू व कश्मीर	27.95	86.67	40.28						
11	कर्नाटक	17.63	74.40	33.87	67.31	81.38	71.68	28.18	0.94	11.16
12	केरल	6.26	39.72	12.20	12.22	38.68	18.89	9.52	-0.26	5.48
13	मध्य प्रदेश	8.09	66.65	20.17	45.56	79.45	53.41	46.32	1.92	16.48
14	महाराष्ट्र	18.34	85.56	42.29	54.02	90.50	68.49	19.45	0.58	6.20
15	मणिपुर	12.91	38.71	19.54	33.72	52.10	38.72	16.12	3.46	9.82
16	मेघालय	14.26	74.40	25.11	26.82	75.42	36.16	8.81	0.14	4.40
17	मिज़ोरम	3.57	8.79	4.88	12.89	19.88	16.21	26.11	12.62	23.22
18	नागालैंड	43.43	57.18	45.63	55.60	45.47	53.37	2.80	-2.05	1.70
19	उड़ीसा	9.47	51.33	14.58	35.32	62.83	39.07	27.30	2.24	16.80
20	पंजाब	81.80	91.13	84.56	92.09	94.24	92.74	1.26	0.34	0.97
21	राजस्थान	13.00	78.65	27.14	50.62	86.51	58.96	28.94	1.00	11.72
22	सिक्किम	21.70	71.93	30.33	70.98	92.95	73.19	22.71	2.92	14.13
23	तमिलनाडु	30.97	69.44	43.07	64.28	74.17	67.42	10.76	0.68	5.65
24	त्रिपुरा	22.17	67.92	27.33	30.60	71.12	37.18	3.80	0.47	3.60
25	उत्तर प्रदेश	25.31	73.23	33.77	56.62	85.78	62.24	12.37	1.71	8.43
26	पश्चिम बंगाल	65.78	79.78	69.65	80.26	86.23	81.98	2.20	0.81	1.77
27	अण्डमान और निकोबार द्वीप	36.35	91.95	51.64	59.43	90.91	67.87	6.35	-0.11	3.14
28	चण्डीगढ़	94.39	99.39	99.09	98.11	97.68	97.73	0.39	-0.17	-0.14
29	दादरा और नागर हवेली	16.85	54.35	19.35	41.17	90.97	45.57	14.43	6.74	13.55
30	दमन ओर दीव	46.42	67.04	54.48	55.87	86.76	71.42	2.04	2.94	3.11
31	लक्षद्वीप	0.97	3.65	2.19	3.41	18.79	11.90	25.15	41.48	44.34
32	पांडिचेरी	76.88	84.18	80.59	92.86	86.05	88.75	2.08	0.22	1.01
	अखिल भारत	26.50	75.06	38.19	55.54	81.38	62.30	10.96	0.84	6.31

टिप्पणी : अखिल भारत के आंकड़ें, असम में 1981 तथा जम्मू व कश्मीर में 1991 को छोड़कर हैं।

स्रोत : आवास तथा सुविधाएं, 1993 का पेपर 2, भारत की जनगणना, 1991।

वास्तविक योजना व्यय की क्षेत्रीय संरचना (प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सामाजिक क्षेत्र			द्विचारा		
		1981-82	1991-92	1997-98	1981-82	1991-92	1997-98
1	आन्ध्र प्रदेश	17.68	20.48	22.46	41.14	43.21	37.77
2	अरुणाचल प्रदेश	24.59	25.90	29.65	45.66	47.07	46.37
3	असम	17.97	34.31	45.89	52.56	29.97	22.12
4	बिहार	15.18	18.28	17.26	38.59	28.88	15.82
5	दिल्ली	52.26	49.74	51.90	38.37	43.90	38.94
6	गोवा	35.11	39.55	42.83	30.23	28.98	27.74
7	गुजरात	17.21	19.19	22.97	41.53	40.59	27.71
8	हरियाणा	15.84	31.82	34.26	41.80	35.55	32.49
9	हिमाचल प्रदेश	22.95	32.64	35.24	45.06	32.78	30.41
10	जम्मू व कश्मीर	30.79	33.31	28.86	32.74	37.04	41.19
11	कर्नाटक	17.79	23.33	32.31	45.70	38.96	23.50
12	केरल	22.82	18.23	18.88	39.59	42.61	39.38
13	मध्य प्रदेश	13.80	21.89	32.74	47.01	39.03	26.39
14	महाराष्ट्र	25.72	20.10	20.69	43.90	38.00	35.09
15	मणिपुर	29.07	24.58	32.44	29.93	37.31	38.57
16	मेघालय	28.97	29.32	37.83	45.09	38.99	33.58
17	मिज़ोरम	26.54	25.68	30.35	45.93	35.38	41.10
18	नागालैंड	26.65	24.38	36.73	39.33	30.42	19.87
19	उड़ीसा	12.28	17.60	32.38	40.79	37.94	23.43
20	पंजाब	18.50	20.40	20.67	49.59	56.62	60.32
21	राजस्थान	17.19	23.30	24.22	47.99	39.00	44.19
22	सिक्किम	19.83	28.09	45.38	41.42	47.07	32.90
23	तमिलनाडु	25.22	34.35	38.89	47.17	40.36	38.67
24	त्रिपुरा	28.69	30.16	43.18	27.53	26.11	22.34
25	उत्तर प्रदेश	15.74	18.48	29.60	45.66	51.09	34.85
26	पश्चिम बंगाल	29.85	21.13	22.83	41.38	47.52	48.06
27	अण्डमान और निकोबार द्वीप	17.07	17.64	34.36	64.72	71.17	48.78
28	चण्डीगढ़	78.83	71.71	81.29	17.84	18.56	13.35
29	दादर और नागर हवेली	11.76	23.08	37.50	13.32	24.51	34.88
30	दमन ओर दियू	35.71	34.61	41.22	30.23	34.66	33.17
31	लक्षद्वीप	15.71	22.69	20.19	50.83	46.81	46.53
32	पांडिचेरी	42.82	37.13	37.24	27.43	42.36	41.15
33	केन्द्रीय सरकार	8.80	12.50	14.80	77.40	72.90	73.00

टिप्पणी : वास्तविक योजना व्यय के लिए निम्नलिखित को एकत्रित कर दिया गया है:

सामाजिक क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आपूर्ति एवं सफाई, शहरी विकास, सूचना, कल्याण एवं श्रम।

1981-82 के लिए आंकड़े 1980-82 का औसत, 1991-92 के 1990-93 का औसत तथा 1997-98 के 1996-98 का औसत है।

स्रोत : विभिन्न योजना दस्तावेज, योजना आयोग, भारत सरकार

अनुलग्नक - 3.8 (1)

**राज्य-वार सड़क घनत्व कि.मी. में
(सड़क लम्बाई प्रति '000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र)
(1996-97 में रैंक के अनुसार व्यवस्थित)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971-72	1981-82	1991-92	1996-97
1	दिल्ली	7984	10527	14256	17924
2	पांडिचेरी	3508*	4286	6698	4859
3	केरल	3106	2751	3567	3749
4	गोवा	1581*	2141	2005	2245
5	उड़ीसा	366	772	1260	1687
6	तमिलनाडु	714	1020	1523	1588
7	चण्डीगढ़	710*	1250	14000	15377
8	त्रिपुरा	386	759	1341	1405
9	पंजाब	594	916	1078	1278
10	महाराष्ट्र	316	586	730	1176
11	नागालैंड	284	379	901	1107
12	दादर और नागर हवेली	460*	492	643	1086
13	असम	383	760	836	872
14	उत्तर प्रदेश	382	520	692	868
15	पश्चिम बंगाल	599	642	700	850
16	कर्नाटक	525*	557	701	751
17	अखिल भारत	344	466	615	749
18	आन्ध्र प्रदेश	264	468	553	647
19	हरियाणा	307	542	601	637
20	हिमाचल प्रदेश	215	369	459	542
21	बिहार	670	481	492	508
22	मणिपुर	392	239	314	490
23	गुजरात	221	375	419	464
24	मध्य प्रदेश	162	242	321	451
25	मेघालय	303	233	291	378
26	राजस्थान	146	212	363	379
27	सिक्किम	329*	156	227	258
28	मिज़ोरम	43*	119	179	229
29	अरुणाचल प्रदेश	125*	152	131	160
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप	82*	83	110	159
31	जम्मू व कश्मीर	40	53	56	97
32	दमन और दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	26
33	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	31

टिप्पणी : * 1975-76 के आंकड़े से संबंधित हैं।

उ.न. (उपलब्ध नहीं)

स्रोत : मूल सड़क सांख्यिकी, भूतल परिवहन मंत्रालय (विभिन्न मामलों)

कि.मी. में राज्य-वार सड़क घनत्व
(कि.मी. प्रति एक लाख जनसंख्या)
(1995 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे.	1981	1988	1995
1	अरुणाचल प्रदेश	2089.49	1130.8	1317.8
2	नागालैंड	754.98	1024.7	1073.3
3	मिज़ोरम	231.35	666.7	939.6
4	उड़ीसा	454	741.3	666.3
5	गोवा	697.69	578.8	608.6
6	हिमाचल प्रदेश	464.32	523.8	586.8
7	मणिपुर	406.35	462.7	585
8	त्रिपुरा	380.1	544.6	544.7
9	दादर और नागर हवेली	209.62	310	509
10	केरल	410	425.6	480.4
11	सिक्किम	335	488.1	456
12	मेघालय	358.96	478.5	428.9
13	तमिलनाडु	256.53	345.1	367.8
14	पांडिचेरी	351.49	447.3	336
15	मध्य प्रदेश	200	241.1	319.3
16	कर्नाटक	296.72	340.3	312
17	असम	23.5	323.1	305.3
18	राजस्थान	187	310.2	296.3
19	अण्डमान निकोबार द्वीप	351.6	363.7	290.3
20	महाराष्ट्र	171.22	330	285.5
21	पंजाब	275.4	303.1	282.4
22	चण्डीगढ़	28.67	319.3	272
23	गुजरात	171.03	219.5	263.4
24	आन्ध्र प्रदेश	219.73	256.8	258.7
25	दिल्ली	224.6	306	242.2
26	हरियाणा	178.82	200.9	166.6
27	जम्मू व कश्मीर	194.73	219.8	163.5
28	उत्तर प्रदेश	136.05	165.9	154.1
29	बिहार	119.73	121.3	101.8
30	पश्चिम बंगाल	104.29	105.6	90.7
31	अखिल भारत	21.68		25.82
32	दमन और दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : उ.न. (उपलब्ध नहीं)

स्रोत : मूल सड़क सांख्यिकी, भूतल परिवहन मंत्रालय (विभिन्न मामले)

अनुलग्नक-3.9 (1)

कि.मी. (प्रति '000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) में रेलवे घनत्व
(1996-97 के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971-72	1981-82	1991-92	1996-97
1	दिल्ली		84	113.28	115.54
2	चण्डीगढ़		110	96.49	72.73
3	पंजाब	42.38	42.78	42.89	42.49
4	पश्चिम बंगाल	41.55	41.85	43	42.46
5	हरियाणा	32.2	34.09	33.9	34.22
6	असम	27.76	27.58	31.45	31.04
7	तमिलनाडु	28.91	29.96	30.83	30.75
8	उत्तर प्रदेश	29.36	30.2	30.29	30.27
9	बिहार	29.67	30.82	30.57	30.22
10	गुजरात	28.77	28.73	26.94	27.15
11	केरल	22.82	23.49	25.32	27.02
12	पांडिचेरी		54.00	54.88	22.45
13	गोवा		19.75	21.34	21.35
14	अखिल भारत	18.33	18.63	19.00	19.08
15	आन्ध्र प्रदेश	17.24	17.39	18.49	18.38
16	महाराष्ट्र	16.97	17.32	17.68	18.05
17	राजस्थान	16.34	16.42	17.02	17.21
18	कर्नाटक	14.61	15.70	15.98	15.95
19	उड़ीसा	12.03	12.71	12.86	14.06
20	मध्य प्रदेश	12.95	12.95	13.31	13.29
21	हिमाचल प्रदेश	4.57	4.57	4.78	4.83
22	त्रिपुरा	1.2	1.2	4.29	4.29
23	नागालैंड	0.53	0.53	0.54	1.15
24	जम्मू व कश्मीर	0.03	0.35	0.35	0.38
25	मिज़ोरम			0.09	0.09
26	मणिपुर			0.04	0.04
27	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.01	0.01
28	मेघालय				
29	सिक्किम				
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप				
31	दादर और नागर हवेली				
32	दमन और दीव				
33	लक्षद्वीप				

स्रोत : रेलवे बोर्ड

रेल मार्ग-लम्बाई, निरपेक्ष बढ़ोत्तरी, अंशतया प्रतिशत बढ़ोत्तरी
(प्रतिशत बढ़ोत्तरी के रैंक के अनुसार व्यवस्थित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1996-97	निरपेक्ष बढ़ोत्तरी		प्रतिशत अंश
प्रतिशत बढ़ोत्तरी						
1	त्रिपुरा	12	45	33	2.2	275.00
2	नागालैंड	9	19	10	0.7	111.11
3	केरल	916	1050	134	9.0	14.63
4	असम	2179	2435	256	17.1	11.75
5	उड़ीसा	1982	2190	208	13.9	10.49
6	जम्मू व कश्मीर	77	84	7	0.5	90.09
7	महाराष्ट्र	5235	5554	319	21.3	6.09
8	आन्ध्र प्रदेश	4781	5057	276	18.5	5.77
9	हिमाचल प्रदेश	256	269	13	0.9	5.08
10	राजस्थान	5614	5890	276	18.5	4.92
11	मध्य प्रदेश	5736	5893	157	10.5	2.74
12	तमिलनाडु	3895	3999	104	7.0	2.67
13	भारत	61,230	62725	1495	100	2.44
14	दिल्ली	168	171	3	0.2	1.79
15	कर्नाटक	3015	3059	44	2.9	1.46
16	पश्चिम बंगाल	3725	3768	43	2.9	1.15
17	हरियाणा	1500	1513	13	0.9	0.87
18	उत्तर प्रदेश	8880	8911	31	2.1	0.35
19	पंजाब	2139	2140	1	0.1	0.05
20	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0.0	0.00
21	गोवा	79	79	0	0.0	0.00
22	मणिपुर	1		1	0	0.00
23	बिहार	5362	5254	-108	-7.2	-2.01
24	गुजरात	5632	5322	-310	-20.7	-5.50
25	चण्डीगढ़	11	8	-3	-0.2	-27.27
26	पांडिचेरी	27	11	-16	-1.1	-59.26
27	मेघालय			0	0.0	
28	मिज़ोरम	0	2	2	0.1	
29	सिक्किम			0	0.0	
30	अण्डमान और निकोबार द्वीप			0	0.0	
31	दादर और नागर हवेली			0	0.0	
32	दमन और दीव					
33	लक्षद्वीप					

स्रोत : रेलवे बोर्ड

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत (कि.वा.)

क्र.सं.राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1970-71	1974-75	1980-81	1989-90	1996-97
1999-2000					
1 दमन और दीव	130.8	276.84	440.1	2346.7	3927.4
2 दादर और नागर हवेली 13.5	14.8	56.3	87.8	2298.8	3882.8
3 पांडिचेरी 175.8	214.4	263.7	592.4	1034.5	931.9
4 चण्डीगढ़ 280.2	363.7	309.0	686.2	794.4	823.8
5 पंजाब 156.2	154.2	303.6	620.5	789.9	921.1
6 गोवा 96.9	157.5	250.8	411.2	719.1	712.8
7 गुजरात 124.4	165.0	238.8	436.8	685.7	834.7
8 दिल्ली 250.6	299.2	403.8	673.6	589.7	653.2
9 महाराष्ट्र 151.7	172.6	244.5	393.6	557.0	520.5
10 हरियाणा 88.8	115.1	209.5	367.4	508.3	530.8
11 तमिलनाडु 124.9	126.4	186.0	295.0	469.4	484.1
12 उड़ीसा 72.9	69.2	114.0	249.2	446.7	354.6
13 मध्य प्रदेश 45.2	61.3	100.3	217.4	368.4	351.7
14 कर्नाटक 101.5	119.3	146.0	272.8	338.3	380.1
15 भारत 79.8	174.9	120.5	236.0	334.0	354.75
16 आन्ध्र प्रदेश 50.4	55.4	101.8	233.5	331.7	391.0
17 राजस्थान 36.8	35.9	99.4	191.6	294.4	334.5
18 हिमाचल प्रदेश 34.1	58.1	66.4	191.9	278.5	339.1
19 केरल 71.4	79.4	112.0	171.0	235.8	261.8
20 लक्षद्वीप	11.2	26.8	143.6	234.2	217.9
21 जम्मू व कश्मीर 36.8	52.7	74.8	176.4	223.7	267.9
22 अण्डमान और निकोबार द्वीप 26.1	27.2	42.3	109.7	210.0	222.4
23 पश्चिम बंगाल 107.3	106.1	117.0	136.2	196.6	204.4
24 उत्तर प्रदेश 48.5	50.0	83.1	157.4	194.3	175.8
25 सिक्किम		37.2	103.3	182.4	192.38
26 बिहार 45.9	48.0	74.1	109.9	145.1	140.8
27 मेघालय	31.3	31.0	106.4	134.5	160.3
28 मणिपुर 4.7	7.7	7.9	79.5	127.9	69.5
29 मिज़ोरम	4.3	5.6	65.0	127.8	120.7
30 असम 20.0	24.0	33.5	92.7	107.6	95.5
31 नागालैंड 7.8	27.2	34.2	58.6	88.0	84.7
32 अरुणाचल प्रदेश	3.4	14.6	56.6	80.8	68.6
33 त्रिपुरा 4.5	6.0	14.5	45.0	80.4	95.5

स्रोत : क) सांख्यिकीय सारांश, भारत, सं.स. प्रकाशन, विभिन्न मामलें।

ख) राज्य विद्युत बोर्ड और राजकीय विद्युत विभाग के कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट ;2001.02ख योजना आयोग।

**संचय जमा तथा सकल बैंक उधार का राज्यवार वितरण : सभी अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंक मार्च 2001**

क्षेत्र/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			अर्ध-शहरी			शहरी/महानगर			योग		
	जमा	उधार	स.ज. अनुपात	जमा	उधार	स.ज. अनुपात	जमा	उधार	स.ज. अनुपात	जमा	उधार	स.ज. अनुपात
उत्तरी क्षेत्र	30008	11745	39.1	32841	10139	30.9	158615	117892	74.3	221464	139777	63.1
हरियाणा	3933	1648	41.9	6517	2500	38.4	9354	4101	43.8	19804	8249	41.7
हिमाचल प्रदेश	4664	1110	23.8	2683	549	20.5	-	-	-	7347	1659	22.6
जम्मू व कश्मीर	3942	650	16.5	1130	320	28.3	5034	2905	57.7	10105	3874	38.3
पंजाब	10385	5289	50.9	14203	4202	2.96	19362	8699	44.9	43950	18190	41.4
राजस्थान	5716	2719	47.6	7549	2475	32.8	14090	7985	56.7	27355	13179	48.2
चंडीगढ़	119	39	32.6	310	54	17.5	7092	7184	101.3	7521	7277	96.7
दिल्ली	1249	291	23.3	450	40	8.9	103683	87018	83.9	105382	87349	82.9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	3588	1197	33.4	5258	1102	21.0	6521	2020	31.0	15367	4318	28.1
अरुणाचल प्रदेश	312	59	18.8	299	47	15.6	-	-	-	611	105	17.3
असम	2323	800	34.4	3432	778	22.7	4109	1615	39.3	9864	3193	32.4
मणिपुर	57	46	79.4	69	38	55.8	297	81	27.1	423	165	38.9
मेघालय	356	82	22.9	269	34	12.6	1022	161	15.7	1647	276	16.8
मिज़ोरम	55	34	61.1	48	20	40.7	286	46	16.1	390	100	25.5
नागालैंड	67	22	33.1	823	102	12.4	-	-	-	890	124	13.9
त्रिपुरा	417	155	37.2	319	83	26.1	806	117	14.5	1542	355	23.0
पूर्वी क्षेत्र	29260	7566	25.9	25765	5421	21.0	71181	33547	47.1	126205	46535	36.9
बिहार	8991	2022	22.5	7705	1506	19.5	9810	2123	21.6	26506	5650	21.3
उड़ीसा	5074	2160	42.6	4306	1523	35.4	5731	2581	45.0	15111	6265	41.5
सिक्किम	167	33	19.9	449	63	14.0	-	-	-	616	96	15.6
पश्चिम बंगाल	10330	2415	23.4	8289	1505	18.2	49639	26177	52.7	68257	30097	44.1
अण्डमान और निकोबार द्वीप	92	22	23.5	293	50	17.1	-	-	-	385	72	18.6
मध्य क्षेत्र	33217	9730	29.3	30365	9188	30.3	67481	24828	36.8	131063	43746	33.4
मध्य प्रदेश	5426	2374	43.8	7755	2701	34.8	16053	9053	56.4	29233	14129	48.3
उत्तर प्रदेश	23056	6263	27.2	17537	4891	27.9	44463	13357	30.0	85057	24511	28.8
पश्चिमी क्षेत्र	17658	8545	48.4	27019	9209	34.1	191507	159346	83.2	236184	177100	75.0
गोवा	2185	275	12.6	5104	1389	27.2	-	-	-	7289	1664	22.8
गुजरात	8560	3256	38.0	11414	3506	30.7	34461	20148	58.5	54436	26910	49.4
महाराष्ट्र	6835	4997	73.1	9951	4238	42.6	157046	139197	88.6	173831	148433	85.4
दादरा और नागर हवेली	63	16	25.9	163	21	12.9	-	-	-	226	37	16.5
दमन और दीव	14	1	5.7	387	56	14.4	-	-	-	401	56	14.1
दक्षिणी क्षेत्र	25695	17233	67.1	65486	28798	44.0	129240	98929	76.5	220421	144960	65.8
आन्ध्र प्रदेश	8039	6220	77.4	12392	6341	51.2	33978	21868	64.4	54410	34429	63.3
कर्नाटक	7498	5136	68.5	9480	5088	53.7	38614	22760	58.9	55592	32984	59.3
केरल	2299	1265	55.0	29650	10312	34.8	13289	7900	59.4	45238	19477	43.1
तमिलनाडु	7651	4560	59.6	13620	6962	51.1	42217	45996	109.0	63488	57518	90.6
लक्षद्वीप	54	5	9.7	-	-	-	-	-	-	54	5	9.7
पांडिचेरी	155	46	30.0	343	96	27.9	1142	405	35.5	1640	548	33.4
अखिल भारत	13942756017	40.218673363857	34.2	624545436562	69.9	950705	556436	58.5				

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अनुलग्नक - 3.11 (2)

**संचय जमा तथा सकल बैंक उधार का राज्यवार वितरण : सभी अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंक मार्च 1994**

क्षेत्र/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			अर्ध-शहरी			शहरी/महानगर			योग		
	जमा	उधार अनुपात	स.ज.	जमा	उधार अनुपात	स.ज.	जमा	उधार अनुपात	स.ज.	जमा	उधार अनुपात	स.ज.
उत्तरी क्षेत्र	11613	4578	39.43	10449	3501	33.50	47204	31942	67.67	69265	40022	57.78
हरियाणा	1591	813	51.07	1949	797	40.90	2552	1310	51.33	6092	2920	47.93
हिमाचल प्रदेश	2053	444	21.62	682	169	24.81	-	-	-	2735	613	22.42
जम्मू व कश्मीर	939	181	19.32	334	90	27.01	1494	800	53.57	2767	1072	38.74
पंजाब	4408	1966	44.61	4886	1464	29.96	5857	2572	43.91	15151	6002	39.61
राजस्थान	2032	1098	54.04	2438	965	39.56	4331	2273	52.49	8801	4336	49.26
चंडीगढ़	54	16	28.79	82	9	11.45	2159	1446	66.98	2295	1471	64.10
दिल्ली	535	60	11.28	78	6	8.22	30811	23542	76.41	31424	23608	75.13
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1369	693	50.63	1625	535	32.95	1806	638	35.33	4799	1867	38.89
अरुणाचल प्रदेश	234	33	14.17	3	0	9.39	-	-	-	237	33	14.10
असम	815	460	56.47	1139	364	31.95	1200	478	39.86	3154	1303	41.29
मणिपुर	21	27	126.64	25	21	83.70	90	41	45.54	136	89	65.21
मेघालय	103	34	33.03	94	12	13.20	345	48	13.89	541	94	17.39
मिज़ोरम	29	11	39.26	89	18	19.71	-	-	-	118	29	24.51
नागालैंड	50	26	52.77	193	76	39.30	-	-	-	243	102	42.07
त्रिपुरा	117	101	86.33	81	45	54.93	171	71	41.46	369	216	58.63
पूर्वी क्षेत्र	8690	4220	48.56	8771	2564	29.24	27892	13208	47.35	45353	19992	44.08
बिहार	4121	1893	45.94	3720	1093	29.38	4912	1509	30.71	12754	4495	35.25
उड़ीसा	1280	920	71.91	1096	564	51.43	1768	1006	56.87	4144	2490	60.08
सिक्किम	42	9	22.09	80	19	23.84	-	-	-	122	28	23.24
पश्चिम बंगाल	3223	1392	43.18	3801	875	23.02	21211	10694	50.41	28236	12961	45.90
अण्डमान और निकोबार द्वीप	24	5	22.06	73	13	18.12	-	-	-	97	18	19.10
मध्य क्षेत्र	11541	4806	41.64	10257	4090	39.88	19677	8523	43.31	41475	17419	42.00
मध्य प्रदेश	2535	1426	56.25	3045	1360	44.65	5579	3349	60.03	11159	6134	54.97
उत्तर प्रदेश	9006	3380	37.53	7211	2730	37.86	14099	5174	36.70	30316	11285	37.22
पश्चिमी क्षेत्र	6425	3017	46.95	10087	3652	36.20	76929	43049	55.96	93441	49718	53.21
गोवा	757	85	11.22	1614	344	21.34	-	-	-	2371	429	18.11
गुजरात	3015	1373	45.54	5014	1993	39.76	11136	5453	48.97	19164	8819	46.02
महाराष्ट्र	2613	1551	59.33	3354	1299	38.74	65793	37596	57.14	71761	40446	56.36
दादर और नागर हवेली	37	8	21.30	-	-	-	-	-	-	37	8	1.30
दमन और दीव	4	1	14.17	104	15	14.09	-	-	-	108	15	14.10
दक्षिणी क्षेत्र	9693	7356	75.89	21848	10211	46.74	38103	26306	69.04	69643	46874	67.31
आन्ध्र प्रदेश	2999	2478	82.61	4619	2613	56.58	9327	6895	73.92	16945	11986	70.73
कर्नाटक	2750	2005	72.90	3188	1652	51.82	9888	6731	68.07	15827	10388	65.64
केरल	188	644	54.24	9448	3178	33.63	4135	2674	64.68	14770	6496	43.98
तमिलनाडु	2652	2194	82.71	4509	2745	60.87	14389	12830	89.17	21550	17768	82.45
लक्षद्वीप	17	2	9.06	-	-	-	-	-	-	17	2	9.06
पांडिचेरी	86	34	39.21	83	24	28.47	365	176	48.30	534	234	43.75
अखिल भारत	49331	24670	50.01	63035	24554	38.95	211610	126667	59.86	323977	175891	54.29

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

**नौवीं योजना के दौरान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत
जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)**

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	नौवीं		औसत
							योजना	बा.स.प्रा.	
							में	वृत्त	प्रति
							बा.स.प.	प्रतिवर्ष	वर्ष
							में रुपये		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	1117.94	624.72	1440.51	1442.34	3755.84	8381.36	1676.27	221.36
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.06	0.59
3	असम	0.22	33.16	41.19	78.26	93.25	246.08	49.22	18.48
4	बिहार	132.26	112.78	130.41	63.67	16.83	455.96	91.19	11.00
5	गोवा	10.82	5.73	0.45	0.00	0.00	16.99	3.40	25.29
6	गुजरात	219.27	267.65	512.33	891.24	1604.96	3495.45	699.09	138.17
7	हरियाणा	221.25	165.01	280.85	296.66	151.93	1115.70	223.14	105.84
8	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	15.56	56.40	38.16	110.12	22.02	36.24
9	जम्मू व कश्मीर	10.51	8.42	24.84	15.71	38.05	97.53	19.51	19.37
10	कर्नाटक	264.48	316.49	456.70	579.50	1691.74	3308.91	661.78	125.49
11	केरल	38.73	40.85	41.55	77.16	96.99	295.28	59.06	18.55
12	मध्य प्रदेश	117.32	163.26	598.67	172.68	819.60	1871.53	374.31	61.99
13	महाराष्ट्र	1073.68	597.13	245.36	318.70	289.23	2524.11	504.82	52.18
14	मणिपुर	0.00	8.96	18.43	19.57	16.27	63.23	12.65	52.94
15	मेघालय	0.00	0.00	0.62	8.15	43.12	51.89	10.38	45.00
16	मिज़ोरम	0.00	0.49	3.19	1.89	3.49	9.06	1.81	20.34
17	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.21	1.07
18	उड़ीसा	535.54	415.83	391.56	516.34	310.50	2169.76	433.95	118.22
19	पंजाब	149.91	171.11	106.35	187.15	209.58	824.11	164.82	67.86
20	राजस्थान	230.11	225.17	188.09	248.42	99.12	990.91	198.18	35.09
21	सिक्किम	0.00	11.69	2.09	0.50	1.92	16.20	3.24	59.94
22	तमिलनाडु	568.52	305.16	591.41	775.14	340.19	2580.42	516.08	83.09
23	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.03	3.67	3.69	0.74	2.31
24	उत्तर प्रदेश	721.39	465.05	431.22	1697.90	606.37	3921.92	784.38	47.24
25	पश्चिम बंगाल	542.31	886.21	819.67	636.09	688.45	3572.74	714.55	89.07
26	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	7.17	1.43	0.69
27	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	9.73	17.41	27.14	5.43	6.40
29	कुल	5954.25	4824.89	6341.06	8093.24	10945.23	36158.66	7231.73	70.42